R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 20 । अंक : 17

01 से 15 जून 2022

पृष्ठ : 48

मूल्य : 25 रु.

2022
नगरीय निकाय
और पंचायत चुनाव

लड़ाई निकाय और पंचायत की...

लक्ष्य मिशन-2023 पर

ओबीसी आरक्षण के पेंच में
गड़बड़ाया मप्र का चुनावी गणित

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद
अब बिना आरक्षण होंगे चुनाव

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

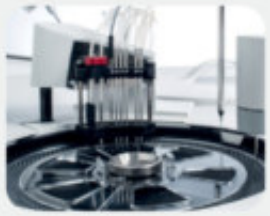

Add : Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

योजना

8 | ई-आबकारी पोर्टल पर...

मप्र कुछ साल पहले तक अवैध और जहरीली शराब के कारण बदनाम था। लेकिन जबसे प्रदेश के आबकारी विभाग की कमान 2002 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव चंद्र दुबे के हाथ में आई है, उन्होंने नए-नए नवाचारों...

राजपथ

10-11 | 200 पार के लक्ष्य पर...

मप्र में मिशन 2023 का घमासान दिन पर दिन तेज होता जा रहा है। भाजपा का पूरा फोकस 200 पार के लक्ष्य पर है। इसके लिए हर स्तर पर तैयारी चल रही है। वहीं निकाय और पंचायत चुनाव की गतिविधियां तेज हो चली हैं।

मप्र कांग्रेस

13 | चौतरफा घेराबंदी करेगी कांग्रेस

मप्र की 230 विधानसभा सीटों के चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति को धार देना तेज कर दिया है। विधानसभा वार पार्टी सोशल मैपिंग की तैयारी में है। पार्टी सभी 230 सीटों के सामाजिक और जातिगत समीकरणों की मैपिंग...

लालफीताशाही

18 | मप्र में 4076 सिपाही कर...

मप्र में आईपीएस अफसरों की लंबी फौज सिपाहियों के हक पर डाका डाले बैठी है। वो ट्रेंड आरक्षकों को मैदानी ड्यूटी पर न भेजकर अपने सरकारी बंगले पर चाकरी करवा रही है। आरक्षकों से झाड़ू पोंछा और घर के लिए सब्जी-भाजी तक खरिदवायी जा रही है। ऐसे एक या दो नहीं...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

मप्र में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और नगरीय निकाय चुनाव की चौसर सजने लगी है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां निकाय और पंचायत चुनाव में अपनों को जिताकर मिशन-2023 की राह आसान करना चाहती है। इसके लिए भाजपा और कांग्रेस ने पूरी तरह कमर कस ली है। भाजपा अपने 17 साल के विकास, तो कांग्रेस 15 माह के शासन के आधार पर मिशन-2023 की तैयारी कर रहीं हैं। लेकिन दोनों की अग्निपरीक्षा पंचायत और निकाय चुनाव में होनी है।

राजनीति

30-31 | वंशवाद में बंधी कांग्रेस

कांग्रेस के चिंतन शिविर में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक मीटिंग में प्रस्ताव रखा कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं हैं, तो प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। हालांकि, बाकी मौकों पर और कार्यकारिणी की बैठक में भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी...

महाराष्ट्र

35 | राज ठाकरे मोहरा भर ही हैं

राज ठाकरे अब भी एक करिश्माई नेता की तरह ही परफॉर्म कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे भले ही उनको नकली-ठाकरे साबित करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन अकेले में वो भी मानते होंगे कि राज ठाकरे के लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा मुहिम का कितना ज्यादा असर हुआ है।

बिहार

38 | बिहार की राजनीति में तूफान

मौसम भले सूखे का हो, मगर बिहार की राजनीति में चर्चाओं की नदी हमेशा उफान मारती रहती है। करीब एक महीना पूरा होने जा रहा है। पटना में राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर 28 अप्रैल को इफ्तार पार्टी हुई थी। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव...

6 -7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

वीआईपी की सुरक्षा में खानापूर्ति चिंताजनक...

किसी कवि ने लिखा है...

अपनों के लिए हर वादे तोड़ के आया हूं, मैं खाकी हूं
आपके लिए अपनों को रोता छोड़ आया हूं....

वाकई हमारी पुलिस पर जिम्मेदारियों का पहाड़ है। लेकिन इन जिम्मेदारियों का आधार इतना खोखला है कि पुलिस वाले अपना कर्त्तव्य ठीक से नहीं निभा पाते। यानी कर्त्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मियों के सामने सुविधाओं और संसाधनों का अभाव है। इस कारण उनके कर्त्तव्य परायणता पर सवाल उठते रहते हैं। आज देश में जितनी जिम्मेदारी पुलिस पर है, उसके एवज में उनके पास संसाधनों का अभाव है। इस कारण वीआईपी की सुरक्षा में भी कई बार खाकी फेल हो जाती है। प्रोटोकॉल के तहत प्रदेश में मंत्रियों, नेताओं के लिए पुलिस की सुरक्षा जरूरी है। इस कारण जब भी कोई मंत्री या बड़ा नेता दौरे पर जाता है तो उसकी सुरक्षा में संबंधित जिले के थाने की पुलिस तैनात की जाती है। लेकिन विडंबना यह है कि माननीय के लिए जो फॉलो वाहन तैनात किया जाता है, वह इतना खटारा रहता है कि माननीय के काफिले की गति की वह बराबरी नहीं कर पाता है। ऐसे में माननीय की सुरक्षा में कई बार बड़ी चूक हो जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि वीआईपी की सुरक्षा में दिखावे की खानापूर्ति क्यों की जाती है। देश में वीआईपी लोगों को महफूज रखना सरकार का कर्त्तव्य होता है। बीस हजार से अधिक विशिष्ट एवं अति विशिष्ट लोगों को एक तय संख्या में सुरक्षाकर्मी मिले हुए हैं। प्रधानमंत्री के एसपीजी सुरक्षा कवर से लेकर जेड प्लस, जेड, वाई प्लस, वाई और एक्स श्रेणी की सुरक्षा के अलावा केंद्र व राज्य में एक या दो सुरक्षाकर्मी साथ लेकर चलने वाले वीआईपी लोगों का आंकड़ा काफी बड़ा है। वीआईपी सुरक्षा में लगे अधिकारियों के मुताबिक, 12000 करोड़ रुपए के सालाना खर्च पर लगभग 20 हजार वीआईपी महफूज रहते हैं। इनकी सुरक्षा में 60,000 से अधिक जवान तैनात हैं। 30,000 से ज्यादा गाड़ियां, वीआईपी सिक्योरिटी में इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन जब ये वीआईपी दौरों पर होते हैं तो संबंधित जिले के थानों से तैनात होने वाले फॉलो वाहन इतने जर्जर होते हैं कि वे कई बार वीआईपी के काफिले से काफी पीछे रह जाते हैं। अगर संसाधनों की कमी है तो सरकार या तो उनके प्रोटोकॉल में कटौती करे या फिर पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए। इसी मुद्दे को लेकर मप्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह को अब अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। डॉ. गोविंद सिंह ने अपनी सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र भी लिखा है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह का आरोप है कि वे जब भिंड जिले के दौरे पर थे तो उन्हें जो वाहन दिया गया था वह बहुत खटारा वाहन था और उन्हें जो सुरक्षाकर्मी दिया गया था उसके पास हथियार तक नहीं था, बिना हथियार के आखिर सुरक्षाकर्मी उनकी सुरक्षा कैसे कर सकता था। यह आवाज भले ही नेता प्रतिपक्ष ने उठाई है, लेकिन प्रदेश के मंत्रियों और अन्य नेताओं के साथ कई बार ऐसी घटना घटित हो चुकी है। गत वर्ष ग्वालियर-चंबल अंचल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का फॉलो वाहन अपनी धीमी रफ्तार के कारण उनके काफिले से दूर हो गया। जिसके कारण केंद्रीय मंत्री बिना सुरक्षा के ग्वालियर पहुंचे। इस संदर्भ में शासन और प्रशासन को गंभीरता से सोचने की जरूरत है और वीआईपी सुरक्षा में होने वाली चूक का समाधान करने की जरूरत है। वरना माननीयों की सुरक्षा में की जाने वाली खानापूर्ति बड़ी घटना को दावत दे सकती है।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 20, अंक 17, पृष्ठ-48, 1 से 15 जून, 2022

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, **जयपुर:**- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (गंजबासौदा) ज्योत्सना अनूप यादव
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर, मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

बिहार में मप्र मॉडल

देश में खेती की लागत को कम करने एवं रासायनिक खेती से हो रहे नुकसान को कम करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वहीं अब मप्र की तर्ज पर बिहार में भी देसी गायों को संरक्षण दिया जाएगा। अभी बिहार सरकार मप्र मॉडल का अध्ययन करा रही है।

● **प्रमोद शर्मा,** भोपाल (म.प्र.)

मिशन 2023 में जुटी पार्टियां

मप्र में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बार चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। भाजपा जहां बूथ विस्तार अभियान और समर्पण निधि जैसे अभियानों के जरिए पार्टी को मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस भी घर चलो घर-घर चलो अभियान के जरिए पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में है।

● **मंजू सिंह,** इंदौर (म.प्र.)

सुधर रही गांवों की स्थिति

प्रदेश में गांवों की स्थिति अब तेजी से सुधर रही है। ग्रामीण इलाकों में विकास के नए सोपान गढ़े जा रहे हैं। प्रदेश को कई योजनाओं में देश में प्रथम स्थान मिलने से इसकी पुष्टि होती है। परंपरागत आय के संसाधनों पर निर्भरता कम होने के फलस्वरूप सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हुए हैं।

● **महेश नागर,** राजगढ़ (म.प्र.)

सड़कों का खाका तैयार

सरकार के दिशा-निर्देश पर योजनाबद्ध तरीके से सड़कों का खाका तैयार किया गया है। जिसके तहत 10 किलोमीटर से कम लंबाई की सड़कों के निर्माण के लिए नई योजना भी तैयार की जा रही हैं। इन्हें भी लोक निर्माण विभाग ही बनाएगा। ज्ञातव्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए 2018 तक मंडी बोर्ड लगभग 400 करोड़ रुपए सालाना देता था। मुख्यमंत्री कार्यालय ने विधानसभा के बजट सत्र के पहले विधायकों से 15-15 करोड़ रुपए तक के कामों के जो प्रस्ताव मांगे थे, उसमें भी अधिकांश ने सड़क निर्माण के कार्य को ही प्राथमिकता दी थी। इसके आधार पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जगह सरकार ने लोक निर्माण विभाग के बजट में 1 हजार 985 करोड़ रुपए का प्रविधान कर दिया है।

● **प्रियांशी मोदी,** ग्वालियर (म.प्र.)

किसानों को मिलेगी राहत

किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने मप्र को पिछले तीन साल में 3 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि दी है। इसके बाद भी अन्नदाता की माली हालत में सुधार नहीं आया। जिन 4 राज्यों में किसान की मासिक आय कम हुई है उसे लेकर संसद की स्थायी समिति ने रिपोर्ट में लिखा है कि इन राज्यों में राज्य का कृषि विभाग केवल मूक दर्शक बना रहा। यानी जो योजनाएं चल रही हैं, उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए प्रयास या मेहनत नहीं की गई।

● **नीलेश रावत,** सीहोर (म.प्र.)

नदियां होंगी प्रदूषण मुक्त

मप्र में नदियों को प्रदूषण होने से बचाने के लिए स्थानीय स्तर पर तैयार किया गया एक्शन प्लान सरकार को भेज दिया गया है। इस मामले में बीते कई महीने से एक्शन प्लान बनाकर सरकार को दिया गया है। जिसमें लंबे समय से सरकार ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया है। पूर्व से चल रहे कार्य तो किए जा रहे हैं लेकिन नए प्लान का असर अब तक नहीं देखा जा रहा है। रीवा में बिछिया और चाकघाट में टमस नदी का प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है।

● **ऋचा बानकानी,** जबलपुर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

खतरे में जादूगर की कुर्सी

राजस्थान के उदयपुर में आयोजित कांग्रेस के तीन दिवसीय चिंतन शिविर में चर्चाओं और कानाफूसियों का केंद्र राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे। खबर गर्म है कि जल्द ही राज्य सरकार की कमान युवा नेता सचिन पायलट को देने का मन कांग्रेस आलाकमान बना चुका है। 71 वर्षीय गहलोत की सरकार पर लग रहे नित नए आरोपों के चलते कांग्रेस आलाकमान खासा चिंतित बताया जा रहा है। दिसंबर, 2023 में राज्य विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल भाजपा बेहद आक्रामक हो गहलोत सरकार को घेरने में जुट चुकी है। सरकार में मंत्री महेश जोशी के पुत्र रोहित जोशी का नाम एक बलात्कार के मामले से जुड़ गया है। दिल्ली पुलिस ने एक 23 वर्षीय युवती की शिकायत पर रोहित जोशी पर बलात्कार की जीरो एफआईआर दर्ज कर ली है। युवती किसी न्यूज चैनल की एंकर बताई जा रही है। स्वयं मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में दंगों का होना भी गहलोत सरकार की किरकिरी का बड़ा कारण बन चुका है। गत 9 मई के दिन भरतपुर में सिखों और मुसलमानों के मध्य हुए इन दंगों को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार कर रही है। अप्रैल माह में अलवर जिले के राजगढ़ में 300 बरस पुराने मंदिर को प्रशासन द्वारा गिराए जाने का मुद्दा भी भाजपा जमकर भुना रही है।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर सस्पेंस बरकरार

दिल्ली के सत्ता गलियारों में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा देश के नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को लेकर हो रही है। नित नए नाम सामने आने से सस्पेंस गहराता जा रहा है कि भाजपा आलाकमान किन दो चेहरों को इन महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों के लिए अपना उम्मीदवार बनाएगा। हालांकि तमाम नामों के बीच यह भी कहा-सुना जा रहा है कि पूर्व की भांति इस बार भी नाम अंतिम समय में ही सार्वजनिक किए जाएंगे और दोनों ही नाम चौंकाने वाले होंगे। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नाम भी अंतिम समय में ही भाजपा ने घोषित कर सबको चौंका दिया था। तब जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी उनमें कोविंद का नाम शामिल ही नहीं था। इस बार भी चर्चा के केंद्र में उप्र की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, झारखंड की राज्यपाल द्रोपदी मुर्मू और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसूइया उइके का नाम सबसे आगे है। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की बाबत भी कयास लगाए जा रहे हैं। दो पूर्व केंद्रीय मंत्रियों थावरचंद गहलोत और बंडारु दत्तात्रेय के नामों पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। भाजपा के एक विश्वसनीय सूत्र की मानें तो इन नामों पर चर्चा भले ही हो रही हो, असल में नाम इनमें से किसी का नहीं है। इस सूत्र का दावा है कि इस बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में से एक पद ऐसे वरिष्ठ भाजपा नेता को दिया जाना तय हो चुका है जो उत्तर भारत से हैं और वर्तमान में एक महत्वपूर्ण राज्य के राज्यपाल भी हैं।

सियासी सूरमा

अखिलेश यादव सियासी तौर पर मंज चुके हैं। राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन में उन्होंने साबित कर दिया कि वोट बैंक पुख्ता रखने का हुनर उनके पास है। आजम खान से उनके मतभेद तो जरूर हैं पर ऐसा दावा कोई नहीं कर सकता कि आजम समाजवादी पार्टी छोड़ेंगे। आजम खान की जेल से रिहाई के वक्त अखिलेश यादव के नहीं पहुंचने को लेकर तमाम कयास लगाए गए। मीडिया में अटकलें भी शुरू हो गई कि शिवपाल, ओमप्रकाश राजभर और आजम खान मिलकर अलग पार्टी बनाएंगे। लेकिन हकीकत कुछ और है। अखिलेश यादव खुलकर मुसलमानों के मुद्दों पर बेशक आक्रामक नहीं दिखते हों पर मुसलमान उनके एजंडे में अभी भी सबसे ऊपर है। तभी तो संभल के जावेद अली को दूसरी बार राज्यसभा भेजने का फैसला किया। आजम खान की इच्छा का आदर करते हुए कांग्रेस छोड़कर आए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की उम्मीदवारी को निर्दलीय की हैसियत से भी सिर माथे लगाया। कपिल सिब्बल की कोशिशों से ही तो आजम खान जेल से बाहर आ पाए हैं। भाई लोग भूल रहे हैं कि सीतापुर जेल पर आजम खान की अगवानी के लिए अखिलेश ने अपने चहेते सहारनपुर के मुस्लिम विधायक आशू मलिक को भेजा था।

नीतीश-नीति

लालू यादव ने एक बार मजाक में कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दाढ़ी है। इस मुहावरे का मतलब होता है अति चतुर होना। कम बोलने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सियासी पैंतरेबाजी में माहिर माने जाते हैं। जातीय जनगणना के मुद्दे पर उन्होंने इसे फिर साबित कर दिखाया है। भाजपा इस मांग से बचने की कोशिश करती रही है। बिहार के तमाम पिछड़े तबके के नेता इसे अरसे से मुद्दा बनाए हैं। नीतीश ने इस मुद्दे पर 1 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। भाजपा साझा सरकार का हिस्सा होने के बावजूद इस बैठक से किनारा करती दिख रही थी। अंत में पार्टी के सूबेदार ने ट्वीट किया कि वे मुख्यमंत्री की बुलाई बैठक में जाएंगे। हां, यह तथ्य छिपा लिया कि बैठक जातीय जनगणना के सवाल पर हो रही है। बहरहाल भाजपा को झुकना पड़ा है। अब तो नवीन पटनायक ने भी समर्थन कर दिया है इस मांग का। नीतीश कुमार ने अभी तक राज्यसभा के अपने उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है। वहीं जद(एकी) के मोदी सरकार में इकलौते मंत्री आरसीपी सिंह की धड़कनें तेज हैं।

भाजपा के चार 'आर'

शिवसेना संग जारी अपने अनवरत 'युद्ध' में भाजपा ने चार ऐसे योद्धाओं की टीम तैयार की है जिन्हें इन दिनों भाजपा के चार 'आर' कह पुकारा जाने लगा है। ये चार हैं राणे (नारायण), राणा (नवनीत), रणौत (कंगना) और राज (ठाकरे)। पिछले कुछ समय से ये चारों 'आर' शिवसेना और उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। जानकारों का दावा है कि भाजपा इस समय महाराष्ट्र राजनीति में फ्रंट फुट पर रह अपनी रणनीति परवान चढ़ा रही है क्योंकि उसका लक्ष्य इस वर्ष होने जा रहे वृहत मुंबई नगर पालिका चुनावों में जीत हासिल करना है। मुंबई नगर पालिका में लंबे समय से शिवसेना का कब्जा है। यदि भाजपा ऐसा कर पाई तो महाविकास अघाड़ी सरकार के साथ-साथ शिवसेना के लिए यह भारी आघात होगा। भाजपा का महाराष्ट्र में कोर वोट बैंक उत्तर भारतीय और गुजराती वोटर हैं। वहीं शिवसेना की मराठी वोटर्स में मजबूत पकड़ है। भाजपा अब इस वोट बैंक पर अपनी पकड़ राज ठाकरे के जरिए बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

गले की फांस बन गईं मैडम

अपनी नर्म तासीर के लिए ख्यात विंध्य क्षेत्र के एक जिले में इन दिनों पुलिस विभाग की एक महिला इंस्पेक्टर की गर्मी अच्छे-अच्छों पर भारी पड़ रही है। आलम यह है कि उक्त महिला अधिकारी को जिस बड़े साहब ने आगे बढ़ाया आज वह उन्हीं के गले की फांस बन गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विंध्य क्षेत्र के जिले में पदस्थ उक्त मैडम की करतूतें इस कदर बढ़ गई हैं कि उक्त जिले के अधिकारी भी उनसे खार खाने लगे हैं। बताया जाता है कि अपनी कद-काठी और सौंदर्य के बल पर मैडम पत्थर को भी पिघला देती हैं। अपनी इसी अदा से वे जिले में पदस्थ होने वाले अफसरों को अपनी फांस में बांध लेती हैं। इसी फांस में उन्होंने जिले के एक एडिशनल एसपी को बांध लिया है। बताया जाता है कि साहब भी मैडम की अदाओं पर इस कदर फिदा हो गए थे कि वे जो चाहती थीं, वे करते थे। अपनी इन्हीं अदाओं से उन्होंने साहब की कृपा पाई और साहब ने ईनाम के रूप में उन्हें महिला थाने से निकालकर एक कमाऊ थाने में पदस्थ करवा दिया। बताया जाता है कि जबसे मैडम नए थाने में पदस्थ हुई हैं, वे साहब के माध्यम से एसपी साहब को साधने में लग गई हैं। वे साहब पर लगातार दबाव बना रही हैं कि वे एसपी साहब से उनकी दोस्ती करा दें। साहब असमंजस में पड़ गए हैं। साहब को यह डर सता रहा है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये इंस्पेक्टर उनकी पोल-पट्टी खोल सकती हैं।

सबको दिखा दिया ठेंगा

प्रदेश में महिला सम्मान और ओबीसी आरक्षण पर हाय-तौबा मचाने वाली पार्टी के कर्ताधर्ता ने राज्यसभा जाने का सपना देख रहे लोगों को ठेंगा दिखा दिया है। दरअसल, प्रदेश में सत्ता छिन जाने के बाद माननीय लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि उन्हें कोई ऐसा मुद्दा मिल जाए, जिस पर सवार होकर उनकी पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में सत्ता में आ जाए। इसके लिए पिछले कई महीनों से उन्होंने महिला सम्मान और ओबीसी आरक्षण को मुद्दा बना रखा है। बात-बात में सत्तारूढ़ पार्टी को घेरने के लिए वे इन दोनों मुद्दों में नमक-मिर्च मिलाकर आरोप लगाते रहते हैं। यानी वे प्रदेशवासियों को यह दिखाना चाहते हैं कि वे और उनकी पार्टी महिला और प्रदेश के सबसे बड़े वोटबैंक ओबीसी के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। माननीय की गतिविधियों को देखते हुए उनकी पार्टी की कुछ महिला नेत्रियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के नेताओं ने राज्यसभा जाने का सपना बुनना शुरू कर दिया था। लेकिन माननीय ने वही किया जो करना चाहते थे। यानी अपनी पसंद के पूर्व सांसद को दोबारा राज्यसभा भेज दिया। उन्होंने यह भी संदेश दे दिया कि जो काम आएगा वह ही ईनाम पाएगा।

बुढ़ापे का मिल गया सहारा

समय के साथ-साथ राजनीति का तरीका भी बदलता जा रहा है। इस समय राजनीति का सबसे बड़ा प्लेटफार्म सोशल मीडिया बना हुआ है। इसलिए भाजपा ने अपने सभी नेताओं को सोशल मीडिया पर सक्रिय होने का निर्देश दिया है। मप्र में भी इस पर अमल किया जा रहा है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि प्रदेश के कई मंत्री सोशल मीडिया पर पूरी तरह सक्रिय नहीं हैं। ऐसे में पार्टी ने मंत्रियों के यहां युवक-युवतियों को पदस्थ किया है, ताकि वे उनके सोशल मीडिया प्लेटफार्म को संभाल सकें। किसी मंत्री के यहां युवक तो किसी के यहां युवती पदस्थ हुई है। इस पदस्थापना से प्रदेश के एक उम्रदराज मंत्री की जैसे लॉटरी लग गई। दरअसल, खाने वाले विभाग के मंत्रीजी के यहां एक युवती पदस्थ हुई है। सूत्रों का कहना है कि जबसे वह युवती मंत्रीजी के यहां पदस्थ हुई है, मंत्रीजी के हाव-भाव ही बदल गए हैं। पहले रफ एंड टफ अंदाज में रहने वाले मंत्रीजी इस दिनों टिप-टॉप नजर आने लगे हैं। बताया जाता है कि सोशल मीडिया की एबीसीडी सीखने के लिए माननीय उक्त युवती के साथ घंटों समय गुजारते हैं। हालांकि मंत्रीजी को जानने वाले ये भी कहने से नहीं कतराते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ हो या न हो लेकिन एक बात तो तय है कि मंत्रीजी को बुढ़ापे का सहारा मिल गया है। अब देखना यह है कि यह सहारा मंत्रीजी को कहीं बेसहारा न कर जाए।

यह कैसी बंदिश ?

प्रदेश के सबसे बड़े विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले बड़े साहब यानी प्रमुख सचिव अपने मंत्रीजी से इस कदर आहत हैं कि उन्होंने विभाग में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं, जो प्रशासनिक वीथिका में चर्चा का विषय बने हुए हैं। बताया जाता है कि मंत्रीजी की आकांक्षाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वे निरंतर फाइल-फाइल खेल रहे हैं। ऐसे में कई बार मंत्रीजी की फाइलों में ऐसा कुछ होता है जिसे करना अपने ऊपर आफत मोल लेना है। हालांकि मंत्रीजी को कायदे-कानून में रहकर काम करने की सलाह कई बार दी जा चुकी है, लेकिन मंत्रीजी हैं कि मानते नहीं हैं। ऐसे में 1996 बैच के उक्त अफसर ने मंत्रीजी की फाइलों से बचने के लिए निर्देश निकाला है कि वहां से जो भी फाइलें आएंगी, उसके लिए सचिव जिम्मेदार होंगे। यानी मंत्रीजी के यहां से आने वाली फाइलों में क्या करना है और क्या नहीं, यह सचिव तय करेंगे। जबकि नियम कहता है कि प्रमुख सचिव ही फाइलों का निराकरण करेंगे। लेकिन मंत्रीजी से निजात पाने के लिए बड़े साहब को यह रास्ता चुनना पड़ा।

तमंचे की राजनीति

प्रदेश में हथियार रखने का शौक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि हर ऐरा-गैरा, नत्थू खैरा हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन लगा देता है। उधर, उच्च पदों पर पदस्थ या पदस्थ रहे लोग भी रसूख के लिए तमंचे का लाइसेंस चाह रहे हैं। इसके लिए वे भी आवेदन कर रहे हैं। लेकिन विडंबना यह देखने को मिल रही है कि आम लोगों को हथियार के लाइसेंस थोड़ी मेहनत-मशक्कत के बाद मिल जा रहे हैं, जबकि रसूखदार लोगों को परिक्रमा करने के बाद भी खाली हाथ रहना पड़ रहा है। ऐसे ही लोगों में एक ब्रिगेडियर और एक हाईकोर्ट के अधिकारी भी शामिल हैं। बताया जाता है कि इन दोनों ने पिछले कई महीनों से पिस्टल के लाइसेंस के लिए आवेदन कर रखा है। इनसे पीछे आवेदन करने वालों को लाइसेंस मिल चुके हैं, लेकिन इन्हें चक्कर कटवाया जा रहा है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमें लाइसेंस देने में गृह विभाग को कहां दिक्कत आ रही है। अब उन्हें कौन बताए कि हथियार के लाइसेंस के लिए भी राजनीतिक पौवा होना जरूरी है। है तो ये भी उसका उपयोग करें।

ई-आबकारी पोर्टल पर चलेगा शराब कारोबार

मप्र कुछ साल पहले तक अवैध और जहरीली शराब के कारण बदनाम था। लेकिन जबसे प्रदेश के आबकारी विभाग की कमान 2002 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव चंद्र दुबे के हाथ में आई है, उन्होंने नए-नए नवाचारों से ऐसी प्रणाली शुरू कर दी है, जिससे अवैध और जहरीली शराब पर अंकुश तो लगा ही है, साथ ही व्यवसायियों की समस्याएं भी दूर हो गई हैं। साथ ही शराब निर्माताओं और व्यापारियों की मोनोपॉली भी खत्म हो गई है।

प्रदेश में शराब के व्यवसाय को पारदर्शी बनाने के लिए आबकारी विभाग ने ई-आबकारी पोर्टल शुरू किया है। अब इसी पोर्टल के माध्यम से सारा काम होगा। आबकारी आयुक्त राजीव चंद्र दुबे ने राष्ट्रीय पाक्षिक अक्स से चर्चा में बताया कि पहले शराब का लाइसेंस लेने के लिए शराब व्यवसायियों को आवेदन लेकर घूमना पड़ता था, अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब उन्हें ई-आबकारी पोर्टल पर आवेदन करना पड़ता है। इस प्रक्रिया से भले ही आबकारी विभाग के अफसरों पर बोझ बढ़ा है, लेकिन व्यवसायी खुश हैं। अब उन्हें लाइसेंस के लिए चक्कर लगाने से मुक्ति मिल गई है। यही नहीं विभाग अब शराब कारोबारियों को और सहूलियत देते हुए 1 जून से विदेशी शराब की ऑनलाइन डिमांड की शुरुआत करने जा रहा है। यानी व्यवसायी अपने संस्थान में बैठे-बैठे ही शराब की मांग और आपूर्ति की व्यवस्था कर सकता है। गौरतलब है कि अभी तक देशी शराब के लिए यह व्यवस्था थी।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश मे अवैध, जहरीली या किसी अन्य प्रदेश से चोरी-छुपे आई शराब की बिक्री पर नकेल कसने के लिए आबकारी विभाग ने शराब की हर बोतल पर बार कोड लागू कर दिया है। इससे कोड स्कैन करते ही पता चल जाएगा कि यह शराब कहां से आई है और कहां के लिए, किस कंपनी से बनी है। अभी बोतल पर सिर्फ होलोग्राम होता है। विभाग का दावा है कि इससे पता चल जाएगा कि शराब असली है या नकली। गौरतलब है कि कई बार ऐसी जानकारी भी मिलती है कि कंपनियां ड्यूटी फ्री शराब बेच रही हैं। कुछ लोग भी इस तरह का धंधा करते हैं। अब यदि कोई ठेकेदार ऐसा करेगा तो चेकिंग में उसकी पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। एक अहम बदलाव यह भी हो रहा है कि अब तक ठेकेदारों को माल मंगवाने के लिए पहले बैंक से चालान भरना पड़ता था। अब आबकारी पोर्टल के माध्यम से इन्हें ई-वॉलेट की सुविधा मिलेगी, जिससे ऑनलाइन पेमेंट हो सके।

गौरतलब है कि आबकारी विभाग के अधिकारियों पर ठेकेदारों से साठ-गांठ के आरोप लगते रहे हैं। यह भी आरोप हैं कि वे अवैध शराब की बिक्री को अनदेखा करते हैं। व्यवस्था में सुधार के लिए ई-आबकारी पोर्टल कुछ दिनों में लांच होने वाला है। इस पोर्टल में जिलेवार हर ठेकेदार का अकाउंट व ई-वॉलेट रहेगा। ई-वॉलेट से सारे शुल्क ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। स्थानीय अफसरों के साथ भोपाल व ग्वालियर मुख्यालय के अफसर भी सीधे जानकारी लेते रहेंगे। आबकारी विभाग के अनुसार ई-आबकारी पोर्टल लांच होने वाला है। इससे विभाग की सारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी।

सरकार की नई व्यवस्था से अधिकारियों और वेयरहाउस में बैठने वाले लोगों की दादागिरी खत्म हो जाएगी। गौरतलब है कि अभी तक महंगी-महंगी दुकानों का ठेका लेकर शराब कारोबारी खुद को ठगा सा महसूस करते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह दुकानों पर शराब की कमी होना है। डिमांड अनुसार वेयरहाउस और डिस्टलरीज से माल सप्लाय नहीं होता था, इस कारण वे परेशान थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ई-आबकारी पोर्टल पर यह साफ-साफ दिख जाएगा कि वेयरहाउस में शराब है या नहीं।

गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 में अपनी शराब नीति बदल दी, जिसका कई पैमानों पर सीधा असर कारोबार पर पड़ रहा है। सरकार ने सिंडिकेट के एकाधिकार को तोड़कर आमजन को राहत दे दी और ठेकेदारों को भी काम पर लगा दिया। देशी-विदेशी शराब दुकान कम्पोजिट होने का असर खासा नजर आ रहा है। बिक्री में तेजी से बढ़ोत्तरी हो गई है लेकिन ठेकेदार अभी भी परेशान हैं। जबसे ठेके हुए हैं, उनकी जमकर फजीहत हो रही है। माल सप्लाय में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई दुकानों पर 8 दिन से माल नहीं पहुंच रहा है जिसकी वजह से दुकानें खाली पड़ी रहती हैं। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए अब ई-आबकारी पोर्टल पर विदेशी शराब की ऑनलाइन डिमांड की व्यवस्था 1 जून से शुरू हो जाएगी। इससे शराब व्यवसायियों की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी।

● **लोकेंद्र शर्मा**

पोर्टल पर दिखेंगे सभी ब्रांड और क्वांटिटी

प्रदेश में शराब के कारोबार को पारदर्शी बनाने के लिए आबकारी विभाग ने ई-आबकारी पोर्टल शुरू किया है, वह शराब कारोबारियों के लिए फायदेमंद होगा। अभी तक शराब कारोबारियों को शराब के लिए वेयरहाउस पर डिपेंड रहना पड़ता था। चौंकाने वाली बात ये है कि सरकारी वेयरहाउस पर ठेकेदारों के कर्मचारियों की लंबी-लंबी लाइन लगी रहती है। माल ट्रक में लोड होता है और सेटिंग से बड़े ठेकेदार लेकर उड़ जाते हैं। छोटे ठेकेदार परेशान होते हैं। डिस्टलरी कंपनी ऑर्डर के बावजूद सप्लाय नहीं कर पा रही है। इसको देखते हुए आबकारी विभाग ने नई व्यवस्था की है। जिसके तहत अब 1 जून से विदेशी शराब ई-आबकारी पोर्टल के माध्यम से कारोबारी ऑर्डर कर सकेंगे। पोर्टल पर अब सभी ब्रांड और उनका स्टॉक नजर आएगा। इससे व्यवसायियों को अपनी मनचाही ब्रांड मिल सकेगी। अभी तक होता यह था कि जब भी शराब कारोबारी वेयरहाउस पहुंचकर अपनी डिमांड रखता था, तो वहां तैनात अधिकारी उसे अपनी पसंद का ब्रांड थमा देते थे। मरता क्या न करता की तर्ज पर कारोबारी को माल लेकर आना पड़ता था।

...खाली हो जाएंगे सरकारी दफ्तर

म प्र में कई विभागों में सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती पर रोक लगी हुई है। ऐसे में साल दर साल कर्मचारी तो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उनकी जगह नई भर्ती नहीं हो रही है। अगर सरकार ने सीधी भर्ती पर से रोक नहीं हटाई तो करीब साढ़े तीन साल बाद सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा पसर जाएगा। इसकी वजह यह है कि 2025 तक प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों में से 60.18 प्रतिशत कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे।

मंत्रालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राजधानी समेत प्रदेशभर के सरकारी दफ्तरों में कार्यरत 2 लाख 63 हजार अधिकारी-कर्मचारी अगले साढ़े तीन साल में रिटायर हो जाएंगे। इसी साल करीब 25 हजार अधिकारी और कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे। कर्मचारी मामलों के जानकार एमपी द्विवेदी के मुताबिक अभी ज्यादातर पुराने कर्मचारी वे हैं जो वर्ष 1977-78 से सेवा में हैं। इस लिहाज से उनकी सेवा अवधि 44 साल और उम्र करीब 60 साल हो रही है। अगले 3 साल में यह सभी रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में सीधी भर्ती पर लगी रोक नहीं हटी तो विभागों में काम करने के लिए पर्याप्त नियमित कर्मचारी भी नहीं बचेंगे। फिलहाल सिर्फ स्कूल शिक्षा और गृह विभाग में सीधी भर्तियां शुरू हो सकी हैं।

प्रदेश में सरकार भर्तियां भले ही रुकी हुई हैं, लेकिन सरकारी अधिकारी-कर्मचारी हर साल रिटायर हो रहे हैं। वर्ष 2021 में 22 हजार 544 अधिकारी और कर्मचारी रिटायर हुए थे। इनमें वर्ष 1977-78 के आसपास सेवा में आए अधिकारी-कर्मचारी सबसे ज्यादा थे। 2001 में नियमित एम्प्लॉई 5 लाख 13 हजार थे, अब 4 लाख 37 हजार बचे हैं। रिटायर होने वालों में प्रथम श्रेणी अधिकारी- 1138, द्वितीय श्रेणी अधिकारी- 2136, तृतीय श्रेणी कर्मचारी- 15974 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी- 3296 थे। वहीं इस साल 7 प्रमुख विभागों में ही 14 हजार 821 एम्प्लॉई रिटायर हो जाएंगे। सांख्यिकी अधिकारी जितेंद्र सिंह के मुताबिक 2001 में प्रदेश में नियमित अधिकारी-कर्मचारियों की संख्या 5 लाख 13 हजार थी। 31 मार्च 2018 में यह आंकड़ा घटकर 4,52,439 हो गया। मौजूदा स्थिति के मुताबिक प्रदेश में 4 लाख 37 हजार नियमित अधिकारी-कर्मचारी हैं।

जानकारों का कहना है कि कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए सरकार को सीधी भर्ती से रोक हटाना होगी। कर्मचारी आयोग के पूर्व सदस्य वीरेंद्र खोंगल कहते हैं कि इतनी तादाद में रिटायरमेंट से विभागों में कार्य व्यवस्था प्रभावित होगी। राज्य सरकार के पास कैडर मैनेजमेंट की अब तक कोई पॉलिसी नहीं है, जो बनानी होगी। साथ ही सीधी भर्ती पर लगी रोक हटाना होगी। वहीं राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के चेयरमैन रमेशचंद्र शर्मा का कहना है कि विभागों में करीब 2.5 लाख अधिकारी-कर्मचारी 2025 के अंत तक रिटायर हो रहे हैं। इसकी बारीकी से समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जो मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। इसमें व्यवस्था न बिगड़े, इसकी रूपरेखा भी शामिल रहेगी।

गौतलब है कि राज्य की प्रशासनिक मशीनरी उम्रदराज अधिकारियों और कर्मचारियों के सहारे चल रही है। उम्रदराज अधिकारियों और कर्मचारियों के कारण योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर नहीं हो पा रहा है। जिसके आम जन को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उधर सरकार खाली पदों पर नई भर्ती नहीं कर रही है। प्रदेश के सरकारी विभागों में प्रथम श्रेणी संवर्ग के करीब 3 हजार पद खाली हैं। यह हैरानी की बात है कि युवाओं के इस प्रदेश में स्थिति यह है कि 44 विभागों में तो 30 साल तक की आयु का एक भी अधिकारी नहीं है, जबकि 9 विभागों में मात्र 115 ही अधिकारी कार्यरत हैं। वैसे सरकारी सेवाओं में महिलाओं का प्रतिशत पहले से बढ़कर 25 प्रतिशत हो गया है, जबकि पिछले साल इनका प्रतिशत 18 था।

प्रदेश में सरकारी विभागों में वर्षों से भर्तियां नहीं होने के कारण प्रथम श्रेणी के करीब 3 हजार पद खाली हैं। सभी 57 विभागों में करीब 11 हजार पद स्वीकृत हैं, जिसके एवज में 7,732 ही अधिकारी कार्यरत हैं। उधर सभी संवर्गों में सबसे अधिक कर्मचारी स्कूल शिक्षा विभाग में 2 लाख 4 हजार 288 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो कि अन्य विभागों का 35 प्रतिशत है। विभागों में शासकीय नियमित अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन निगम-मंडलों में इनकी संख्या 60 हजार से घटकर 45 हजार रह गई है। यानि महिलाओं को भी 30 प्रतिशत आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।

● **जितेंद्र तिवारी**

डेढ़ लाख से अधिक कर्मचारी उम्रदराज

सरकारी विभागों में 51 से 55 साल के बीच की आयु के 88 हजार 610 और 55 से 60 साल आयु के 75 हजार 353 अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत हैं। यानी इनकी संख्या 1 लाख 63 हजार 963 है, जबकि 60 साल से अधिक आयु के अधिकारियों, कर्मचारियों की संख्या 24 हजार 86 है। 18 से 30 साल तक की आयु वर्ग के प्रथम श्रेणी के अधिकारी जिन विभागों में कार्यरत हैं, उनमें कृषि कल्याण में एक, वन विभाग में 19, तकनीकी शिक्षा में 82, स्वास्थ्य विभाग में 3, चिकित्सा शिक्षा में 2, महिला एवं बाल विकास में एक, जीएडी में एक, गृह विभाग में 4 तथा राजस्व विभाग में 12 ही अधिकारी पदस्थ हैं। प्रदेश में अब सरकारी विभागों में भर्तियां करने की मांग उठने लगी हैं। सपाक्स के अध्यक्ष जेएस तोमर का कहना है कि सरकारी विभागों में भर्तियां करने की मांग लगातार कर रहे हैं। केवल 5 प्रतिशत पदों पर ही भर्तियां हो रही हैं। इससे अधिकारियों के पद खाली हैं। पीएससी की भर्ती में भी ओबीसी आरक्षण का विवाद है।

मप्र में आगामी विधानसभा चुनाव शिवराज सिंह चौहान बनाम कमलनाथ होगा। इसको लेकर दोनों पार्टियों ने चुनावी जमावट शुरु कर दी है। भाजपा पूरी तरह चुनावी मोड में है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में पार्टी मिशन 2023 की रणनीति में कांग्रेस से काफी आगे है। भाजपा का पूरा फोकस प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 200 सीटों को जीतने पर है। इसके लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी मोर्चा संभालना शुरु कर दिया है।

200 पार के लक्ष्य पर फोकस

मप्र में मिशन 2023 का घमासान दिन पर दिन तेज होता जा रहा है। भाजपा का पूरा फोकस 200 पार के लक्ष्य पर है। इसके लिए हर स्तर पर तैयारी चल रही है। वहीं निकाय और पंचायत चुनाव की गतिविधियां तेज हो चली हैं। इन्हें लेकर भाजपा संगठन भी अतिरिक्त सक्रिय हो चुका है। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे मंडल अध्यक्षों व पदाधिकारियों से रूबरू होंगे। सत्ता-संगठन के तालमेल पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रदेश भाजपा की कार्यसमिति को भी संबोधित करेंगे। दो सप्ताह पूर्व ही भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश भी जिलों की कोर कमेटियों से मैदानी फीडबैक लेकर गए हैं। ऐसे में राजस्थान में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद नड्डा का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है।

भाजपा अध्यक्ष का यह दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि अब मप्र पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है। प्रदेश में पहले दौर में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं। इसके बाद 2023 में विधानसभा चुनाव होंगे। निकाय और पंचायत चुनावों को 2023 के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। ताकि चुनाव से पहले सभी कमियों को दूर किया जा सके। इससे पहले इस साल मार्च में नड्डा ने इंदौर और अप्रैल में गृहमंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा किया था।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मप्र का दौरा विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बेहद अहम है। वे अपने दौरे के दौरान सत्ता और संगठन के तालमेल पर बात करेंगे। 2023 और 2024 के चुनावी रोडमैप पर भाजपा संगठन से चर्चा करेंगे। क्योंकि प्रदेश निकाय-पंचायत चुनाव के मुहाने पर हैं, इसलिए वे टिकट वितरण के मापदंडों पर भी संगठन से चर्चा कर सकते हैं। सत्ता-संगठन के बीच चल रही खींचतान की खबरों को लेकर सूत्रों का कहना है कि मप्र के राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि दोनों के बीच तालमेल का अभाव है। लेकिन अन्य पार्टियों की तरह भाजपा में कभी भी अनबन सतह पर नहीं दिखाई देती। देश में एकमात्र मप्र ऐसा राज्य है, जहां भाजपा का संगठन सबसे मजबूत और संगठित है। इसकी मिसाल पूरे देशभर में दी जाती है।

सत्ता, संगठन और संघ ने पहले ही संकेत दे दिया है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ही पार्टी का मुख्य चेहरा होंगे। सर्वे में भी लोगों ने इस पर मुहर लगाई है। गौरतलब है कि **आगामी दिनों** में भाजपा शासित हिमाचल प्रदेश और गुजरात में इस वर्ष नवंबर-दिसंबर महीने में चुनाव होने की संभावना है। उम्मीद यही की जा रही है कि इन दोनों राज्यों के साथ जम्मू और कश्मीर में भी चुनाव होगा। फिर अगले वर्ष फरवरी-मार्च महीने में मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में चुनाव होगा। मेघालय और नागालैंड में स्थानीय क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व में भाजपा के सहयोगी दलों की सरकार है, जबकि त्रिपुरा में भाजपा पहली बार 2018 में चुनाव जीतकर सरकार बनाने में सफल रही थी। फिर अगले वर्ष मई में कर्नाटक में चुनाव निर्धारित है। 2018 में हुए चुनाव में कर्नाटक में त्रिशंकु विधानसभा चुनी गई थी, जिसमें भाजपा साधारण बहुमत से 8 सीटों से दूर रह गई थी। भाजपा को सत्ता से दूर रखने के इरादे से कांग्रेस

10 फीसदी वोट शेयर बढ़ाने पर होगी चर्चा

पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर भाजपा संगठन सतर्क हो गया है। इसलिए शिवप्रकाश के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रवास महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वे विधायकों, मंत्रियों और सांसदों के काम की समीक्षा भी करेंगे। इस दौरान जमीनी कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेंगे। वहीं, अगले महीने से भाजपा के नए ऑफिस का काम भी प्रारंभ होना है। उसकी रूपरेखा भी तय की जाएगी। बैठक में मंडल के पदाधिकारियों से बूथ विस्तारक अभियान और पार्टी के 10 फीसदी वोट शेयर बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। भाजपा अध्यक्ष स्थानीय निकाय चुनावों के लिए चुनावी रणनीति पर चर्चा करने के लिए संगठन के पदाधिकारियों से भी मिलेंगे, ताकि चुनाव से पहले सभी कमियों को दूर किया जा सके। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि हमारा सौभाग्य है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक से तीन जून तक मप्र के दौरे पर रहेंगे। एक जून को वे भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यसमिति के सदस्यों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे।

पार्टी और जनता दल (सेक्युलर) की मिलीजुली सरकार बनी। दोनों दलों के कई विधायक बाद में बगावत करके भाजपा में शामिल हो गए और 2019 अंतत: भाजपा की सरकार बन ही गई। और फिर 2023 के नवंबर-दिसंबर महीने में छत्तीसगढ़, मप्र, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होगा।

इन सभी 12 चुनावी राज्यों में मप्र ही एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां भाजपा सबसे सुरक्षित और संगठित है। अत: संगठन और संघ मप्र को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। जबकि अन्य राज्यों में भाजपा कुछ बदलाव कर सकती है। अभी हाल ही में राजस्थान में संपन्न भाजपा की बड़ी बैठक में राष्ट्रीय नेताओं ने भी संकेत दिया कि मप्र में पार्टी सबसे मजबूत और संगठित स्थिति में है। वहीं राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की घोषणा की गई। दरअसल, 2018 में सत्ता जाने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह जनता के बीच सक्रियता दिखाई, उससे भाजपा के प्रति मतदाताओं का विश्वास प्रगाढ़ हुआ है। वहीं चौथी पारी में मुख्यमंत्री बनने के बाद से शिवराज सिंह चौहान ने बिना आराम किए प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया है, उससे भाजपा आज मजबूत स्थिति में पहुंच गई है।

उधर 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस जितनी संगठित थी इस बार वह उतनी ही बेदम है। प्रदेश में अंगद की तरह पैर जमाकर बैठे शिवराज सिंह चौहान को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस के साथ-साथ भाजपा के अनेक असंतुष्ट भी कोशिश करते रहे, मगर उन्हें अभी तक तो कामयाबी नहीं मिली। नर्मदा की तलहटी में बचपन से तैरने वाले शिवराज राजनीति के अनेक सैलाब को पार करते चले गए। दिग्विजय सिंह की सरकार को सत्ता से हटाने के साथ प्रदेश में भाजपा सरकार के करीब 19 साल और शिवराज के करीब 17 साल के शासन के विरोध में कांग्रेस ने उन्हें उखाड़ फेंकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन शिवराज उतने ही मजबूत होते चले गए। यह तो तय है कि मप्र में होने वाले आगामी विधानसभा के चुनाव लगातार चौथी बार सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह

चौहान के नेतृत्व में ही भाजपा लड़ेगी! इसके पीछे कई कारण हैं। पहला यह कि आज भाजपा के पास शिवराज का विकल्प नहीं है और शिवराज अपनी अनेक लोकलुभावन योजनाओं के कारण चर्चित हैं। पार्टी में अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा के साथ-साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी उनके संबंध मधुर हैं। जो उन्हें स्थायित्व प्रदान किए हैं।

वहीं 2003 के विधानसभा चुनाव से मिशन-2018 तक प्रयोग में उलझी कांग्रेस प्रदेश के दिग्गजों की खेमेबाजी में ऐसी उलझी है कि सत्ता में आने के बाद भी 15 माह के अंदर ही सत्ता गंवानी पड़ी। इन सालों में कांग्रेस ने हर कोशिश की कि ये गुटबंदी खत्म हो जाए, पर ज्यों-ज्यों दवा की **त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता ही गया** कि तर्ज पर मसला ऐसा उलझता गया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी इसे नहीं सुलझा पाए। अब जबकि देश के सबसे बड़े हिंदी राज्य उप्र में लगातार दूसरी बार भाजपा की सरकार बन जाने के बाद मप्र ही कांग्रेस को दिखाई दे रहा है कि यहां अगर भाजपा को नहीं रोका गया तो कांग्रेसमुक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को रोकने की कोई राह उसके पास बचेगी! इसलिए कांग्रेस एक बार फिर से समन्वय की कवायद में जुटी हुई है।

मप्र में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि पूरी भाजपा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व को पूरे मन से स्वीकार रही है। इसलिए उसके सामने भाजपा को हराने के लिए कोई माध्यम नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा जुनून, जज्बे और लक्ष्य के साथ मैदान में उतरती है। तभी वह हर काम में सफलता अर्जित कर लेती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चौथी पारी में सत्ता, संगठन और संघ का समन्वय हर बार की अपेक्षा अधिक देखा जा रहा है। इसलिए कांग्रेस के लिए 2023 बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है।

प्रदेश सरकार इस समय मिशन मोड में है। इसकी वजह है आगामी विधानसभा चुनाव। भाजपा सरकार आगामी विधानसभा चुनाव में विकास के मुद्दे पर मैदान में उतरेगी। इसके लिए विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को धड़ाधड़ मंजूरी दी जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आत्मनिर्भर मप्र अभियान को प्रदेश के गांव संबल दे रहे हैं। इसकी वजह यह है कि प्रदेश सरकार के नवाचारों से गांवों की तस्वीर बदली है। प्रदेश सरकार का शहर की ही तरह गांवों के विकास पर भी फोकस है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की अभ्युदय योजना को माध्यम बनाया है।

● **कुमार राजेन्द्र**

सिंधिया का बढ़ा कद, कोर ग्रुप और इलेक्शन कमेटी में शामिल

भाजपा ने स्टेट इलेक्शन कमेटी, स्टेट कोर ग्रुप, प्रदेश आर्थिक समिति और प्रदेश अनुशासन समिति की घोषणा कर दी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इलेक्शन कमेटी के साथ कोर ग्रुप में जगह दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खास माने जाने वाले विधायक रामपाल सिंह को इलेक्शन कमेटी में जगह दी गई है। इसमें एससी-एसटी वर्ग के कोटे से भी दो नए नाम जोड़े गए हैं। इसमें सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक को जगह दी गई है। वहीं, सीनियर लीडर अध्यक्ष विक्रम वर्मा, सत्य नारायण जटिया, प्रभात झा, कृष्ण मुरानी मोघे को कोर ग्रुप में जगह नहीं मिल पाई है। वीडी शर्मा के बीते दो साल के कार्यकाल के बाद यह बदलाव देखने को मिला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 जून से तीन दिनों के मप्र प्रवास पर रहेंगे। 1 जून को वे भोपाल में रहेंगे। इससे पहले यह बदलाव किया गया है। नए कोर ग्रुप, इलेक्शन कमेटी के साथ नड्डा बैठक करेंगे।

जुबानी जंग से असहज भाजपा

सिंधिया समर्थक मंत्रियों से संगठन भी नाखुश

चाल, चेहरा, चरित्र वाली भाजपा में संगठन सर्वोपरि होता है। संगठन के दिशा-निर्देश पर ही नेता काम करते हैं। लेकिन जबसे भाजपा में सिंधिया समर्थक नेता शामिल हुए हैं, पार्टी में बदजुबानी बढ़ गई है। खासकर सिंधिया समर्थक मंत्री अपनी ऊटपटांग बयानबाजी और हरकतों के कारण चर्चा का विषय बने रहते हैं। सिंधिया समर्थक मंत्रियों से संगठन भी नाखुश है। कई बार मंत्रियों को हिदायत दी जा चुकी है कि वे सरकार और संगठन की गाइडलाइन के अनुसार ही व्यवहार करें। लेकिन ना चाहकर भी मंत्री कई बार ऐसा कुछ कह या कर जाते हैं जिससे भाजपा और प्रदेश सरकार की किरकिरी होती है।

सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के कारण राज्य में अपनी मजबूती का एहसास कराने वाली भाजपा इन दिनों गुना-शिवपुरी संसदीय सीट को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों एवं भाजपा सांसद केपी यादव के बीच चल रही जुबानी जंग से असहज महसूस कर रही है। हाल ही में गुना के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में राज्य सरकार के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया ने मंच पर मौजूद सिंधिया से मुखातिब होकर यह कहते हुए माफी मांगी कि लोकसभा चुनाव में आपको हराकर यहां की जनता ने गलती की है। मैं सभी की ओर से माफी मांगता हूं। दरअसल सिसौदिया बताना चाहते थे कि गुना की जनता सिंधिया से बहुत प्यार करती है और उनकी हार पर अफसोस कर रही है। वह सिंधिया के वफादार मंत्रियों में हैं।

उनकी इस टिप्पणी पर भाजपा संगठन ने तो तत्काल कुछ नहीं कहा लेकिन एक दिन बाद ही सांसद केपी यादव बिफर पड़े। उन्होंने सिसौदिया पर निजी टिप्पणी करते हुए कहा कि 'कांग्रेस की हार पर आंसू बहाने वाले मंत्री ने भाजपा के कार्यकर्ताओं और जनता का अपमान किया है। उनकी यह हरकत मूर्खतापूर्ण है और लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है। गुना-शिवपुरी से भाजपा की जीत हजारों कार्यकर्ताओं के त्याग और संघर्ष की जीत है। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति भाजपा की सरकार में मंत्री है वह कांग्रेस की हार का रोना कैसे रो सकता है। यादव इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने सिसौदिया के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना अकबर जैसे क्रूर मुगल शासक से करके उन्होंने करोड़ों देशवासियों की भावनाओं का अपमान किया है। मोदी की तुलना करनी है तो वीर शिवाजी से करनी चाहिए। यादव के बयान के बाद एक और दर्जा प्राप्त मंत्री गिर्राज डंडौतिया ने भी यह कहकर इस विवाद को हवा दे दी कि सिंधिया को हराकर गुना की जनता आंसू बहा रही है। मामला बढ़ता देख आखिरकार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने सख्ती का संदेश देते हुए सांसद केपी यादव एवं मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया से स्पष्टीकरण मांग लिया।

2019 के संसदीय चुनाव में गुना-शिवपुरी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी केपी यादव ने कांग्रेस के तत्कालीन सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगभग एक लाख से अधिक मतों से हरा दिया था। यह सिंधिया के राजनीतिक जीवन की पहली हार थी। भाजपा ने यादव की जीत पर खूब धूमधड़ाका किया था। माना गया था कि अपराजेय समझे जाने वाले सिंधिया को हराकर भाजपा ने सफलता की नई कहानी लिखी है। हालांकि लगभग एक साल बाद ही सिंधिया अपने समर्थक विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। वह राज्य में भाजपा के एक नए शक्तिकेंद्र के रूप में देखे जाते हैं। वह खुद केंद्र में नागरिक उड्डयन जैसा मंत्रालय संभाल रहे हैं जबकि उनके समर्थक अनेक विधायक शिवराज सरकार में मंत्री हैं। भाजपा में उन्हें दो साल से ज्यादा हो चुके हैं। वह पार्टी की रीति-नीति को पूरी तरह आत्मसात कर चुके हैं। वह विचारधारा के स्तर पर जिस तरह भाजपा का पक्ष रखते हैं उससे भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेता भी गहरे प्रभावित हैं। वे यह कहते नहीं थकते कि हमें महसूस ही नहीं होता है कि सिंधिया कभी हमसे अलग थे। इसके उलट गुना-शिवपुरी में उनके समर्थकों में उनकी हार की टीस अभी भी है। वे केपी यादव को मन से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि वहां सांसद अलग-थलग पड़े रहते हैं। बीच-बीच में एक-दूसरे के खिलाफ बयान देकर वे माहौल गर्माए रहते हैं।

दरअसल केपी यादव पूर्व में कांग्रेस में सिंधिया के कट्टर समर्थक थे। सिंधिया के सांसद रहते वह उनके प्रतिनिधि की भूमिका निभाते रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अशोकनगर सीट से कांग्रेस के टिकट की मांग की थी। आश्वासन मिलने के कारण वह तैयारियों में लग गए थे लेकिन समीकरण ऐसे बने कि टिकट नहीं मिल पाया। इससे खफा होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने अवसर का लाभ उठाते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें सिंधिया के खिलाफ अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। उम्मीद के विपरीत उन्होंने सिंधिया को पराजित कर दिया। तभी से दोनों के बीच दरारें गहरी हो चुकी हैं।

सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद केपी यादव ने उनके साथ कुछ कार्यक्रमों में मंच साझा किया था लेकिन बाद में महत्व न मिलने का आरोप लगाते हुए वह दूरी बनाने लगे। बीच-बीच में सिंधिया समर्थकों और यादव के बीच जुबानी जंग चलती रहती है लेकिन इस बार मामला बढ़ने पर प्रदेश नेतृत्व समय से सक्रिय हो गया और सांसद के साथ मंत्री सिसौदिया को प्रदेश कार्यालय में बुलाने का आदेश दे दिया गया। सांसद ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपनी सफाई दे दी है कि सिंधिया समर्थक मंत्री उन्हें बार-बार सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करते रहते हैं। मंत्री सिसौदिया एवं गिर्राज डंडौतिया को भी कार्यालय आकर सफाई देने के लिए कहा गया है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने दोनों पक्षों को संदेश दिया है कि किसी भी स्थिति में अपने मतभेद सार्वजनिक रूप से न व्यक्त करें। कोई दिक्कत है तो पार्टी फोरम पर बात की कही जाए। सुनवाई सबकी होगी।

● **विकास दुबे**

चौतरफा घेराबंदी करेगी कांग्रेस

मप्र की 230 विधानसभा सीटों के चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति को धार देना तेज कर दिया है। विधानसभा वार पार्टी सोशल मैपिंग की तैयारी में है। पार्टी सभी 230 सीटों के सामाजिक और जातिगत समीकरणों की मैपिंग करने की तैयारी में है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस नेता अरुण यादव को जिम्मेदारी दी है। अरुण यादव ओबीसी के साथ एससी, एसटी और सामान्य वोटरों की सोशल मैपिंग तैयार करेंगे। कांग्रेस इस बार चुनाव से पहले सोशल मैपिंग का खाका तैयार कर उम्मीदवार चुनेगी। सिर्फ सोशल मैपिंग ही नहीं बल्कि भाजपा को घेरने के लिए कांग्रेस ने आरोप पत्र बनाना शुरू कर दिया है। भाजपा सरकार के मंत्रियों और उनके विभागों से जुड़े मामलों को खंगाला जा रहा है। उसके जरिए कांग्रेस चुनाव के ठीक पहले आरोप पत्र जारी कर भाजपा को कटघरे में खड़ा करेगी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस 2023 के चुनाव के लिए हर उस रणनीति पर काम कर रही है जो भाजपा को घेरने में सफल हो सके।

प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही डेढ़ साल का समय बाकी हो लेकिन कांग्रेस पार्टी हर उस रणनीति के तहत खुद को तैयार करने की कोशिश में है जो 2023 के चुनाव में भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को मजबूती दे सके। 2018 के चुनाव परिणाम उसका आत्मविश्वास बढ़ाए हुए हैं। जनता ने तो उसका साथ दिया था। अगर सिंधिया दल न बदलते तो पार्टी सत्ता में होती। यही कारण है कि सर्वे के अलावा दो बड़े नेताओं को अलग-अलग जिम्मेदारी देकर कांग्रेस भाजपा की चौतरफा घेराबंदी करने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस पार्टी वचन-पत्र तैयार करने में जुट गई है। इस बार वचन-पत्र तैयार करने के लिए कमलनाथ ने नेताओं से जमीनी हकीकत टटोलने को कहा है। इसके लिए उन्होंने तौर-तरीकों में बदलाव लाने को कहा है। कांग्रेसी नेताओं से कहा गया है कि वे कंफर्ट जोन से बाहर आएं। लक्जरी गाड़ी से उतरकर जनता के बीच जाकर जनसंपर्क करें। इसके लिए रोजाना 10 किमी के क्षेत्र में पैदल जनसंपर्क कर सीधे पब्लिक से कनेक्ट होने का टास्क दिया है।

कमलनाथ कांग्रेसी नेताओं की जमीनी रिपोर्ट भी तैयार करा रहे हैं। भोपाल में हुई कांग्रेस की बैठक में कमलनाथ ने साफ शब्दों में कहा है कि वचन-पत्र में वही योजनाएं शामिल की जाएं, जिनको पूरा किया जा सके। इसके लिए जनता के बीच में जाकर वचन-पत्र में जनता से मुद्दों को शामिल करने की बात कही है। कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में हर हाल में जीत हासिल करना चाहती है। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ लगातार रणनीतिक तैयारी में जुटे हुए हैं। उन्होंने जिलेवार और विधानसभावार नेताओं को जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी है। लेकिन पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती हैं, वे 13 जिले जहां कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी के दिग्गज नेताओं को इन विधायक विहीन जिलों की जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता को उनकी पसंद और पकड़ के जिलों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

गौरतलब है कि प्रदेश के 52 जिलों में से 13 ऐसे हैं, जहां से कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। इसे देखते हुए पार्टी ने इन जिलों में वरिष्ठ नेताओं को मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी दी है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव, नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह, अजय सिंह, राजमणि पटेल सहित अन्य नेता शामिल हैं। ये न सिर्फ इन जिलों में सक्रियता बढ़ाएंगे बल्कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। जिले में काम करने वाले विभिन्न संगठनों से संवाद बढ़ाकर उन मुद्दों पर काम करेंगे, जो मतदाताओं को प्रभावित करते हैं।

प्रदेश के जिन 13 जिलों में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है, वहां 42 विधानसभा सीटें हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार-विमर्श करके मिशन 2023 के लिए जिलेवार कार्ययोजना तैयार की है। वरिष्ठ नेताओं-कार्यकर्ताओं से संगठन की गतिविधि बढ़ाने, मतदाता संपर्क अभियान चलाने और मतदान केंद्रों पर कार्यकर्ताओं की सशक्त टीम बनाने के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। साथ ही संभावित प्रत्याशी को लेकर उनकी राय ली जाएगी। इसके साथ ही ऐसे संगठनों के पदाधिकारियों के साथ भी बैठकें की जाएंगी, जिनका समाज के विभिन्न वर्गों में अच्छा दखल है। इनसे जिले के प्रमुख मुद्दे पर बात होगी। प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर ने बताया कि पार्टी मिशन 2023 की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है। वरिष्ठ नेताओं को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी है। जिन जिलों में अभी हमारे एक भी विधायक नहीं है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि 2023 में पार्टी की जीत सुनिश्चित हो सके।

● **राजेश बोरकर**

प्रदेश अध्यक्ष भी संभालेंगे मोर्चा

विधायक विहीन जिलों में पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी मोर्चा संभालेंगे। इन जिलों में बूथ, मंडलम और सेक्टर समितियों के पदाधिकारियों के सम्मेलन होंगे। इनमें प्रदेश कांग्रेस के नेता हिस्सा लेंगे। इसके अलावा संभाग स्तरीय सम्मेलन भी किए जाएंगे। ये वरिष्ठ नेताओं की बैठक होने के बाद प्रारंभ होंगे। गौरतलब है कि नवंबर 2020 में हुए उपचुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति में परिवर्तन आया है। खंडवा में मांधाता, बुरहानपुर में नेपानगर, मंदसौर में सुवासरा और निवाड़ी जिले में पृथ्वीपुर सीट पर चुनाव हारने के बाद इन जिलों में कांग्रेस का कोई विधायक नहीं रह गया है। प्रदेश के जिन जिलों में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है उनमें टीकमगढ़, निवाड़ी, रीवा, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, हरदा, नर्मदापुरम, सीहोर, खंडवा, बुरहानपुर, नीमच और मंदसौर आदि शामिल हैं।

मप्र के गांवों में बड़ी आबादी नहीं कर रही शौचालय का उपयोग

स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किए हुए लगभग 8 साल हो गए हैं, लेकिन विडंबना यह है कि देश पूरी तरह खुले में शौच मुक्त नहीं हो पाया है। हैरानी की बात यह है कि शौचालय होने के बाद भी मप्र में 33.3 प्रतिशत ग्रामीण आबादी खुले में शौच कर रही है। इसकी वजह है कागजों पर शौचालय, पानी की कमी, घटिया क्वालिटी के शौचालय या आदत में बदलाव नहीं होना आदि। इसका खुलासा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस-5) की 2019-21 की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार देश के ग्रामीण इलाकों में आज भी 25.6 फीसदी आबादी खुले में शौच करती है। शहरी क्षेत्र की बात करें तो 6.1 फीसदी आबादी खुले में शौच कर रही है। मप्र में 33.3 प्रतिशत ग्रामीण आबादी शौचालय का उपयोग नहीं कर रही। शहरी क्षेत्रों में 7.1 फीसदी लोग खुले में शौच कर रहे हैं। हालांकि राहत की बात ये है कि 2015-16 के मुकाबले खुले में शौच करने वालों के आंकड़ों में 2019-21 में सुधार हुआ है। देश में 2015-16 में जहां ग्रामीण क्षेत्रों में 54 प्रतिशत से ज्यादा लोग खुले में शौच करते थे तो वहीं शहरी क्षेत्रों में ये आंकड़ा 10.5 प्रतिशत था। शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा गांवों में खुले में शौच करने वाले लोगों में 25 प्रतिशत की कमी आई है।

एनएफएचएस-5 की रिपोर्ट के अनुसार खुले में शौच करने वाले राज्यों में मप्र पांचवें स्थान पर है। बिहार 43.9 प्रतिशत के साथ पहले, झारखंड 41 प्रतिशत के साथ दूसरे, ओडिशा 37 प्रतिशत के साथ तीसरे, तमिलनाडु 33.9 प्रतिशत के साथ चौथे, मप्र 33.3 प्रतिशत के साथ पांचवें और गुजरात 31.4 प्रतिशत के साथ छठे स्थान पर है। मप्र की 33 फीसदी से ज्यादा ग्रामीण आबादी खुले में शौच करती है। चिंता की बात ये है कि मप्र अभी भी उन शीर्ष राज्यों में शुमार है, जहां ज्यादा लोग शौचालय का प्रयोग नहीं करते। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा खुले में शौच करने वाले राज्यों की सूची में मप्र 5वें नंबर पर है। रिपोर्ट के अनुसार खुले में शौच को लेकर ग्रामीण आबादी की सोच में बदलाव हुआ है। 2015-16 में जहां पूरे ग्रामीण भारत की 54 प्रतिशत आबादी खुले में शौच करती थी, तो वहीं साल 2019-21 में 25 प्रतिशत की गिरावट के साथ ये आंकड़ा 25.9 प्रतिशत पर आ गया। यानी भारत की अभी भी 25.9 प्रतिशत ग्रामीण आबादी खुले में शौच कर रही है।

दरअसल, प्रदेश सरकार ने स्वच्छता अभियान के तहत प्रत्येक पंचायत को गांव में शौचालय निर्माण कराने की जिम्मेदारी दी। प्रत्येक शौचालय के लिए 3.50 लाख रुपए दिए गए। पंचायतों ने शौचालयों का निर्माण भी करा लिए, लेकिन अधिकांश पर ताले लगे हैं। बाहर से आने-जाने वाले व ग्रामीण इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ताले लगने का प्रमुख कारण पानी तथा सफाई व्यवस्था का अभाव बताया जा रहा है। सरकार ने जनपद के माध्यम से पंचायतों को शौचालय निर्माण कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी। शौचालय के लिए ऐसे स्थान का चयन करना था जहां गांव से निकले वाले बाहरी लोगों के साथ जरूरत पड़ने पर स्थानीय लोग भी इसका उपयोग कर सकें। अधिकांश पंचायतों में बस स्टैंड के पास शौचालय बनवाए गए। 3.50 लाख रुपए में पुरुष व महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय के साथ छत पर पानी की टंकी रखना भी शामिल था। 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने के साथ सफाई की जिम्मेदारी भी पंचायत की ही है। सरपंच-सचिवों ने राशि **मिलते ही तुरत-फुरत निर्माण** कराकर अपना कमीशन तो ले लिया, लेकिन इनके संचालन के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई। शौचालयों पर रखी टंकियों में पंचायत पानी नहीं भर पा रही है। सफाई की व्यवस्था भी नहीं होने से इन पर ताले जड़ दिए गए हैं।

स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी जिसका उद्देश्य 2019 तक ग्रामीण क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त करना था। जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों को शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपए की राशि दी गई ताकि वह अपने घरों में शौचालय निर्माण करवा सकें लेकिन लापरवाह कार्यप्रणाली के चलते सरकार का यह सपना सिर्फ सपना बनकर रह गया। जिसका उदाहरण ग्रामीण क्षेत्रों में खंडहर हो रहे शौचालय जिनका ठेकेदारी प्रथा के आधार पर निर्माण होने की वजह से गुणवत्ताहीन निर्माण किया गया। यही कारण है कि गांवों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालय उपयोग के लायक ही नहीं है। दरअसल इसके घटिया निर्माण की वजह से यह मजबूती प्रदान नहीं कर पाए कहीं बिना गड्ढे के सीट लगाकर उसकी फोटो खींचकर पूरा करा दिया। अधिकारियों के निरीक्षण न करने के कारण ग्राम पंचायत मिलीभगत से यह निर्माण किए गए।

● **अरविंद नारद**

प्रदेश में लाखों शौचालय उपयोग लायक नहीं

प्रदेश खुले में शौच मुक्त राज्य है। यानी 100 फीसदी ओडीएफ। मप्र को ओडीएफ बनाने के लिए सरकार ने 97,60,574 घरों में शौचालय बनवाए हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के कारण ये शौचालय कागजों में ही रह गए। प्रदेशभर में लाखों लोग आज भी खुले में शौच करने को मजबूर हैं। दरअसल, प्रदेशभर में जो शौचालय बनाए गए हैं या तो वे कागजों पर बने हैं या फिर गुणवत्ताहीन हैं। सरकार ने कई स्तरों पर इसकी जांच-पड़ताल भी की, लेकिन भ्रष्टाचारियों तक आंच नहीं पहुंची। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। इसके लिए घर-घर शौचालय के जरिए स्वच्छता की योजना परवान चढ़नी थी, मगर भ्रष्टाचार की गंदगी ने इसे भी गंदा कर डाला। भ्रष्टाचारियों ने गांव में शौचालय निर्माण की योजना को चूना लगा दिया। अब खुले में शौच मुक्त अभियान की सच्चाई खुलकर सामने आने लगी है। सरपंचों और ग्राम सचिवों ने शौचालय निर्माण में जमकर खेला किया। प्रदेशभर में शौचालय निर्माण में जमकर घोटाले हुए हैं। न गड्ढा बनाया, न ही सीट लगाई, केवल दीवार खड़ी कर राशि आहरित कर ली गई है। राजधानी भोपाल, सीहोर, रायसेन, सतना, सीधी, बैतूल, सिंगरौली, खंडवा, बुरहानपुर सहित डेढ़ दर्जन जिलों की स्थिति का आंकलन करने के बाद यह पाया गया कि शौचालय निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है, जिसके कारण लोग खुले में शौच करने को मजबूर हो रहे हैं।

अन्य राज्यों में लागू होगा पंजाब मॉडल?

पंजाब के मुख्यमंत्री और पूर्व स्टैंड-अप कॉमेडियन भगवंत मान ने अपने ही एक कैबिनेट मंत्री डॉ. विजय सिंगला को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर इस बात को रेखांकित किया है कि कॉमेडियन में निर्भीकता और जीवटता शायद दूसरे लोगों से कहीं ज्यादा होती है। फिर चाहे वो भगवंत मान हों या फिर व्लादिमिर जेलेंस्की। राजनीतिक हल्कों में मुख्यमंत्री मान द्वारा मात्र दो माह के कार्यकाल में ही अपने ही एक मंत्री का स्टिंग ऑपरेशन करवाकर ताबड़तोड़ उन्हें बर्खास्त कर गिरफ्तार करने के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। इस पर पंजाब भाजपा नेता हरजीत ग्रेवाल ने कहा कि यह कोई तरीका नहीं किसी को एकदम बर्खास्त कर दिया जाए। पहले मंत्री से बातचीत की जानी चाहिए, समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई भ्रष्ट नेता पार्टी में शामिल है तो **इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री** की भी है। उधर पंजाब के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री डॉ. राजकुमार वेरका ने भी मान सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पंजाब में आप सरकार के मंत्रियों को कोई हक नहीं कि वे रिश्वत मांगें, क्योंकि पंजाब में से रिश्वत मांगने का काम तो अरविंद केजरीवाल की टीम ने संभाला हुआ है।

आम आदमी की पार्टी ने दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी सुशासन का ऐसा उदाहरण पेश किया है, जो अन्य राज्यों के लिए नजीर बन गया है। जिस तरह भ्रष्टाचार के आरोप में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है, उससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या अन्य राज्य भी पंजाब के इस मॉडल को अपनाएंगे। मप्र में भी कई भाजपा नेता गुपचुप तरीके से कहने लगे हैं कि मप्र में भी इस फॉर्मूले को लागू कर देना चाहिए। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ पंजाब के मॉडल को आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सराहा जा रहा है। मप्र में भी इस मुद्दे पर जमकर चर्चा हो रही है। हर कोई यही चाहता है कि मप्र में भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इसी तरह कार्रवाई हो। मप्र में मंत्रियों और विधायकों के भ्रष्टाचार के किस्से अब लोगों की जुबां पर आ गए हैं। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता ही कहने लगे हैं कि बिना पैसे के कोई काम ही नहीं करता। मंत्रियों के बंगलों से सीधे फोन कर लोगों को बुलाया जाता है और सिस्टम के बाद ही आदेश मिल पाता है। हाथोंहाथ यह भी कहा जाता है कि रिकमंड कहीं से भी करवाओ, चलना सिस्टम से ही होगा।

मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जगह-जगह सभाओं में यह कहकर दहाड़ते हैं कि भ्रष्टाचार करने वाले को उल्टा लटका दूंगा, जमीन में गाड़ दूंगा और प्रदेश में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसके बाद भी भ्रष्टाचार चरम पर है। मंत्रियों और विधायकों के भ्रष्टाचार के किस्से आम लोगों की जुबां पर आना इस बात का संकेत है कि भ्रष्टाचार की अति हो गई है। एक वरिष्ठ मंत्री की स्थिति यह है कि वे आवेदन पर ही कोड डाल देते हैं और बाद में उनके ओएसडी संबंधित व्यक्ति को बुलाकर हिसाब-किताब कर लेते हैं।

इस देश में अमूमन राजनेताओं और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ रहा है। खासकर बीते कुछ सालों में तो भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा राजनीति में किए गए इन्वेस्टमेंट का अपेक्षित डिविडेंड ही माना जाता है। कई राजनेता और अफसर भ्रष्टाचार को कोसते हुए अरबों की संपत्ति अर्जित करते जाते हैं और जनता उनकी इस मासूम अदा को हतप्रभ होकर देखती रहती है। उल्टे कई जगह तो वो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे नेताओं को जिता भी देती है। सरकार में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार का यह कारोबार बेखटके चलता रहता है। अलबत्ता निजी तौर पर कुछ राजनेता जरूर बेदाग दिखते हैं, लेकिन वो अपवाद हैं। अगर उनके सहयोगी भ्रष्टाचार करते पकड़े जाते हैं तो उन्हें बचाने का खेल शुरू हो जाता है। यह बचाव अक्सर भ्रष्टाचार के आरोप राजनीति से प्रेरित होने, विपक्ष का षड्यंत्र होने, करप्शन के ठोस सबूत पेश करने की चुनौती देने या फिर किसी जांच कमेटी से जांच कराकर रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डालने के रूप में होता है। कुछेक मामले कोर्ट में चले जाते हैं। उन पर बरसों सुनवाई चलती है। बिरले मामलों जैसे लालू प्रसाद यादव, ओमप्रकाश चौटाला, पी. शशिकला जैसे मामलों में सजाएं भी हो जाती हैं। लेकिन इससे भ्रष्टाचारियों का हौसला कम नहीं होता। केवल करप्शन के रेट रिवाइज होते रहते हैं, जो रुपए की ताकत नापने का एक नकारात्मक जरिया होते हैं।

● **जय सिंह**

हिम्मत भरा फैसला

भगवंत मान का यह हिम्मत भरा फैसला कई मायनों में अहम है। आज देश में तकरीबन सभी सरकारें कम या ज्यादा मात्रा में भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तमाम ठेकों, टेंडरों, ट्रांसफर व पोस्टिंग में कमीशन, बयाना, नजराना और शुक्राना तय है। ये अमूमन 10 फीसदी से लेकर 25 फीसदी तक हो सकता है। किसी मंत्री या अफसर तक अगर दस्तूरी के हिसाब से यह रकम पहुंचती रहे तो भी वो 'ईमानदार' की श्रेणी में ही गिना जाता है। 'भ्रष्टाचारी' शब्द का व्यावहारिक अर्थ है तयशुदा कमीशन अथवा पैसे से ज्यादा की लालच करना। डॉ. विजय सिंगला 10 साल पहले आम आदमी पार्टी में शरीक हुए थे। पेशे से वो डेंटिस्ट और साढ़े 6 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। डॉक्टर होने के कारण ही उन्हें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का अहम पद दिया गया था। लेकिन लालच और भ्रष्टाचारी कल्चर का कोई 'दि एंड' नहीं होता। इस हिसाब से देखें तो विजय सिंगला ने बतौर कमीशन विभागीय खरीद और ठेकों का 1 फीसदी ही मांगा था, जो कमीशन की प्रचलित दरों के हिसाब से नगण्य ही कहा जाएगा। कहते हैं कि सिंगला ने 58 करोड़ के कामों के बदले सिंगला ने 1.16 की रिश्वत ठेकेदार व अफसरों से मांगी थी। राजनेताओं का चरित्र यह है कि वो पूरी बेशरमी के साथ झूठ बोल सकते हैं। भ्रष्टाचार करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण दे सकते हैं। विजय सिंगला ने भी कुछ दिन पहले मंत्रालय की कमान संभालते हुए दावा किया था कि वो भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो सकता है कि उनकी नजर में 1 परसेंट कमीशन 'भ्रष्टाचार' की श्रेणी में न आता हो।

शिवराज एक्शन में

मप्र को सुशासित राज्य बनाने के लिए शिवराज सिंह चौहान इस समय पूरी तरह एक्शन में हैं। मामा के एक्शन को देखकर अफसरान सकते में हैं। वजह यह है कि अफसरों की तनिक भी नाफरमानी बर्दाश्त नहीं की जा रही है। पहले छोटी-छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देने वाले मुख्यमंत्री अब किसी को बख्शने के मूड में नहीं हैं। अफसरों को गलती की सजा तत्काल मिल रही है। इसलिए मंत्रालय से लेकर मैदानी स्तर तक अफसर पूरी तरह सजग और सतर्क हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शासन का मूलमंत्र है- जनता ही सर्वोपरि है। ऐसे में जब भी मुख्यमंत्री के सामने जनता की उपेक्षा, योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही-भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, वे आगबबूला हो जाते हैं। उसके बाद भी भर्राशाही और लापरवाही के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने अब रोजाना जिलों की समीक्षा शुरू कर दी है। वे रोजाना दो जिलों की समीक्षा कर रहे हैं और अफसरों को दिशा-निर्देश दे रहे हैं। यानी अब मुख्यमंत्री फुल फार्म में हैं। वे खुद कहते हैं- अब मामा एक्शन में है। इसके तेवर इन दिनों अलसुबह की सामूहिक वर्चुअल बैठकों से दिखने लगे हैं। सुबह 6:30 बजे होने वाली समीक्षा बैठक ने अफसरों की नींद उड़ा दी है। जिस तरह सवाल-जवाब हो रहे हैं, उससे दूसरे जिले भी सकते में आ गए हैं। साहब, कब-क्या पूछ लें... इसका अंदाजा लगाना भी बहुत ही मुश्किल। जानकार कह रहे हैं कि प्रशासन और पुलिस की सर्जरी से पहले ये कड़वी **गोलियां और इंजेक्शन** दिए जा रहे हैं। जिसने झेल लिया, वही लंबी रेस में दौड़ पाएगा। मुख्यमंत्री कह ही रहे हैं कि जिसमें दम हो, वही रहे फील्ड में। मुख्यमंत्री के इस बदले रूप ने जंग लगे अफसरों को भी फुर्तीला बना दिया है। अब अफसर रोजाना विभाग के कार्यों का हिसाब-किताब तैयार करके अपने साथ ले जाते हैं। कई अफसर तो होमवर्क भी करने लगे हैं।

चौथी पारी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रॉबिन हुड अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। वहीं उनके इस अंदाज का ही परिणाम है कि माफिया, अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। प्रदेश सरकार ने पिछले 15 महीने में लगभग 12 हजार करोड़ रुपए की जमीन भू-माफियाओं, गुंडों और आदतन अपराधियों से मुक्त कराई है। इसके तहत 15 हजार एकड़ से ज्यादा की जमीन अवैध कब्जे से छुड़ाई गई है। छुड़ाई गई जमीनें राजस्व, नगरीय निकाय और वन विभाग की हैं। बीते मार्च में माफिया को चेतावनी देते हुए कहा था कि मप्र में मामा (शिवराज सिंह चौहान) का राज है। गुंडे और बदमाश यह न समझ लें कि कांग्रेस और कमलनाथ की सरकार है। मामा का बुलडोजर चला है। उन्होंने यह भी कहा कि मप्र में जितने भी गुंडे और अपराधी हैं, वे सुन ले कि अगर किसी गरीब और कमजोर की तरफ हाथ उठाया तो मैं मकान खोदकर मैदान बना दूंगा। उसके बाद से लगातार माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वहीं अब मुख्यमंत्री ने अफसरों पर भी नकेल कसनी शुरू कर दी है।

प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री किस कदर संवेदनशील हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अफसरों से साफ-साफ शब्दों में कह दिया है कि जिसमें दम हो वही फील्ड में रहे। दरअसल, गुना में पुलिसकर्मियों के बलिदान की घटना के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में हैं। उन्होंने कलेक्टर-आयुक्त, पुलिस अधीक्षक-पुलिस महानिरीक्षक आदि से साफ कहा है कि अपराधियों को नहीं छोड़ने का

मप्र में मंडरा रहा है बड़ा खतरा

मप्र में बड़ा आतंकी खतरा मंडरा रहा है। खुफिया खबर है कि आतंकी संगठन आपस में मिल गए हैं। सिमी, जेएमबी, सूफा समेत कई आतंकी संगठनों ने अपना महागठबंधन बना लिया है और इनकी नजर मप्र पर है। इनके साथ मप्र में सक्रिय पाकिस्तानी आंतकी संगठनों से प्रभावित कई दूसरे आतंकी संगठन भी आ गए हैं। नक्सलियों के बाद अब इन आतंकियों ने मप्र को अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया है। इनकी मप्र के साथ दूसरे राज्यों को दहलाने की साजिश है। ये इनपुट मिलते ही मप्र के साथ केंद्र की खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर आ गई हैं। भोपाल में अब थाने के बीट स्तर इंटेलिजेंस इनपुट जुटाया जा रहा है। मप्र में एक बार फिर आतंकी खतरा मंडराने लगा है। सूत्रों के अनुसार मप्र में सक्रिय आतंकी संगठनों ने अपना महागठबंधन बना लिया है। यह संगठन अब आतंकी मूवमेंट और उसके नेटवर्क को पहले से ज्यादा मजबूत कर रहा है। नक्सलियों के बाद आतंकियों ने मप्र को सबसे सुरक्षित ठिकाना माना है।

संकल्प है मेरा। कलेक्टर और आयुक्त को इसमें पुलिस का साथ देना है। शिकार कोई एक दिन नहीं होता, शिकारी-गोकशी करने वालों, जुआ-सट्टा चलाने वालों, ड्रग्स का धंधा करने वालों और अवैध शराब बेचने वालों को बर्बाद कर दें। सीईओ जिला पंचायत विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि जनकल्याण के कार्यों और योजनाओं में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये उनकी ड्यूटी है। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने डीजीपी से कहा एक बार फील्ड के अधिकारियों से बात कर लें, जो फील्ड में कुछ करके दिखा सके, वही रहेगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टालरेंस चाहिए। एक्शन में देर नहीं होनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति पैदा करें कि अपराध हो ही नहीं। मुख्यमंत्री का कहना है कि कानून व्यवस्था मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस का काम जनता के लिए शांति स्थापित करना है। वहीं मुख्यमंत्री का एक्शन कई अफसरों पर भारी पड़ने लगा है। इसकी वजह यह है कि शिवराज योजनाओं में गड़बड़ी करने वाले अफसरों पर पैनी नजर रखने के साथ उन पर कार्रवाई करने से भी नहीं चूक रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने पिछले कुछ दिनों से सुबह 6:30 बजे ही बजे अफसरों की क्लास लेना शुरू कर दिया है। वे हर रोज दो जिलों के सरकारी अफसरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करते हैं और उन्हें सख्त हिदायत तो देते ही हैं। साथ में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई भी करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री से जुड़े लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर जमीनी स्तर पर योजनाओं की जानकारियां जुटाना शुरू कर दिया है, इतना ही नहीं मुख्यमंत्री आवास से हर जिले में योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद किया जा रहा है और इस दौरान कई ऐसी जानकारियां उनके पास आ रही हैं जो आसानी से सुलभ नहीं होती, क्योंकि अधिकारी गड़बड़ियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने अपना एक अलग से खुफिया तंत्र विकसित कर लिया है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि एक जिले के कलेक्टर से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने उस इलाके के भ्रष्ट अफसरों की सूची तक उन तक पहुंचा दी और कार्रवाई के निर्देश भी दिए। ज्यादातर शिकायतें आवास निर्माण से लेकर राशन वितरण और पानी व बिजली से जुड़ी आ रही हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टरों को भी निर्देश दिए हैं कि वे अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क विकसित करें और भ्रष्ट अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई भी करें। उन्होंने समीक्षा के दौरान राजगढ़ जिले में राशन वितरण में गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इसके साथ ही आवास योजना में गड़बड़ी होने पर सात कर्मचारियों की सेवाएं भी समाप्त की गई हैं। मुख्यमंत्री हर बैठक में साफ कह रहे हैं कि वे भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल चाहते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा एक कलेक्टर को भ्रष्ट अधिकारियों की सूची सौंपे जाने के मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने तंज कसा है और सवाल किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा के भ्रष्ट अधिकारी की सूची कार्रवाई के लिए कलेक्टर को सौंपी, क्या मुख्यमंत्री उन पर कार्रवाई के लिए अक्षम है, जिस कलेक्टर के मातहत इतने भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन्हें पद पर रहने का क्या अधिकार है, क्या वह डीएम इन की निष्पक्ष जांच कर पाएंगे और जब मुख्यमंत्री को इनके भ्रष्टाचार की जानकारी है तो यह अधिकारी अभी तक बचे कैसे हैं। यह कैसी जीरो टॉलरेंस नीति है।

मुख्यमंत्री जहां शासन की योजनाओं की प्रगति के बारे में फीडबैक ले रहे हैं, वहीं माफिया और दबंगों पर नकेल कसने के लिए अफसरों को फ्री हैंड भी दे रहे हैं। डिंडोरी और खंडवा के कलेक्टर व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से वीसी के माध्यम से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रॉबिन हुड अंदाज में दिखे और अफसरों से कहा-करप्शन के मामले में **जीरो टॉलरेंस** रखें। मेरी तरफ से फ्री हैंड है, अपराधियों को न छोड़ें। मुख्यमंत्री ने दोनों जिलों के प्रभारी मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी ली और कई निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने खंडवा प्रशासन से नवाचार, कुपोषण से मुक्ति के प्रयासों, एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी, पेयजल, प्रधानमंत्री आवास, खंडवा शहर में पेयजल स्थिति, राशन वितरण, बिजली बिल माफी शिविर, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों, रोजगार मेला, अमृत सरोवर, मनरेगा के काम, अपराध नियंत्रण, अवैध उत्खनन, माफियाओं के खिलाफ अभियान, अतिक्रमण से मुक्ति अभियान, लाड़ली लक्ष्मी योजना, कैरियर काउंसलिंग, छात्रवृत्ति की स्थिति, केंद्र और राज्य की फ्लैगशिप स्कीम सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

● **सुनील सिंह**

खाई को पाटने की कोशिश

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वाकई जादुई व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। वे एक ऐसे राजनेता हैं जो पत्थर को छूकर पारस बना देते हैं। अपने इसी हुनर के सहारे उन्होंने ग्वालियर में सामाजिक समरसता के नए युग का प्रारंभ किया। मुख्यमंत्री ने 2 अप्रैल 2018 को हुई हिंसा के मामले में अहम बैठकें ली। मुख्यमंत्री ने दो अलग-अलग स्थानों पर आयोजित बैठकों में अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि आज सामाजिक समरसता के नए युग का प्रारंभ हो रहा है। इसलिए मिशन-2023 से पहले बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेला है। साल 2018 हिंसा की वजह से भाजपा सत्ता से बेदखल हुई थी। अब मुख्यमंत्री शिवराज ने उस खाई को खत्म करने की कोशिश की। 2 अप्रैल 2018 में हुए जातिगत उपद्रव के मुद्दे पर चर्चा की गई। एससी-एसटी वर्ग के लोगों से भाजपा की जो दूरियां बढ़ गई थी। उनको दूर किया गया। भाजपा में आने के बाद से सिंधिया इसे खत्म करने लग गए थे। इसलिए मौका देखते ही मुख्यमंत्री शिवराज और केंद्रीय मंत्री को बुलाकर दोनों समाज के बीच सुलह कराई गई। जिससे इनका वोट बैंक फिर से तैयार हो जाए। क्योंकि इसी चलते भाजपा सत्ता का सुख भोगने से वंचित रह गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मेरे मन में एक संतोष है कि हमारा समाज टूटेगा नहीं, हम मिलकर साथ चलेंगे और इस दिशा में सरकार पूरी गंभीरता से कदम उठाएगी। 2 अप्रैल 2018 को एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ आंदोलन हुआ था।

प्रदेश में सरकार की तमाम कोशिश के बाद भी कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। इसके पीछे की वजह प्रदेश में पुलिस बल की कमी को बताया जा रहा है। वाकई प्रदेश में पुलिस बल की कमी है। बावजूद इसके प्रदेश में 4076 सिपाही साहबों के बंगले पर चाकरी कर रहे हैं। चाकरी कर रहे ये पुलिसकर्मी अब मुखर हो गए हैं और गृहमंत्री तक शिकायत कर चुके हैं कि उन्हें जीडी में लगाया जाए।

मप्र में 4076 सिपाही कर रहे बंगला ड्यूटी

मप्र में आईपीएस अफसरों की लंबी फौज सिपाहियों के हक पर डाका डाले बैठी है। वो ट्रेंड आरक्षकों को मैदानी ड्यूटी पर न भेजकर अपने सरकारी बंगले पर चाकरी करवा रही है। आरक्षकों से झाड़ू पोंछा और घर के लिए सब्जी-भाजी तक खरिदवायी जा रही है। ऐसे एक या दो नहीं बल्कि चार हजार से ज्यादा आरक्षक हैं जो अफसरों के बंगलों पर मेम साहब की ड्यूटी बजा रहे हैं।

मप्र में आईपीएस अफसर आरक्षकों को मैदानी ड्यूटी पर नहीं जाने दे रहे हैं। वजह ये है कि उन सिपाहियों से अपने बंगले पर ड्यूटी करवा रहे हैं। एएसआई रैंक के कर्मचारी ये सिपाही साहब के बंगले पर कपड़ा-बर्तन धोने से लेकर झाड़ू-पोंछा तक कर रहे हैं। ऐसे 4076 सिपाही हैं जिन्हें बंगला ड्यूटी पर लगा रखा है। इन्हें पीएचक्यू में मर्ज किया जाना है। लेकिन फाइल 2 महीने से अटकी पड़ी है। आईपीएस लॉबी ऐसा होने ही नहीं दे रही क्योंकि फिर आरक्षक उनके हाथ से निकल जाएंगे। उन्हें बंगला ड्यूटी से हटाकर पीएचक्यू भेजना पड़ेगा।

मप्र के ये चार हजार से ज्यादा ट्रेड आरक्षक प्रदेश के गृहमंत्री, डीजीपी, एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसपी, एएसपी, सीएसपी से लेकर आरआई तक के बंगले पर झाड़ू-पोंछा, बर्तन, कपड़े, माली, गाय सेवक, गेट कर्मी, कुक, स्वीपर, ड्राइवर, साफ-सफाई करने समेत दूसरे दीगर काम कर रहे हैं। इन आरक्षकों को 5 साल की सेवा के बाद आरक्षक जीडी के पद पर संविलियन से किया जाना था। संबंधित प्रक्रिया जीओपी 57/53 को साल 2013 में तत्काल डीजीपी नंदन दुबे ने बंद कर दिया था, जबकि ट्रेड आरक्षक प्रमोशन पाकर असिस्टेंट सब इंस्पेकर बन गए हैं। लेकिन संविलियन नहीं होने के कारण आज भी वे झाड़ू-पोछे का काम आईपीएस अफसरों के बंगले पर कर रहे हैं। तत्कालीन डीजीपी विवेक जौहरी ने ट्रेड आरक्षक के संविलियन के संबंध में एक कमेटी का गठन किया था, लेकिन यह सब खानापूर्ति ही साबित हुआ।

पुलिस फोर्स की कमी होगी दूर

इस संविलियन की प्रक्रिया से पुलिस विभाग को कोई नुकसान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मैदानी स्तर में फायदा होगा। लेकिन आईपीएस लॉबी ऐसा नहीं चाहती है। ट्रेंड आरक्षकों का कहना है कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में ट्रेड आरक्षक संविलियन की प्रक्रिया चालू है। मप्र में 9 साल से ये प्रक्रिया बंद है। आरक्षक को जीडी आरक्षक के तहत ही वेतन मिलता है। इस संविलियन से शासन पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं आएगा। साथ ही मैदानी पुलिस बल की कमी भी दूर होगी। नई भर्ती के तहत पुलिस आरक्षक 2 साल के बाद पुलिस विभाग को मिलते हैं लेकिन ट्रेड आरक्षक के संविलियन के तत्काल बाद पुलिस फोर्स में 4076 का इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा प्रधान आरक्षक और एसआई स्तर के खाली पदों को भी भरा जा सकता है। दूसरी तरफ होमगार्ड कर्मचारियों को 3 साल के बाद 15 प्रतिशत के हिसाब से आरक्षक जीडी बनाया जाता है।

मप्र में ट्रेड आरक्षकों की संख्या 4076 है। इनमें 150 एएसआई, 300 हेड कांस्टेबल और 3350 कांस्टेबल हैं। एडीजी, आईजी, डीआईजी को 8 ट्रेंड आरक्षक रखने की पात्रता है। एसपी 4 ट्रेंड आरक्षक रख सकता है। एएसपी को 1 ट्रेंड आरक्षक रखने की पात्रता है। वर्तमान में एक आईपीएस अफसर के बंगले पर 25 से 35 तक ट्रेंड आरक्षक चाकरी कर रहे हैं। आरआई को पात्रता नहीं, फिर भी ट्रेड आरक्षक को सरकारी घर पर तैनात किया गया है।

ट्रेंड आरक्षकों की मांग पर 24 मार्च को गृहमंत्री के कार्यालय से एक पत्र जारी कर राजेश राजौरा एसीएस गृह विभाग को भेजा गया है। गृह विभाग ने 28 मार्च को एक पत्र संविलियन के संबंध में पुलिस मुख्यालय को भेजा। इस पत्र का 2 महीने के बाद भी मुख्यालय ने जवाब नहीं दिया। मुख्यालय में बैठे डीजीपी सुधीर सक्सेना ने पत्र को मंजूरी नहीं दी। यदि वो पत्र पास कर देते हैं तो संविलियन की प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी।

पुलिस मुख्यालय ने जीओपी क्रमांक 57/93 23 अक्टूबर 1993 जारी कर विभाग में तैनात आरक्षक ट्रेंडमैन श्रेणी दो में 5 साल की सर्विस करने के बाद आरक्षक का जीडी में मर्ज करने का प्रावधान था। इसे पुलिस मुख्यालय के आदेश पर साल 2013 में बंद कर दिया गया। विधानसभा में विधायक सत्यपाल सिकरवार के सवाल पर 2017 में तत्कालीन गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने जीओपी फिर से शुरू करने आश्वासन दिया था। इसके बावजूद आज तक कुछ नहीं हो पाया।

● **राकेश ग्रोवर**

कागजों में नदियां पूरी तरह निर्मल

नदियों के पानी की जांच के बदले मापदंडों के चलते लगभग सभी नदियों का पानी मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी रिपोर्ट में स्वच्छ हो गया है। इसके चलते पानी सालभर से ए और बी श्रेणी का बना हुआ है जबकि हकीकत में नदियों के पानी में सीवेज आदि मिलने के कारण खूब गंदगी घुली हुई है। इससे कई जगह बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी भी अधिक है। फीकल कॉलीफॉर्म और टोटल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया भी नदियों के पानी में काफी मात्रा में हैं जो नुकसानदेह हो सकते हैं। प्रदूषण नियंत्रण के केवल मापदंड ही नहीं बदले बल्कि सैंपल लेने के तरीके में भी बदलाव के चलते नदियां स्वच्छ हो गई हैं।

नदियों में बढ़ते प्रदूषण की स्थिति और एनजीटी में उसकी रिपोर्ट देने की बाध्यता के चलते सीपीसीबी ने मापदंडों में बदलाव किया है। इसके तहत फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया को प्रति 100 एमएल पानी में 2500 एमपीएन तक मान्य किया गया है। वहीं, टोटल कॉलीफॉर्म 5000 तक मान्य हैं जबकि पहले के मापदंडों में यह 50 तक ही मान्य किए जाते थे। अब इतनी बड़ी संख्या में मान्य होने के चलते नदियों का पानी असुरक्षित की श्रेणी से बाहर हो गया है। एमपीपीसीबी की मार्च की वाटर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट में केवल खान, चंबल, शिवना और क्षिप्रा नदी का पानी ही संतोषजनक श्रेणी का नहीं पाया गया। अन्य सभी नदियों का पानी संतोषजनक है, जबकि अभी नर्मदा नदी में ही बड़ी मात्रा में एल्गी तैर रही है। जो प्रदूषण के कारण ही बढ़ती है। एमपीपीसीबी के सदस्य सचिव एए मिश्रा ने इस संबंध में ज्यादा बात नहीं की उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मापदंड सीपीसीबी ने तय किए हैं।

पहले नदी के पानी की सैंपलिंग किनारे से होती थी क्योंकि किनारे के पानी का ही घाटों पर अधिकांश लोग उपयोग करते हैं। वे न केवल इसमें स्नान करते हैं बल्कि आचमन के लिए भी नदी के पानी का उपयोग करते हैं। लेकिन अब पीसीबी का अमला नदी के बीच में से सैंपल ले रहा है। चूंकि नदी के बीच में प्रवाह तेज रहता है इसलिए किसी तरह की गंदगी यहां टिक ही नहीं पाती, इसलिए असलियत सामने नहीं आ पाती।

प्रदेश की कई जीवनदायिनी नदियों में निर्मल जल की धारा की बजाय प्रदूषण का जहर बह रहा है। नदियों का पानी प्रदूषण के खतरे की सीमाएं पार कर चुका है। समाधान के नाम कागजी योजनाओं पर पैसा जरूर बहा रहे हैं। इधर समस्या गहराती जा रही है।

प्रदेश की पवित्र क्षिप्रा नदी को स्वच्छ और प्रवाहमान बनाने के लिए बीते 20 साल में करीब 650 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। लेकिन क्षिप्रा आज भी मैली है। प्रदूषण विभाग की स्टडी के अनुसार क्षिप्रा नदी का पानी अब आमचन तो दूर नहाने लायक भी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक क्षिप्रा नदी का पानी डी ग्रेड का है। जनप्रतिनिधि इसका कारण इंदौर से आने वाले प्रदूषित पानी की रोकथाम के लिए सही उपाय नहीं होना बता कर पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि खान डायवर्सन योजना अब तक जल संसाधन विभाग को हैंडओवर ही नहीं हुई है, इसलिए इसके मेंटेनेंस का बजट में प्रावधान नहीं किया जाता। क्षिप्रा की स्वच्छता और प्रवाहमान बनाने की मांग को लेकर क्षिप्रा तट दत्त अखाड़ा घाट पर धरना दे रहे संतों को फिर प्रशासन आश्वासन थमाकर इस मुद्दे को ठंडा करने में जुटा है।

क्षिप्रा को इंदौर के गंदे पानी से बचाने के लिए सबसे पहले राघौ पिपलिया पर स्टापडैम बनाया गया था। क्षिप्रा को स्वच्छ रखने के लिए 2004 में 6 करोड़ की नदी संरक्षण योजना के तहत शहर के सभी बड़े नालों को पाइप लाइन और पंपिंग स्टेशनों से जोड़कर गंदे पानी को सदावल ट्रीटमेंट प्लांट पर छोड़ा गया। यह योजना पंपिंग आधारित होने से नगर निगम पर सालाना 1 करोड़ रुपए बिजली खर्च आने से बार-बार पंपिंग बंद होने के कारण गंदा पानी क्षिप्रा में मिलता रहा। इस बीच 4 करोड़ रुपए से हरसिद्धि से सीवरेज लाइन डाली गई जो **रुद्रसागर में एकत्र** गंदे पानी को रामघाट पर मिलने से रोककर नदी में आगे लेकर छोड़ती है। सिंहस्थ 2016 में खान डायवर्सन योजना लागू की गई। इस पर करीब 80 करोड़ रुपए खर्च हुए लेकिन राघौ पिपलिया स्टापडैम से गंदा पानी ओवरफ्लो होकर क्षिप्रा में मिल रहा है। क्षिप्रा को प्रवाहमान बनाने के लिए करीब 500 करोड़ से ज्यादा की नर्मदा क्षिप्रा लिंक और उज्जैनी टू उज्जैन योजना लागू की गई है। इनसे समय-समय पर नर्मदा का पानी मिलता है।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

कागजों में स्वच्छ लेकिन आसपास के जलस्त्रोत तो दूषित होंगे ही

पर्यावरणविद् डॉ. सुभाष सी पांडे के अनुसार नदियों का पानी मापदंड बदलकर भले ही स्वच्छ दिखा दिया जाए लेकिन इसके दुष्प्रभाव तो देखने को मिलते ही हैं। चूंकि इसके आसपास जो कुएं और बोरवेल होंगे उनके पानी पर भी नदी का प्रभाव पड़ता है। यदि नदी का पानी प्रदूषित होगा तो उनका पानी भी दूषित होने की पूरी संभावना रहती है। उन्होंने कलियासोत नदी के आसपास के भूजल स्रोतों के पानी की जांच की थी, इसके आसपास के डेढ़ किलोमीटर के दायरे में पानी पीने योग्य नहीं पाया गया। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। मापदंडों की एक खास बात यह भी है कि इसमें पानी में कितने हैवी मेटल मौजूद हैं इसकी जांच ही नहीं की जा रही है जबकि नदियों में औद्योगिक अपशिष्ट मिलने के बाद उसके पानी में हैवी मेटल्स की मात्रा भी काफी बढ़ जाती है। बेतवा नदी में औद्योगिक क्षेत्रों के पास के पानी में पहले भी हैवी मेटल मिले थे लेकिन अब जांच नहीं की जा रही।

भारत के शहर सबसे प्रदूषित

भारत की राजधानी दिल्ली में कितना प्रदूषण है, इसको लेकर डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट जारी की है। यूएन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने दुनिया भर के शहरों की एयर क्वालिटी रैंकिंग जारी की है। इस रिपोर्ट में दिल्ली को दुनिया की कैपिटल सिटी के रूप में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बताया गया है। इस रिपोर्ट में सबसे खराब गुणवत्ता वाले 50 शहरों में से 35 शहर भारत के हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ के मानकों पर भारत का एक भी शहर खरा नहीं उतरा है। एयर क्वालिटी रैंकिंग में भारत की राजधानी दिल्ली (85.5) को सबसे प्रदूषित शहर के रूप में रखा गया है। इसके बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका (78.1) और तीसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप के चाड देश की राजधानी अन जामेना (77.6) को रखा गया है। 2021 की वैश्विक एयर क्वालिटी रिपोर्ट में 117 देशों के 6475 शहरों का डेटा शामिल किया गया। इस रिपोर्ट में 20 से 35 फीसदी शहरी पीएम 2.5 पॉल्यूशन को व्हीकल प्रदूषण के रूप में रिकॉर्ड किया गया है।

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि नई दिल्ली में 2021 में पीएम 2.5 सांद्रता में 14.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पीएम 2.5, 2020 में 84 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से बढ़कर 96.4 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हो गया है। वहीं, रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का वार्षिक पीएम 2.5 औसत 2019 में मापी गई सांद्रता पर वापस आ गया है। ग्रीनपीस इंडिया के कैंपेन मैनेजर अविनाश चंचल ने आईक्यूएयर के हालिया आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह रिपोर्ट सरकारों और नगर निगमों के लिए एक चेतावनी है। उन्होंने कहा कि यह एक बार फिर उजागर कर रहा है कि लोग खतरनाक रूप से प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। भारत में वाहनों की वार्षिक बिक्री बढ़ने की उम्मीद के साथ ही वायु गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। इसके लिए अगर समय पर सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए तो स्थिति और भी जटिल हो सकती है।

हाल ही में जारी एक नई रिपोर्ट 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के हवाले से पता चला है कि 2021 के दौरान देश के 48 फीसदी शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा निर्धारित मानकों से करीब 10 फीसदी ज्यादा था। गौरतलब है कि 2021 के दौरान देश में पीएम 2.5 का वार्षिक औसत स्तर 58.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया था। जिसकी वजह से वायु गुणवत्ता में पिछले तीन वर्षों से दर्ज किए गए सुधार का भी अंत हो गया था और पीएम 2.5 का वार्षिक औसत दोबारा 2019 के स्तर पर पहुंच गया था।

संगठन आईक्यू एयर द्वारा जारी यह रिपोर्ट 117 देशों के 6,475 शहरों से लिए पीएम 2.5 के वायु गुणवत्ता संबंधी आंकड़ों पर आधारित है। देखा जाए तो 2021 में देश का ऐसा कोई भी शहर नहीं था, जो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन को पूरा करता हो। गौरतलब है कि वायु प्रदूषण के बढ़ते असर को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2021 में पीएम 2.5 के वार्षिक मानक को 10 से घटाकर 5 माइक्रोग्राम प्रति वर्ग मीटर कर दिया था, जिससे प्रदूषण के बढ़ते असर को सीमित किया जा सके। रुझान को देखें तो मध्य और दक्षिण एशिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में से 11 भारत में ही हैं, जिनमें दिल्ली भी एक है। देखा जाए तो 2021 में दिल्ली के पीएम 2.5 के स्तर में पिछले वर्ष की तुलना में 14.6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। गौरतलब है कि 2020 के दौरान दिल्ली में पीएम 2.5 का वार्षिक औसत स्तर 84 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया था, जो 2021 में बढ़कर 96.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर पहुंच गया था।

हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) द्वारा सर्दियों के दौरान (15 अक्टूबर 2021 से 15 फरवरी 2022) देश के अलग-अलग हिस्सों की वायु गुणवत्ता का विश्लेषण किया गया था। जिसके अनुसार सर्दियों में देश के सभी हिस्सों में वायु प्रदूषण के कणों में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई थी। हालांकि इस बात से संतोष किया जा सकता है कि अधिकांश क्षेत्रों में पीएम 2.5 का कुल क्षेत्रीय औसत पिछली सर्दियों की तुलना में कम था, लेकिन कई क्षेत्रों में सर्दियों में होने वाले धुंध के चरणों में गंभीर वृद्धि दर्ज की गई थी। खासकर उत्तरी और पूर्वी मैदानी इलाकों में क्षेत्रों के बीच बड़ी दूरी होने के बावजूद प्रदूषण का चरम खतरनाक रूप से ज्यादा था।

● **कुमार विनोद**

सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया का कोई भी देश मानकों पर नहीं है खरा

रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया का कोई भी देश 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा निर्धारित मानकों पर खरा नहीं था। देखा जाए तो वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े पर्यावरण संबंधी खतरों में से एक है जो हर साल करीब 70 लाख लोगों की जान ले रहा है। इतना ही नहीं यदि 2019 के आंकड़ों को देखें तो दुनिया की 90 फीसदी से ज्यादा आबादी ऐसी हवा में सांस लेने को मजबूर है जो धीरे-धीरे उसकी जान ले रही है। इतना ही नहीं वातावरण में बढ़ता प्रदूषण अस्थमा, कैंसर और मानसिक रोगों जैसी बीमारियों की जड़ है। जिसका बोझ दुनिया के लाखों लोगों को ढोना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 222 शहरों ने डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित मानकों को हासिल किया था जबकि दूसरी तरफ 93 शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर तय मानकों से करीब 10 गुना ज्यादा था। वहीं यदि इससे होने वाले आर्थिक नुकसान को देखें तो रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण हर रोज 60,938 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा रहा है, जो कि विश्व के सकल उत्पाद के करीब 4 फीसदी के बराबर है। रिपोर्ट का मानना है कि वायु प्रदूषण समाज के कमजोर तबके को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। अनुमान है कि 2021 में 5 वर्ष से कम उम्र के 40,000 बच्चों की मौत के लिए सीधे तौर पर पीएम 2.5 जिम्मेवार था। इतना ही नहीं शोध में यह भी सामने आया है कि पीएम 2.5 के संपर्क में आने से कोविड-19 संक्रमण का खतरा कहीं ज्यादा बढ़ जाता है जिससे मृत्यु भी हो सकती है।

सहरिया पर महंगाई की मार

रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के चलते इस साल के शुरुआती महीनों में भारत समेत पूरी दुनिया में खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ी हैं। विडंबना यह है कि आपसी लड़ाई में शामिल ये दोनों देश दुनिया के एक बड़े हिस्से को गेहूं, मक्का और सूरजमुखी की आपूर्ति करते हैं। 17 मई, 2022 को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत की थोक मुद्रास्फीति अप्रैल में बढ़कर 15.08 फीसदी हो गई, जो मार्च में 14.55 फीसदी थी। देश में ईंधन और खाद्य-पदार्थों के दाम बढ़ने से खुदरा महंगाई की दर भी पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ने का सबसे ज्यादा असर देश के सबसे कमजारे तबके पर पड़ रहा है। इसकी झलक पूर्वी राजस्थान की सीमा से लगे मप्र के शिवपुरी जिले के 6 गांवों में तब देखने को मिली। इन सारे गांवों में सहरिया आदिवासी लोग रहते हैं, जिन्हें सरकार ने 'खासतौर से संवदेनशील आदिवासी समुदाय' के तौर पर वर्गीकृत कर रखा है। इस समुदाय के लोग शिवपुरी समेत मप्र के करीब 8 जिलों में रहते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक इनकी आबादी 6,14,958 है।

सहरिया आदिवासी लंबे समय से भयंकर गरीबी और कुपोषण का सामना कर रहे हैं। अब खाद्य-पदार्थों के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के चलते दालों और सब्जियों जैसी बुनियादी चीजें उनकी पहुंच से बाहर हो रही हैं। वे महीने के ज्यादातर दिनों में इनके बगैर गुजारा कर रहे हैं। जिसके चलते उनके अस्तित्व पर खतरा और बढ़ गया है। उदाहरण के लिए अशरपी आदिवासी को लें। मोहरा गांव की अशरपी ने 11 मई को दिन की पहली खुराक ली थी। उन्होंने आम के अचार के साथ दो रोटियां खाई थीं। अचार के लिए कच्चे आम उनका बच्चा पास के जंगल से लाया था। उनके पति शंकर कहते हैं- 'अचार का स्वाद अच्छा नहीं है लेकिन हम हर दिन सूखी रोटियां तो नहीं खा सकते। इसलिए उनके साथ जो मिलता है, वो खा लेते हैं।' अशरपी और उसके परिवार को रोटी के साथ सब्जी दो दिन पहले खाने को मिली थी, जब उन्होंने प्याज को भूनकर उसकी सब्जी बनाई थी। उसके पहले उन्होंने चने की दाल बनाई थी, जिसके लिए चने राजस्थान में रहने वाले उनके माता-पिता ने दिए थे। उस दिन उन्होंने रोटियों के साथ वह दाल खाई थी।

अशरपी कहती हैं,- 'उस दिन मैं अपने माता-पिता से मिलने गई थी तो मेरी भाभी ने जोर देकर कहा कि मैं अपने परिवार को खिलाने के लिए थोड़ी सी दाल ले जाऊं।' अशरपी को याद नहीं है कि पिछली बार कब उन्होंने पूरा खाना खाया था, जिसमें पोषण वाली सब्जी भी शामिल थी, केवल आलू-प्याज या दालें नहीं। उन्होंने बताया कि घर में खाने वाली कोई चीज नहीं है। दूसरे गांव, कोल्हापुर की रहने वाली राजधनी तीन महीने की गर्भवती थीं। गांव में किसी के यहां शादी होने के कारण उस दिन उन्हें कई दिनों के बाद दोनों वक्त का खाना मिला था।

हालांकि वह ठीक से तो याद नहीं कर पाईं, लेकिन करीब 20-25 दिन पहले उन्हें दोनों वक्त का खाना खाने को मिला था। उन्होंने कहा कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। राजधनी बताती हैं कि दो साल पहले जब उनका पहला बच्चा होने वाला था, तो उन्हें दोनों वक्त की खुराक मिल जाती थी। वे कहती हैं - 'मुझे भूख महसूस नहीं होती।' ये वे शब्द हैं, जो आप यहां किसी भी सहरिया को कहते सुनेंगे, खासकर महिलाओं को। यह शब्द, उस समुदाय को बार-बार याद दिलाते हैं कि उसने कठोर हकीकत को स्वीकार कर लिया है, कुपोषित होना जिसकी नियति बन चुकी है। इन गांवों के लोग सब्जी के नाम पर केवल आलू-प्याज बना सकते हैं, वह भी एक सप्ताह में केवल कुछ बार। दाल भी वे महीने में केवल 4-5 बार खा पाते हैं, उसमें भी खासकर चने की दाल।

राजधनी के गांव के ही रहने वाले 52 साल के सियाराम कहते हैं- 'पहले हम रोज तो नहीं, लेकिन सप्ताह में कुछ दिन लौकी, करेला और भिंडी पका लेते थे, लेकिन अब ये सब्जियां भी 60 रुपए किलो के करीब हैं। अब हम केवल आलू खरीदते हैं।' गांव के लोग जंगल से जंगली सब्जियां भी तोड़ते हैं लेकिन वे मानसून के बाद ही उगेंगी। 2017 में, मप्र सरकार ने खासतौर से आदिवासी समुदायों के लिए एक योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत एक परिवार को सब्जियों, दूध और फलों के लिए हर महीने एक हजार रुपए मिलते थे। हालांकि इन 6 गांवों में से हर किसी ने यही बताया कि उन्होंने 2-3 महीने पहले ही ये राशि लेना बंद कर दिया।

● **बृजेश साहू**

भूखे हैं कई पेट

धान, गेहूं, सरसों और आलू की बुआई व कटाई के समय सहरिया समुदाय के लोग मप्र के अलग-अलग हिस्सों, राजस्थान और उप्र में खेतिहर मजूदर के रूप में काम करने के लिए जाते हैं। बाकी बचे 6-7 महीनों के दौरान, वे अपनी कमाई से जीने की कोशिश करते हैं या फिर अपने गांवों में काम खोजने की कोशिश करते हैं। मई के महीने के दौरान उनमें से कई लोग कई तेंदूपत्ते तोड़ते हैं। हालांकि बाकी बचे तमाम लोगों के आजीविका के स्रोत सीमित हैं। सियाराम के परिवार में 12 लोग हैं, जिनमें 5 साल से कम उम्र के तीन छोटे बच्चे शामिल हैं। इन सभी को महीने में कम से कम 10-12 दिनों के लिए गेहूं की सूखी रोटियों से ही काम चलाना पड़ता है। आदिवासियों के घरों में आजकल राशन के नाम पर केवल गेहूं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत हर परिवार को महीने में 35 किलो राशन मिलता है, जिसमें 25 किलो गेहूं और दस किलो चावल होते हैं। आठ लोगों का परिवार चलाने वाले शंकर ने कहा,-'हमारा गेहूं 10-12 दिनों में खत्म हो जाता है। खाने को चावल भी मिलता है, लेकिन उसे खाकर लगता ही नहीं कि कुछ खा भी रहे हैं। उसके साथ हम और क्या खाएं।' इनमें से ज्यादातर लोगों को सरकारी दुकान से चीनी, नमक और मिट्टी के तेल जैसी अन्य वस्तुएं नहीं मिलती हैं, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत उन्हें मिलनी चाहिए।

प्रदेश के नेशनल पार्क शिकारियों के निशाने पर

पुलिस बल भी नहीं मिल रहा

वन विभाग को पुलिस बल भी नहीं मिल रहा है। पुलिस मुख्यालय साफ कह चुका है कि पार्कों को देने के लिए पुलिसकर्मी नहीं हैं। ऐसे में वन विभाग ने वनरक्षक और वनपाल को फोर्स में रखने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है। तीन साल पहले एक प्रस्ताव बनाया गया था। उसके अनुसार तीनों पार्कों में एक-एक कंपनी तैनात की जानी है। प्रत्येक कंपनी में 112 सुरक्षाकर्मी होंगे। इसमें 18 से 25 साल के 24 वनरक्षक और 34 वनपाल रहेंगे। यह प्रस्ताव तीन साल से मंत्रालय में पड़ा है। उल्लेखनीय है कि फोर्स का गठन न होने पर वर्ष 2018 में आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इसके बाद 16 अक्टूबर 2019 को वन विभाग ने प्रस्ताव में संशोधन कर गृह विभाग को भेजा। प्रस्ताव करीब सवा साल गृह विभाग में पड़ा रहा। फिर वन सचिवालय को लौटा दिया। अब नोटशीट अलमारी में कैद है।

प्रदेश में बाघों के शिकार के मामले साल-दर-साल बढ़ रहे हैं। यह इस बात के संकेत हैं कि प्रदेश के नेशनल पार्क शिकारियों के निशाने पर हैं। प्रदेश के सबसे प्रमुख नेशनल पार्कों में से तीन कान्हा, पेंच और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शिकार की घटनाओं में इजाफा हुआ है। इस गंभीर संकट के बीच सरकारी व्यवस्था का यह आलम है कि बाघों की सुरक्षा के लिए एक दशक में भी स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन ही नहीं हो पाया। जबकि केंद्र सरकार ने वर्ष 2012 में कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच टाइगर रिजर्व में फोर्स गठित करने की सलाह दी थी। वह 100 प्रतिशत फंड देने को भी तैयार थी, लेकिन वर्चस्व खोने के डर से राज्य सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके लिए यह शर्त रखी गई थी कि तीनों टाइगर रिजर्व में क्षेत्र संचालक (फील्ड डायरेक्टर) केंद्र सरकार नियुक्त करेगी।

सरकारी अव्यवस्था और भर्राशाही का परिणाम है कि प्रदेश के नेशनल पार्कों में लगातार शिकार की घटनाएं हो रही हैं। यदि बाघों के शिकार के मामले को देखा जाए तो सर्वाधिक प्रभावित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। जहां पिछले दो साल में तीन बाघिन, तीन शावकों का शिकार हुआ है। इस अवधि में पेंच पार्क में 10 वन्य प्राणियों का शिकार हुआ, जिनमें से एक बाघ है। वहीं कान्हा नेशनल पार्क में 8 वन्यजीवों का शिकार किया गया। शिकार के मामलों में सबसे ज्यादा गिरफ्तारी पेंच पार्क में हुई, जहां 19 आरोपितों को पकड़ा गया। 124 बाघों के साथ मप्र को बाघ स्टेट का दर्जा लौटाने वाले बांधवगढ़ में दो साल के अंदर तीन बाघिन और तीन शावकों का शिकार हो गया। शहडोल संभाग के जंगलों में शिकारियों के फंदे में फंस कर 5 साल के अंदर 10 से ज्यादा बाघों की जान चली गई। अकेले उमरिया जिले में खेतों में फैलाए गए करंट की वजह से दो साल में सात से ज्यादा तेंदुए मारे गए। यहां छोटे वन्य प्राणियों में सूअर का शिकार भी होता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर डॉ. बीएस अन्नागिरी के अनुसार जंगल और जानवरों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा श्रमिक तैनात किए जाते हैं। इसके बावजूद जो घटनाएं होती हैं उसकी विधिवत जांच होती है।

प्रदेश के कान्हा और पेंच नेशनल पार्क में वन्यप्राणियों के लगातार शिकार हो रहे हैं। दो साल में कान्हा पार्क में हिंसक वन्यजीवों द्वारा चीतल-सांभर के शिकार को छोड़ दें, तो साल 2019 से मार्च 2021 तक शिकारियों ने छह सांभर, एक जंगली सूअर और एक सेही का शिकार किया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के डायरेक्टर एके सिंह का कहना है कि कान्हा के कोर एरिया में वन्यजीवों के शिकार की घटनाओं में पिछले दो सालों में कमी आई। शिकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लगातार विभाग का अमला और मुखबिर सूचना तंत्र सक्रिय रहते हैं। वहीं करंट लगाकर शिकार की घटनाएं पेंच राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में लगातार बढ़ती जा रही हैं। जंगल में फैलाए गए करंट में फंसकर भालू, चीतल सहित अन्य वन्यप्राणी अपनी जान गवां रहे हैं। पेंच प्रबंधन के मुताबिक एक जनवरी 2020 से अब तक सामने आए शिकार के 10 में से 7 मामलों में जंगल के आसपास करंट फैलाकर वारदात को अंजाम दिया गया है। हाल ही में पेंच प्रबंधन ने तीन मई को बाघ हड्डी व पेंगोलिन की खाल बरामद कर तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। हालांकि बाघ और पेंगोलिन का शिकार कब और कहां किया गया है, इसकी जांच की जा रही है। पेंच पार्क के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश सिंह कहते हैं कि सूचना तंत्र को मजबूत करने के साथ ही गश्ती पर जोर दिया जा रहा है।

वर्ष 2018 के बाघ आंकलन के अनुसार मप्र में देश के सबसे ज्यादा (526) बाघ हैं। मप्र में बाघों की सुरक्षा के दावे भी किए जाते हैं, पर असल स्थिति कुछ और ही है। प्रदेश में बाघों की मौत के आंकड़े साल-दर-साल बढ़ रहे हैं। पिछले साल 42 बाघों की मौत हुई थी और इस साल साढ़े चार माह में 18 बाघ मर चुके हैं। इस गंभीर संकट के बीच सरकारी व्यवस्था का यह आलम है कि बाघों की सुरक्षा के लिए एक दशक में भी स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन ही नहीं हो पाया। जबकि केंद्र सरकार ने वर्ष 2012 में कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच टाइगर रिजर्व में फोर्स गठित करने की सलाह दी थी। वह 100 प्रतिशत फंड देने को भी तैयार थी, लेकिन वर्चस्व खोने के डर से राज्य सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके लिए यह शर्त रखी गई थी कि तीनों टाइगर रिजर्व में क्षेत्र संचालक (फील्ड डायरेक्टर) केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। ऐसे में राज्य सरकार का दखल नहीं रहता। केंद्र सरकार की योजना के अनुसार इनमें सशस्त्र बल तैनात होना था। बाघों की संख्या को लेकर मप्र का मुकाबला कर्नाटक से है, वहां वर्ष 2012 में ही फोर्स का गठन किया जा चुका है। वहां बाघों की सुरक्षा सशस्त्र बलों के हाथ में है लेकिन मप्र में सुरक्षा डंडाधारी वनकर्मियों के भरोसे है। इस कारण शिकारी सक्रिय हैं। वर्ष 2021 में प्रदेश में 8 बाघों का शिकार हुआ था।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

केन-बेतवा लिंक परियोजना का सर्वे पूरा

केन-बेतवा लिंक परियोजना को अब जल्द ही रफ्तार मिलेगी। दिल्ली से आई 10 सदस्यीय टीम ने यहां बुंदेलखंड के 13 जिलों में तीन दिन सर्वे किया और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। रिपोर्ट तैयार कर अब केंद्र सरकार को दी जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक दो दशक से लंबित परियोजना पर अब जल्द कार्य शुरू हो सकेगा। बुंदेलखंड में सिंचाई और पेयजल समस्या को देखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2002 में केन-बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस परियोजना के जरिए बुंदेलखंड की दो बड़ी नदी केन एवं बेतवा को आपस में जोड़कर बारिश के पानी को बर्बाद होने से रोका जाएगा, ताकि बारिश के पानी का संग्रहण और सही उपयोग हो और प्यासा बुंदेलखंड हरियाली से भरा क्षेत्र बने। पहले शुरुआती दौर में यह परियोजना उप्र और मप्र में जमीन के विवाद में उलझी रही।

कई दौर की बैठक के बाद मामला निपटा तो पिछले वर्ष फरवरी में केंद्र सरकार ने परियोजना के लिए 44 हजार 605 करोड़ रुपए बजट में मंजूर किए। इसके बाद परियोजना के अमलीजामा पहनाने की पूरी संभावना बन गई। अब इसे धरातल पर उतारने के उद्देश्य से तेजी से काम किया जा रहा है। बुंदेलखंड के 13 जिले इस परियोजना से जुड़े हैं। दिल्ली से राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण (केंद्रीय जल आयोग), केंद्रीय मृदा एवं पदार्थ अनुसंधान केंद्र व जिला लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सात सदस्यीय टीम ने दो दिन पूर्व बुंदेलखंड में सर्वे के लिए डेरा डाला। यहां 18, 19 व 20 मई को मप्र के 9 जिले पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन और उप्र के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर में टीमों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर सर्वेक्षण किया और रिपोर्ट तैयार की। बांदा जनपद में केन नदी में **दो बैराज** बनाए जाने हैं, इसके लिए मौके का जायजा लिया। साथ ही मप्र के दोधन बांध को भी देखा। इसके अलावा नहरों के रिमाडलिंग का भी काम होना है। टीम में आए अधिकारियों ने अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंताओं के साथ बैठक की और परियोजना को लेकर चर्चा की। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के डायरेक्टर जनरल एवं केंद्रीय बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण के सीईओ भोपाल सिंह ने प्रशासनिक कामकाज के बंटवारे की रूपरेखा निर्धारित की जा रही है। सर्वेक्षण रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी जाएगी। इसके बाद आगे कार्य के लिए निर्णय लिया जाएगा।

केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत ढोढन (पन्ना) में डैम बनाकर केन के पानी को रोका जाएगा। यहां से 220.624 किलोमीटर की नहर बनाकर केन का पानी बरुआसागर (झांसी) से निकली बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा। इसमें दो किलोमीटर लंबी सुरंग भी बनाई जाएगी। केन नदी का पानी बेतवा नदी में ट्रांसफर किया जाएगा। दोनों नदियों को जोड़ने के लिए 220.624 किलोमीटर लंबी केन-बेतवा लिंक नहर बनाई जाएगी।

बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा सहित 13 जिलों के 62 लाख लोगों को इस परियोजना से बेहतर पेयजल आपूर्ति होगी। दो लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। केन-बेतवा लिंक परियोजना की वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व का आधा क्षेत्र डूब जाएगा। ऐसे में पार्क के वन्य प्राणियों को दूसरे स्थान पर सुरक्षित बसाने के लिए कोर एरिया को विस्तार देने की योजना है। इसके लिए पार्क से सटे 21 गांवों के लोगों को विस्थापित किया जाएगा। इनमें पन्ना जिले के 7 और छतरपुर के 14 गांव हैं। राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। इसी के साथ छतरपुर एवं पन्ना कलेक्टर ने संबंधित गांवों में संपत्ति का सर्वे शुरू करा दिया है। अगले 6 से 8 महीने में सर्वे का काम पूरा होने की संभावना है। उधर, दोनों नदियों पर बनने वाले ढोढन बांध को लेकर तमाम तरह के निर्णय लेने का अधिकार रखने वाली केन-बेतवा लिंक परियोजना अथारिटी का कार्यालय इसी हफ्ते भोपाल में खुल जाएगा। विश्वेश्वरैया भवन में अथारिटी को जगह दी गई है। इसके बाद छतरपुर जिले में भी कार्यालय खोला जाएगा।

परियोजना का काम एक कदम आगे बढ़ा है। राजस्व और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बैठकें शुरू हो गई हैं। बांध में अब सबसे बड़ी अड़चन पार्क है। जहां से पहले वन्यप्राणियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना है। इसकी कार्यवाही तेज हो गई है। छतरपुर कलेक्टर ने राजस्व **अमले को सर्वे** में लगा दिया है। इसमें गांव के प्रत्येक रहवासी की कृषि भूमि, आवासीय भूमि सहित अचल संपत्ति का आंकलन किया जा रहा है। इस काम के पूरा होने के बाद लेंड ट्रांसफर (राजस्व से वनभूमि में परिवर्तित) की जाएगी। आगे की कार्रवाई उसके बाद ही शुरू होगी। इनमें से 10 गांव डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। इनमें छतरपुर जिले के ढोढन, खरियानी, भोरखुआं, पलकौहां, सुकवाहा, कुपी, नैगुवां, शाहपुरा, मैनारी, पाठापुर शामिल हैं। इनकी भूमि सरकार अधिग्रहीत करेगी। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना से मप्र और उप्र के बुंदेलखंड क्षेत्र को सिंचाई एवं पीने का पानी मिलेगा।

● **सिद्धार्थ पांडे**

कोर एरिया का होगा विस्तार

डूब क्षेत्र के बाहर रहने वाले 11 गांवों में पार्क के कोर एरिया का विस्तार किया जाएगा। पार्क की 6 हजार 17 हेक्टेयर भूमि डूब रही है। इसमें से 4141 हेक्टेयर भूमि कोर एरिया की है। इसकी भरपाई छतरपुर और पन्ना जिले के गांव कोनी, मरहा, पाठापुर, कटहरी-बिल्हारा, मझौली, कोनी, गहदरा, खमरी, कूड़न, नैगुवां, डुंगरिया, घुघरी, बसुधा, कदवारा का विस्थापन होगा। इन गांवों की 4396 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है।

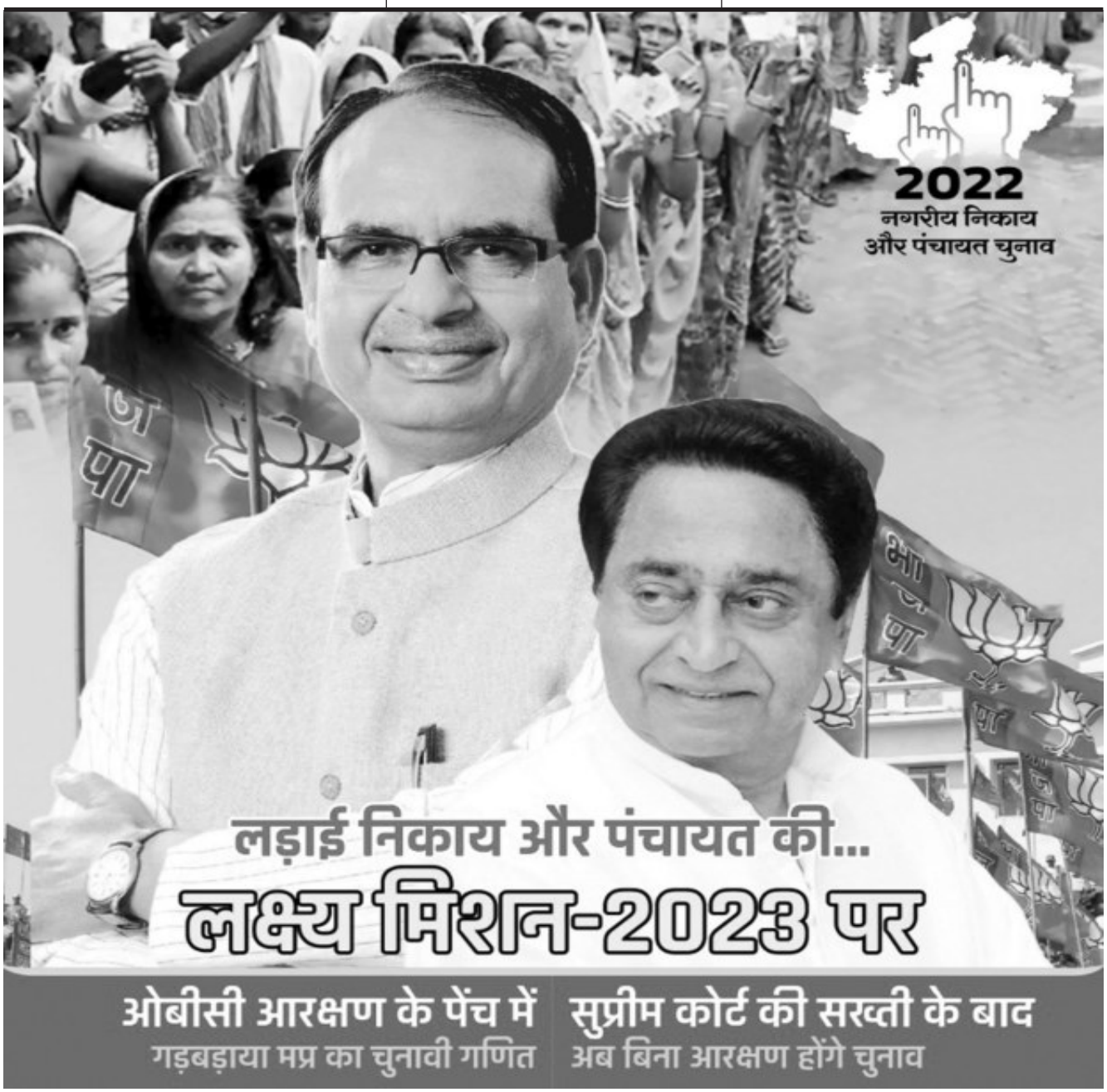

मप्र में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और नगरीय निकाय चुनाव की चौसर सजने लगी है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां निकाय और पंचायत चुनाव में अपनों को जिताकर मिशन-2023 की राह आसान करना चाहती है। इसके लिए भाजपा और कांग्रेस ने पूरी तरह कमर कस ली है। भाजपा अपने 17 साल के विकास, तो कांग्रेस 15 माह के शासन के आधार पर मिशन-2023 की तैयारी कर रहीं हैं। लेकिन दोनों की अग्निपरीक्षा पंचायत और निकाय चुनाव में होनी है।

● राजेंद्र आगाल

मप्र में 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। भाजपा की कोशिश है कि इस चुनाव में वह कांग्रेस को आधा सैकड़ा सीट भी न जीतने दे। वहीं कांग्रेस 2018 की तरह भाजपा को मात देकर सत्ता में वापसी करना चाहती है। इसके लिए पिछले एक साल से शह-मात का खेल जारी है। दोनों पार्टियां मिशन-2023 के लिए खूब मेहनत कर रही हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव होने में अभी 15 माह का समय बाकी है। ऐसे में दोनों पार्टियों की चुनावी तैयारी का आंकलन प्रदेश में होने वाले पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में हो जाएगा। सत्ता का **सेमीफाइनल** कहे जाने वाले इन चुनावों में जनता यह संकेत दे देगी कि 2023 में वह किसके साथ जाएगी। इसके लिए दोनों पार्टियों ने प्रदेश के सबसे बड़े वोटबैंक ओबीसी को साधने के लिए साम, दाम, दंड, भेद का भरपूर सहारा लिया है। अपनी रणनीतियों के सहारे दोनों पार्टियां चुनावी रण में एक-दूसरे को पटखनी देने के लिए कमर कस चुकी हैं।

तय होगी मिशन-2023 की रूपरेखा

प्रदेश में पंचायत चुनाव भले ही पार्टी आधारित नहीं होते हैं, लेकिन टिकट पार्टियां ही तय करती हैं। इसलिए प्रदेश में होने वाले पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। प्रदेश में 25 जून, 1 जुलाई और 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होंगे और 14 और 15 जुलाई को मतगणना होगी। इससे जो तस्वीर निकलकर सामने आएगी, वह मिशन-2023 की रूपरेखा तय करेगी। गौरतलब है कि मप्र में पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में आरक्षण मिल गया, लेकिन इससे आंकड़े नहीं बदलेंगे। लगभग तय है कि आरक्षण 14 प्रतिशत ही होगा। तो क्या आंकड़ों की तरह राजनीतिक समीकरण भी अप्रभावित होंगे? बिलकुल नहीं, बल्कि पूरे केंद्र में ही यही 14 प्रतिशत आरक्षण का खेल है। कांग्रेस के 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग के जवाब में जब भाजपा सरकार ने 35 प्रतिशत आरक्षण की मांग पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के **माध्यम से उठा दी थी,** तभी संकेत मिलने लगे थे कि हकीकत से अधिक तपिश दावों में होगी। अर्थात् दोनों दलों को संकेत मिल चुके थे कि यदि ओबीसी को आरक्षण मिला भी तो 50 प्रतिशत की बाध्यता में ये 14 प्रतिशत से अधिक होने वाला नहीं है। ऐसे में हकीकत से आगे बढ़कर दावों की नौबत आ गई। हालांकि कांग्रेस दावों के मामले में ही नहीं, बल्कि आरोप-प्रत्यारोप में भी पीछे छूटती दिखी। यदि कांग्रेस अब इसका विरोध करती है, तो पार्टी के लिए सियासी जोखिम से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। भाजपा पहले से इन चुनावों में ओबीसी को आरक्षण में बाधा और चुनाव में देरी का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ती रही है। इधर, कांग्रेस ने तथ्यों के आधार पर प्रतिक्रिया में खास दिलचस्पी नहीं दिखाई।

भाजपा की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में बेहतर मानी जाती रही है। ऐसे में प्रबल संभावना है कि पहले नगरीय निकायों के चुनाव कराए जाएं, इसके बाद पंचायतों के लिए चुनाव हों। इस स्थिति को लेकर कांग्रेस की तैयारियों की चुनौती बढ़ जाएगी। चूंकि नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव टलते-टलते विधानसभा चुनाव के करीब आ गए हैं, तो इसका प्रभाव मिशन-2023 को भी प्रभावित करेगा ही। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस चुनाव तो नगरीय निकायों का लड़ेंगी, लेकिन नजरें विधानसभा चुनाव पर होंगी।

ओबीसी आरक्षण घटा

परिसीमन के बाद भले ही त्रिस्तरीय पंचायत में सीटें बढ़ गई हैं, पर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटें कम हुई हैं। पिछले चुनाव में जिला पंचायत सदस्य की 841 सीटें थीं, जो इस बार बढ़कर 875 हो गई हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण घट गया। 2014-15 के चुनाव में ओबीसी के लिए 168 सीटें आरक्षित थीं, जो इस बार घटकर 98 रह गईं। इसी तरह सरपंच पद के आरक्षण में पिछड़ा वर्ग को नुकसान हुआ है। पंच पद की रिपोर्ट आनी बाकी है और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया 31 मई को भोपाल में संपन्न हुई। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की पिछड़ा वर्ग के प्रतिवेदन के आधार पर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कराई। 25 मई को देर रात तक आरक्षण की प्रक्रिया चली। जिला पंचायत सदस्य के लिए हुए आरक्षण में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 140, अनुसूचित जनजाति के लिए 231 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 98 आरक्षित की गई हैं।

406 सीट अनारक्षित हैं यानी किसी भी वर्ग का व्यक्ति इन पर चुनाव लड़ सकता है। 2014-15 के चुनाव में जिला पंचायत में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 136, अनुसूचित जनजाति के लिए 222, अन्य पिछड़ा वर्ग 168 और अनारक्षित सीटें 315 थीं। इसी तरह सरपंच पद के लिए अभी तक संचालनालय को 22 हजार 424 पंचायतों की जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें 3 हजार 302 अनुसूचित जाति, 7 हजार 837 अनुसूचित जनजाति, 2 हजार 821 अन्य पिछड़ा वर्ग और 8 हजार 562 अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित हुई है। हालांकि, कुछ जिलों से रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। वहीं, पिछले चुनाव को देखें तो कुल 22 हजार 607 सीटों में अनुसूचित जाति के लिए 3 हजार 248, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 7 हजार 812, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 हजार 76 और अनारक्षित 7 हजार 471 सरपंच के पद थे। इस प्रकार भले ही ओबीसी के लिए अधिकतम 35 प्रतिशत तक सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था लागू की गई हो, पर इसका फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। जनपद

आरक्षण से बिगड़ा गणित

भोपाल नगर निगम के वार्ड आरक्षण ने भाजपा-कांग्रेस के कई नेताओं के समीकरण और गणित दोनों बिगाड़ दिया है। अब वे अपने वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसलिए नई जमीन तलाश रहे हैं। मां-पत्नी या अपने रिश्तेदारों को भी मैदान में उतारने का प्लान बना रहे हैं। इनमें पूर्व निगम अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष जैसे बड़े नेता भी शामिल हैं। नगर निगम के 85 वार्डों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया 25 मई को हो चुकी है। इससे पूरी तस्वीर बदल गई है। खासकर ओबीसी के वार्डों के रिजर्वेशन ने नेताओं का समीकरण गड़बड़ा दिया है। वहीं, कई नेताओं के समीकरण बने भी हैं। यही कारण है कि रविंद्र भवन के ऑडिटोरियम में जब रिजर्वेशन हो रहा था, तब कोई खुशी से झूम रहा था तो किसी के चेहरे पर मायूसी देखने को मिली थी। कई दिग्गज नेता अब दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। हालांकि, यह किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि कम समय में वार्डवासियों के बीच पैठ जमाना और पार्टी की अंदरूनी कलह भी रहेगी। भाजपा के सुरजीत सिंह चौहान पिछले निगम परिषद में अध्यक्ष रह चुके हैं। वे वार्ड 51 से पार्षद हैं। यह वार्ड अब अनारक्षित महिला के हिस्से में चला गया है। ऐसे में चौहान के परिवार से कोई महिला चुनाव में उतर सकती हैं, या फिर उन्हें दूसरे वार्डों की ओर रूख करना पड़ेगा। वार्ड 31 से कांग्रेस पार्षद रहे अमित शर्मा अब 33 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ेंगे। वार्ड-31 ओबीसी (महिला) कैटेगिरी के हिस्से गया है। भाजपा से रविंद्र यति, शंकर मकोरिया, मनोज राठौर, महेश मकवाना, सरोज जैन, जगदीश यादव, रामबाबू पाटीदार, गणेशराम नागर, गिरीश शर्मा, तुलसा वर्मा, कृष्णमोहन सोनी, मनोज चौबे जैसे कई नेताओं के समीकरण भी गड़बड़ा गए हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष मोहम्मद सगीर, शहवार मंसूरी, रईसा मलिक, मोहम्मद सऊद, अब्दुल शफीक समेत कई कांग्रेसियों के वार्ड भी बदल गए हैं।

इंदौर में ओबीसी के वार्ड 21 से हुए 18

नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इंदौर नगर निगम के कुल 85 में से 34 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। जिस ओबीसी आरक्षण के चलते यह सब हुआ वहां ये हुआ कि ओबीसी के वार्ड पहले 21 थे, मगर आरक्षण के बाद 18 रह गए। इसी तरह महिलाओं के लिए 42 वार्ड आरक्षित हुए। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से चुनावों की हलचल तेज हुई थी। सुप्रीम कोर्ट व नगरीय प्रशासन विभाग के निर्देश पर इंदौर जिला प्रशासन ने देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की। शहर के कुल 85 वार्डों का आरक्षण हुआ। 13 वार्ड अनूसचित जाति और 3 वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए वर्ष 2020 में आरक्षित थे। लॉटरी के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18 वार्ड आरक्षित किए गए। अजा-अजजा वार्ड में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित हुए। इधर आरक्षण के कारण पिछली निगम में सभापति सहित सभी एमआईसी सदस्यों के वार्डों में आरक्षण की स्थिति बदल गई है। नगर निगम के साथ जिला पंचायत के 17 वार्डों, इंदौर, सांवेर, महू, देपालपुर जनपद अध्यक्ष और वार्डों का आरक्षण हुआ। कलेक्टर मनीष सिंह की उपस्थिति में यूनिवर्सिटी सभागृह में बैठे जनप्रतिनिधियों व पूर्व पार्षदों ने वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया के दौरान लॉटरी के माध्यम से पर्चियां निकाली। निगम चुनाव में महिला प्रतिभागियों के 50 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं। ऐसे में 85 वार्ड में से 42 वार्ड में महिलाएं लड़ेंगी। वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया के दौरान सभागृह में ज्यादातार सामान्य व पिछड़ा वर्ग के पूर्व पार्षद व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। आरक्षण प्रक्रिया को देखने के लिए कांग्रेस व भाजपा नेता भी पहुंचे थे। वार्ड आरक्षण लॉटरी की पर्चियां उठाने के लिए कई लोग एक साथ मंच पर पहुंचे तो कलेक्टर ने सबको आने से रोका और एक-एक करके नाम व पहचानकर लोगों को पर्चियां उठाने के लिए मंच पर बुलाया। इसमें कुछ जनप्रतिनिधि तो कुछ आम लोगों ने भी पर्चियां उठाई। लॉटरी शुरु होने से पहले एडवोकेट जयेश गुरनानी के कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए आरक्षण प्रक्रिया पर आपत्ति ली। इस पर अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर ने उन्हें अपनी आपत्ति मंच पर आकर देने को कहा।

ये है इंदौर के वार्डों का आरक्षण

कुल वार्ड: 85

- **पिछड़ा वर्ग महिला:** वार्ड क्रमांक 6, 43, 74, 12, 67, 23, 16, 19, 29।
- **पिछड़ा वर्ग पुरुष:** वार्ड क्रमांक 65, 13, 17, 72, 78, 32, 40, 9, 11।
- **अनुसूचित जाति मुक्त:** वार्ड क्रमांक 24, 26, 35, 36, 47, 54।
- **अजा महिला:** वार्ड क्रमांक 18, 30, 45, 46, 59, 61, 76।
- **अनुसूचित जनजाति मुक्त:** वार्ड क्रमांक 75
- **अजजा महिला:** 77, 79।
- **सामान्य (अनारक्षित):** वार्ड क्रमांक 80, 53, 41, 1, 66, 58, 31, 63, 83, 21, 14, 49, 85, 82, 81, 70, 68, 64, 57, 56, 51, 50, 35, 27, 22, 10, 5।
- **सामान्य (अनारक्षित) महिला:** वार्ड क्रमांक 71, 7, 60, 48, 15, 38, 62, 52, 55, 37, 8, 84, 25, 69, 3, 4, 39, 73, 44,28, 42, 34, 2, 20।

पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए अभी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 313 पदों में से 41 अनुसूचित जाति, 115 अनुसूचित जनजाति और 30 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 127 पद अनारक्षित हैं। एससी, एसटी, ओबीसी एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष लोकेंद्र गुर्जर का कहना है कि पिछले चुनाव में 56 जनपद पंचायत अध्यक्ष के पद आरक्षित थे। उधर, ओबीसी आरक्षण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारे पास कई शिकायतें आ रही हैं। अन्याय तो हुआ है, पर हम चाहते हैं कि अब पंचायत चुनाव हो। मेरी अपील है कि यदि थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो इसको अदालत के मामलों में न फंसाएं, जनता के बीच जाना चाहिए।

निकाय चुनाव 2023 का लिटमस टेस्ट

प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सूबे की नगर निगमों के महापौर को पार्षद नहीं बल्कि अब सीधे जनता चुनेगी। शिवराज सरकार बकायदा अध्यादेश लेकर आई है। मेयर का चुनाव सीधे जनता से कराने के फैसले के बाद निकाय चुनाव को 2023 के विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है, जहां पर कांग्रेस और भाजपा के लिए असल इम्तिहान होगा? प्रदेश में साल 2003 से मेयर का चुनाव जनता के द्वारा चुने जाने का नियम लागू था, लेकिन साल 2018 में कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो मेयर का चुनाव पार्षदों के माध्यम से कराने का फैसला ले लिया था। यही वजह थी कि शिवराज सरकार ने राज्य निकाय चुनाव की संभावनाएं बनते ही मेयर का चुनाव सीधे जनता से कराने के लिए सक्रिय कदम उठाया है। प्रदेश में कुल 16 नगर निगम हैं जबकि 100 नगर पालिकाएं और 264 नगर पंचायतें हैं। वहीं, ग्राम पंचायतों की संख्या 23 हजार से कुछ ज्यादा हैं। मप्र में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम, देवास, सिंगरोली, कटनी, सतना, छिंदवाड़ा और मुरैना में नगर निगम हैं। निकाय चुनाव 2019 में ही होने थे, लेकिन परिसीमन और फिर आरक्षण के चलते चुनाव टलते रहे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब चुनाव की संभावना बनी है, जिसके चलते सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं।

साल 2023 के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अब उससे पहले निकाय चुनाव में कांग्रेस और भाजपा की परीक्षा होनी है। ऐसे में नगर निगम के मेयर का चुनाव सीधे जनता के द्वारा होना है। कांग्रेस 2019 में सत्ता में होने के कारण अप्रत्यक्ष चुनावों के जरिए अधिकांश नगरीय निकायों को कब्जाने के लिए फायदों की आस में थी, लेकिन अब सत्ता में बैठी भाजपा ने जनता के पाले में गेंद डाल दी है। कांग्रेस-भाजपा को दोनों ही दलों को निकाय चुनाव में जीत का परचम फहराने के लिए

ग्वालियर की स्थिति

ग्वालियर में प्रस्तावित त्रि-स्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण और जनपद पंचायत अध्यक्षों एवं जिला पंचायत के वार्ड (जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन क्षेत्र) आरक्षण की कार्रवाई की गई। कलेक्ट्रेट ऑफिस में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की निगरानी में बॉक्स में पर्चियां डालकर वार्ड व पंचायतों का आरक्षण किया गया है। जिसके बाद शहर में काफी रोचक स्थिति बन गई है। जो वार्ड पहले सामान्य थे वह ओबीसी हो गए हैं। ओबीसी को पहले 17 वार्ड मिल रहे थे, लेकिन बदलाव के बाद 20 वार्ड मिले हैं वहीं यूआर (अनारक्षित वर्ग) को जहां पहले 37 वार्ड मिले थे उनको अब 34 ही वार्ड मिले हैं। शहर के 66 वार्ड में से 33 वार्ड सभी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं।

66 वार्ड की स्थिति

- **एससी के आरक्षित वार्ड-** 23, 28, 16, 22, 37, 61, 11, 60, 36, 39, 17
- **एसटी के लिए आरक्षित वार्ड-** 6
- **ओबीसी को मिले यह वार्ड-** 12, 35, 50, 59,02, 31, 48,63, 64,62, 38, 24, 56, 04, 09, 15, 10, 27, 65,21
- **यूआर के लिए यह रहे वार्ड-** 01, 03, 05, 07, 08, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 33, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 66

महिलाओं के लिए 33 वार्ड

ओबीसी, यूआर के आरक्षण में बदलाव हुआ है। इसके साथ ही महिलाओं को 66 वार्ड में से 33 वार्ड में प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा। अनारक्षित वर्ग को 34 वार्ड मिले हैं, इनमें से 17 वार्ड महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं। वहीं ओबीसी को 20 वार्ड मिले हैं उनमें से 10 महिलाओं के लिए हैं। एसटी में एक सीट है वह सामान्य है, जबकि एससी के लिए 11 वार्ड हैं और उनमें से 6 महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं।

बदल गए समीकरण

नगरीय निकाय चुनाव में भाग्य आजमाने के सपने देखने वाले कुछ लोगों को नए आरक्षण से झटका लगा है। जैसे एसटी में पहले 6 वार्ड फीमेल थे, लेकिन इस बार सामान्य हो गए। इसके साथ ही ओबीसी को 3 वार्ड ज्यादा मिलने से 3 वार्ड में सामान्य प्रत्याशी का समीकरण गड़बड़ा गया है। जनपद पंचायत मुरार का अध्यक्ष पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है। जनपद पंचायत घाटीगांव (बरई) के अध्यक्ष का पद अनारक्षित महिला, जनपद पंचायत डबरा के अध्यक्ष का पद अनारक्षित और जनपद पंचायत भितरवार के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हुआ है।

जनता के बीच अब जाना होगा। इस निकाय चुनाव के बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते दोनों ही दल किसी तरह का कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि निकाय चुनाव के नतीजों का असर विधानसभा चुनाव पर भी पड़ना लाजमी है। देखना है कि निकाय चुनाव में किसका दबदबा रहता है?

महापौर की दौड़ में माननीय भी कूदे

मप्र में होने वाले चुनावों को लेकर भाजपा सहित कांग्रेस भी बड़ी मुश्किल में फंस गई है। चुनावों को लेकर जहां एक ओर वैसे ही दोनों पार्टियों में तनाव बना हुआ था, वहीं अब खुद के विधायक ही इन दोनों पार्टियों के लिए बड़ी परेशानी का विषय बनते दिख रहे हैं। दरअसल प्रदेश में महापौर पद के लिए टिकटों की खींचतान बढ़ती जा रही है। सबसे अहम ये कि विधायकों का इस पद के लिए दबाव बढ़ रहा है। इसमें भाजपा संगठन फिलहाल विधायकों को प्रारंभिक तौर पर टिकट देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन 4 प्रमुख शहरों में से 3 शहरों में विधायकों की दावेदारी ज्यादा है। वहीं, कांग्रेस को विधायकों को टिकट देने में कोई ऐतराज नहीं है। हालांकि जयपुर चिंतन के तहत एक पद-एक व्यक्ति के फॉर्मूले से उलझन की स्थिति है। इसलिए इस मामले में भी आगे निर्णय पर पेंच है। दरअसल, विधायकी से ज्यादा महापौर पद को पसंद करने के पीछे सीधे चुनाव में महापौर पद का जलवा है। पूरे नगर निगम के बजट पर महापौर का अधिकार रहता है। उस पर सियासी तौर पर भी भोपाल-इंदौर जैसे शहरों का महापौर विधायकों से ज्यादा रूतबा व वजनदारी रखता है। सीधे तौर पर महापौर जिले-निगम का प्रथम नागरिक हो जाता है।

महापौर पद के लिए भाजपा में विधायकों की दावेदारी का सबसे ज्यादा जोर भोपाल-इंदौर में है। ग्वालियर में भी समीकरण विधायकों के जरिए प्रभावित हो रहे है। भोपाल से कृष्णा गौर, इंदौर से सुदर्शन गुप्ता और रमेश मेंदोला की दावेदारी है। खनिज निगम के पूर्व अध्यक्ष गोविंद मालू भी दावेदारी कर रहे हैं। ग्वालियर में विधायकों से ज्यादा पूर्व मंत्रियों की दावेदारी है। यहां से पूर्व मंत्री माया सिंह टिकट की दावेदारी में हैं। जबलपुर में भाजपा विधायक अजय विश्नोई की भी महापौर पद के लिए दावेदारी उभरी है, लेकिन सत्ता-संगठन दोनों उन पर सहमत नहीं है। महापौर पद के लिए कांग्रेस इंदौर से संजय शुक्ल का नाम घोषित कर चुकी है। यह नाम जयपुर चिंतन के पहले से घोषित है। अब चिंतन के बाद एक पद-एक व्यक्ति का फॉर्मूला है। इस कारण एक ही पद पर कोई नेता रह सकेगा। इस लिहाज से कांग्रेस अब जबलपुर या ग्वायिलर में इस फॉर्मूले को आजमाने में झिझक रही है। ग्वालियर में कमलनाथ संगठन के ही चेहरे को टिकट देने के पक्ष में हैं। दूसरी ओर, जबलपुर में विधायक के तौर पर तरुण भनोत और विनय सक्सेना का नाम भी महापौर पद के लिए पार्टी में उभरा है।

भाजपा संगठन 50 साल से ज्यादा उम्र और विधायक-सांसद पद वाले नेता को टिकट देने के पक्ष में नहीं है। हालांकि अभी इस पर निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर पार्टी में इस पर चर्चा हुई है। साथ ही पार्टी को यही सुझाव भी निकाय चुनाव कमेटी की बैठकों के दौरान मिले हैं। भाजपा के पास विकल्प भी बहुत है, इस कारण वह विधायक-सांसदों से हटकर नई पीढ़ी को टिकट देने के पक्ष में है। अगले हफ्ते टिकट के मापदंड तय हो जाएंगे। दूसरी ओर कांग्रेस ने सर्वे करके जीत के चेहरे के तौर पर टिकट देने

का फॉर्मूला रखा है। पार्टी जयपुर चिंतन के बाद जरूर विधायक-सांसदों को टिकट देने के पक्ष में नहीं है। इसका असर आगे के टिकट वितरण पर नजर आएगा। भाजपा में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टिकट वितरण में असरदार नजर आते हैं। संगठन के लिए सबसे बड़ी चुनौती केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे को साधना है। ग्वालियर-चंबल में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खेमे का संतुलन भी रखना होगा। वहीं, हर अंचल में क्षत्रपों को साधने की चुनौती है। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का खेमा असरदार है। कांग्रेस में इन दोनों के सामने क्षत्रपों को साधने की चुनौती नहीं है, पर गोविंद सिंह, अरुण यादव, अजय सिंह, जीतू पटवारी जैसे नेताओं की पसंद-नापसंद को तरजीह दी जा सकती है। फिलहाल पार्टी समन्वय और संतुलन की राह पर आगे बढ़ रही है।

जो जिताए उसी को टिकट

कांग्रेस ने निकाय चुनाव में प्रत्याशी चयन के मापदंड तय कर दिए हैं। इसमें दो ही कसौटी पर उम्मीदवार परखे जाएंगे। एक वह जो क्षेत्र में जीतने वाला लोकप्रिय चेहरा हो और दूसरा वह जो पार्टी का खांटी और कट्टर कार्यकर्ता हो। प्रदेश संगठन ने साफ कर दिया है कि इसके अलावा किसी मापदंड पर विचार नहीं होगा। टिकट चयन के लिए जिले से लेकर प्रदेश कांग्रेस तक जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं। यह भी कहा गया है कि 50 प्रतिशत महिलाओं के मामले में भी क्राइटेरिया का पालन हो। आरक्षण के हिसाब से महिला उम्मीदवारों के चयन में लगनशील, सक्रिय एवं उस क्षेत्र में लोकप्रिय चेहरों को टिकट दिया जाए। जिला कांग्रेस कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। पीसीसी में प्रदेशभर के 52 जिलों के 313 विकासखंड का कंट्रोल रूम होगा जहां से पीसीसी चीफ समेत उनकी टीम निगरानी करेगी। एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे प्रदेश की स्थिति पर नजर रखी जाएगी। कोशिश की जाएगी कि प्रत्याशियों के बीच आम सहमति बन जाए। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को जिताने की कोशिश की जाएगी। प्रत्याशी का चयन और अच्छे परिणाम की जिम्मेदारी जिला अध्यक्षों एवं स्थानीय नेताओं को सौंपी गई है।

पार्षद प्रत्याशियों का चयन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा। समिति अपने सदस्यों से गोपनीय सर्वे कराकर निर्णय लेंगी। समितियां सर्वानुमति से प्रत्याशियों का नाम तय कर सूची पीसीसी को भेजेंगी। प्रत्येक जिले के लिए एक वरिष्ठ नेता को प्रभारी मनोनीत किया जाएगा। 9 संभागीय प्रभारी भी बनाए गए हैं। नगर निगम, नगरपालिका और नगर परिषद में 27 प्रतिशत टिकट ओबीसी को दिए जाएंगे। नगर निगम में प्रत्याशी चयन समिति के अध्यक्ष शहर एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे। वहीं सांसद एवं लोकसभा प्रत्याशी 2019, जिले के विधायक, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष समिति के सदस्य होंगे।

उधर, भाजपा ने प्रत्याशी चयन के लिए पहले ही तैयारी कर ली है। अब पार्टी का पूरा फोकस पंचायत और निकाय चुनावों के माध्यम से मिशन-2023 पर है। वैसे तो भाजपा ने मार्च 2020 से ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा निरंतर सक्रिय हैं और सत्ता और संगठन को सक्रिय रखे हुए हैं। पार्टी ने लक्ष्य बनाकर पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का खाका तैयार किया है। पार्टी का पूरा फोकस 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतकर सत्ता में बने रहने पर है।

जबलपुर में आरक्षण की तस्वीर साफ

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जिले में आरक्षण की पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई। नगर निगम जबलपुर में ओबीसी की एक सीट आबादी की तुलना में अधिक रिजर्व हुई। अब वार्ड नंबर 51 रविंद्रनाथ टैगोर ओबीसी हो गई। शहर के सभी 79 वार्डों में 21 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित हो गई हैं। इसी के साथ जिला पंचायत के सभी 17 वार्डों, जनपद पंचायत अध्यक्षों के पदों की तस्वीर भी साफ हो चुकी है। नगर निगम जबलपुर में अभी ओबीसी आरक्षण 25 प्रतिशत के हिसाब से 20 सीट पर मिला था। जबकि आबादी के मुताबिक जिले में ओबीसी की संख्या 26.58 प्रतिशत है। इस कारण एक सीट बढ़ाई गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नमः शिवाय अरजरिया के मुताबिक निर्देशों के अनुसार एससी-एसटी के प्रकरण व महिला आरक्षण में कोई परिवर्तन नहीं होना था। जहां आबादी के अनुसार ओबीसी के पद घट या बढ़ रहे हैं, वहां आरक्षण होना था। जबलपुर में एससी के 11, एसटी के 4, ओबीसी के 20 और सामान्य महिला 22 व सामान्य 22 सीटों का आरक्षण किया गया था। एक सीट ओबीसी की बढ़ाई जानी थी, जो सामान्य से ली गई। सामान्य के 22 वार्डों में 9 वार्ड पिछली बार ओबीसी के लिए आरक्षित थी। इस कारण 13 वार्डों से ही एक वार्ड का चयन किया गया। मानस भवन में अधिकारियों और सामान्य लोगों की मौजूदगी में वार्ड नंबर 8, 11, 16, 32, 34, 35, 39, 40, 42, 51, 55, 56, 73 की पर्ची डाली गई। लॉटरी सिस्टम से एक पर्ची निकलवाई गई, तो वार्ड क्रमांक 51 रविंद्रनाथ टैगोर ओबीसी में आरक्षित हुई।

जबलपुर नगर निगम की तस्वीर

- **एससी अनारक्षित**- वार्ड नंबर 44, 52, 78, 62, 63
- **एससी महिला**- वार्ड नंबर 9, 29, 48, 53, 58, 66
- **एसटी अनारक्षित**- वार्ड नंबर 64 व 77
- **एसटी महिला**- वार्ड नंबर 70 व 75
- **ओबीसी अनारक्षित**- 51, 38, 74, 5, 2, 54, 37, 28, 3, 59, 65
- **ओबीसी महिला**- वार्ड नंबर 1, 57, 67, 27, 10, 71, 17, 20, 36 व 24
- **सामान्य**- 18, 23, 26, 43, 45, 46, 47, 49, 61, 8, 11, 16, 32, 34, 35, 39, 40, 42, 55, 56, 56 व 73
- **सामान्य महिला**- 13, 14, 19, 21, 30, 33, 50, 60, 69, 72, 76, 4, 6, 7, 12, 15, 22, 25, 31, 41, 68 व 79

महंगाई खा रही सारी कमायी

देश में पिछले 6-7 साल से महंगाई लगातार बढ़ रही है। सरकार महंगाई पर जवाब देने से बचने के लिए यूक्रेन-रूस युद्ध को जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन वास्तविकता यह है कि बढ़ी जीएसटी, वैट, जीएसटी और जमाखोरी करके मुनाफा कमाने की पूंजीपतियों की चाहत इसके लिए जिम्मेदार है। इस सबके लिए हमारा सरकारी तंत्र जिम्मेदार है, जो पूरी तरह अव्यवस्था के दौर से गुजर रहा है। जनता से सच छिपाया जा रहा है। जो भी आंकड़े बताए जा रहे हैं, वो सही नहीं हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर मध्यम और गरीब तबका परेशान है। जानकारों का कहना है कि अगर समय रहते महंगाई पर काबू नहीं पाया गया, तो आने वाले दिनों में यह और भी बढ़ेगी, जिससे अपराध बढ़ेंगे।

आर्थिक मामलों के जानकार पीयूष जैन का कहना है कि महंगाई तो 2020 के कोरोना के आने के दौरान से तेजी से बढ़ रही है। लेकिन सरकार ने बढ़ती महंगाई के लिए कोरोना को दोषी ठहराकर अपना पल्ला छाड़ लिया था। तब लोगों ने भी कोरोना को वैश्विक महामारी समझकर महंगाई के दंश को स्वीकार कर लिया था। लेकिन अब सरकार ने रूस और यूक्रेन युद्ध को महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। ऐसे में जब सरकार ही अपनी जिम्मेदारी से बचेगी, तो महंगाई पर कैसे काबू पाया जा सकता है? पीयूष जैन का कहना है कि देश के कुछ चंद पूंजीपतियों ने जिस तरह से बाजार पर अपना कब्जा किया है, उसे देखकर तो नहीं लगता है कि महंगाई पर जल्द काबू पाया जा सकता है। आटा, दाल और चावल के साथ खाद्य तेल का कारोबार चंद पूंजीपतियों के हाथों में है। ये लोग सरकार की अनदेखी कर अपनी इच्छानुसार चीजों के भाव तय करके जमकर पैसा कमाने में लगे हैं। क्योंकि सरकार का अप्रत्यक्ष रूप से इनके ऊपर हाथ है। यही वजह है कि महंगाई अनियंत्रित होती जा रही है।

आर्थिक मामलों के जानकार एवं कर विशेषज्ञ (टैक्स एक्सपर्ट) ध्रुव अग्रवाल का कहना है कि सरकार अपना खजाना भरने के लिए गरीबों की जेबें खाली करने में लगी है। जिस तरीके से मई के पहले सप्ताह में ही घरेलू गैस के सिलेंडर के दाम एकमुश्त 50 रुपए बढ़ाए हैं, उससे देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को करारा झटका लगा है। उन्होंने बताया कि खुदरा महंगाई दर तो करीब सात फीसदी के आसपास है, जबकि थोक महंगाई दर पिछले एक साल से दो-दहाई अंकों पर पहुंच चुकी है, जो अपने आप में सामान्य बात नहीं है। उनका कहना है कि कोरोना के कारण देश के लोग बढ़ती आर्थिक परेशानियों से उबरे नहीं थे कि यूक्रेन और रूस के लंबे खिंचते युद्ध की वजह से कच्चे तेल और अनाज के साथ खाद्य तेल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं।

सरकार की नीयत में खोट

छोटे-बड़े व्यापारियों ने साफ कहा है कि सरकार की नीयत में खोट है। उनका कहना है कि हमारी सरकार को भलीभांति मालूम है कि कोरोना महामारी के चलते लोगों का रोजगार छिना है और कामधंधा मंदा हुआ है। परिवार-के-परिवार कोरोना के चलते उजड़ गए हैं। ऐसे में पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट, गैस, खाद्य तेल, खाद्यान्न महंगे करना, कर (टैक्स) बढ़ाना और कई तरह की वसूली प्रथा को बढ़ावा देना ठीक नहीं है। कई राज्यों में तो गैस सिलेंडर 1,000 रुपए से ज्यादा का मिल रहा है। देश का किसान गेहूं, धान (चावल), सब्जी, खाद्यान्न तेल की फसलें और दालें पैदा करता है, लेकिन उसे सही दाम कभी नहीं मिलते।

दिल्ली के चांदनी चौक के व्यापारी विजय प्रकाश जैन का कहना है कि पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से पटरी पर लाने के लिए बड़ी सूझबूझ और मेहनत की आवश्यकता होती है। अगर व्यवस्था में पारदर्शिता न हो, तो वह ठीक नहीं हो सकती। हमारे यहां कुछ भी ठीक नहीं है, यही वजह है कि व्यवस्था सुधरने की जगह बिगड़ती जा रही है। जैसा कि मौजूदा समय में हो रहा है। उनका कहना है कि सन् 2020 में जब कोरोना के चलते जिन लोगों की नौकरियां गईं, उनकी अभी तक पूर्ण रूप से वापसी नहीं हुई है। जिन्हें नौकरी मिल गई, उनमें से बहुतों को पूरा और योग्यतानुसार वेतन नहीं मिल रहा है। इससे देश में बड़े तबके की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। सरकार इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। विजय प्रकाश जैन का कहना है कि आंकड़े बताते है कि सन् 2020 से ही देश में लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। ऐसे में सरकार को ठोस और कारगर कदम उठाने की जरूरत है, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। साथ ही बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए भी सरकार को बेहतर कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार को अपनी मनमानी को रोकना होगा। अन्यथा पड़ोसी देशों जैसे हालात बनने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि देश का बड़ा तबका महंगाई की चौतरफा मार से कराह रहा है।

दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रो. एस राज सुमन का कहना है कि जब कोरोना महामारी चरम पर थी, तब और जब देश में पांच राज्यों में चुनाव चल रहे थे, तब महंगाई का मुद्दा दबा रहा। जैसे ही पांच राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित हुए, महंगाई बढ़ी भी और लोगों का ध्यान भी इसने खींचा। अब यूक्रेन-रूस का युद्ध चल रहा था, तब भी महंगाई की चर्चा दबाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने बताया कि हाल ही में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की रिपोर्ट में यूक्रेन संकट की वजह से चालू वित्त वर्ष 2022-23 में सारी दुनिया में व्यापारिक घाटा बढ़ा है। इसके मद्देनजर वैश्विक व्यापार लगभग 4.7 से घटकर तीन फीसदी तक रह गया है। ऐसे में भारत जैसे देश में आशंका जताई जा रही है कि महंगाई अभी और बढ़ेगी। उनका कहना है कि हमारी सरकार को महंगाई पर काबू पाने के लिए सही-सही आंकड़े सार्वजनिक करने होंगे। साथ ही कोरोनाकाल में गई युवाओं की नौकरी को वापस दिलाने का प्रयास करना होगा। जमाखोरी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना होगा और कर (टैक्स) कम करना होगा। अन्यथा महंगाई सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती ही जाएगी। उनका कहना है कि देश में महंगाई बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण अगर कोई है, तो वो है देश में पूंजीपतियों की विस्तारवादी सोच। क्योंकि वे जमकर जमाखोरी करने और चीजों के मनमाने दाम वसूलने में लगे हैं।

● **अक्स ब्यूरो**

वंशवाद में बंधी कांग्रेस

देश की सबसे पुरानी पार्टी दिन पर दिन रसातल में जा रही है, उसके बावजूद पार्टी वंशवाद से मुक्त नहीं हो पा रही है। आलम यह है कि पार्टी के नेता भी वंशवाद को बढ़ाने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस कारण पार्टी मजबूत नहीं हो रही है।

कांग्रेस के चिंतन शिविर में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक मीटिंग में प्रस्ताव रखा कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं हैं, तो प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। हालांकि, बाकी मौकों पर और कार्यकारिणी की बैठक में भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाए जाने की मांग कर रहे थे। जब प्रमोद कृष्णम ने ये पहल की तब राहुल गांधी वहां नहीं थे। प्रमोद कृष्णम की मांग पर न तो सोनिया गांधी ने कुछ बोला, न ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने जरूर सपोर्ट किया। दीपेंद्र हुड्डा का कहना रहा कि प्रियंका गांधी को सिर्फ उप्र तक सीमित करके नहीं रखा जाना चाहिए।

बीच में प्रमोद कृष्णम को मल्लिकार्जुन खड्गे रोकने की कोशिश जरूर करते रहे, लेकिन वो नहीं माने। दीपेंद्र हुड्डा की तरह रंजीत रंजन ने भी प्रियंका गांधी को एक राज्य तक सीमित न करने के प्रस्ताव का समर्थन किया। मल्लिकार्जुन खड्गे चिंतन शिविर के लिए बनी राजनीतिक समिति के संयोजक हैं और उसी पैनल में प्रमोद कृष्णम और रंजीत रंजन भी हैं। ये सवाल जब सचिन पायलट के सामने मीडिया ने उठाया तो बोले कि कांग्रेस में सबको बोलने का हक है और राहुल गांधी ने भी उसी बात को अपने तरीके से एनडोर्स किया है। कांग्रेस पार्टी के डीएनए में सबको बिना डरे बोलने की आजादी है, जबकि भाजपा में ऐसा नहीं है।

जोड़ा जाए तो राहुल गांधी 18 साल से सक्रिय राजनीति में हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा को अभी तीन साल ही हुए हैं। पहले प्रियंका गांधी सिर्फ अमेठी और रायबरेली में अपने भाई और मां के चुनाव कैंपेन तक खुद को सीमित रखती थीं। 2019 के आम चुनाव से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस महासचिव और पूर्वांचल का प्रभारी बनाया गया, लेकिन तब से लेकर अभी तक उनके नाम कामयाबी के नाम पर जीरो बैलेंस ही है। जिस क्षेत्र में प्रियंका गांधी बचपन से चुनाव प्रचार में शामिल होती रहीं, औपचारिक जिम्मेदारी मिलते ही फेल हो गईं, राहुल गांधी को अमेठी में भाजपा की स्मृति ईरानी ने हरा दिया।

फिर 2022 का विधानसभा चुनाव आया और तमाम तामझाम के बावजूद कांग्रेस को महज दो सीटें मिलीं, वो भी नेताओं ने अपने बूते जीती होंगी। प्रियंका गांधी ने 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' जैसा जोरदार कैंपेन चलाया और 40 फीसदी महिला उम्मीदवारों को टिकट भी दिया था। बेशक राहुल गांधी को हाल फिलहाल कोई कामयाबी नहीं मिली है। अपनी भी सीट हार गए। वो तो वायनाड ने इज्जत बचा ली, लेकिन ऐसा 2019 के बाद से ही ज्यादा हो रहा है। तभी से जब से प्रियंका गांधी को कांग्रेस में औपचारिक जिम्मेदारी दी गई है।

2018 में राहुल गांधी ने देश के तीन राज्यों में कांग्रेस को जीत दिलाई थी- मप्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़। उससे करीब 6 महीने पहले कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता में वापसी नहीं करा पाए, लेकिन भाजपा को आने से रोक देना भी तो कम महत्व की चीज नहीं है। 2017 में राहुल गांधी पर उप्र की हार की तोहमत तो मढ़ दी जाती है, लेकिन पंजाब की जीत का कोई क्रेडिट नहीं मिलता। पंजाब चुनाव निश्चित तौर पर कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी बदौलत और प्रशांत किशोर के कैंपेन के बूते जीता था, लेकिन राहुल गांधी भी काफी सक्रिय रहे। ये जरूर था कि उप्र के मुकाबले कम सक्रियता रही। कैप्टन के दबाव में ही सही, लेकिन राहुल गांधी ने ही उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया था।

उसी साल गुजरात चुनाव में कांग्रेस इतना तो नहीं कर पाई कि सरकार बना ले, लेकिन भाजपा को मुश्किल में तो डाल ही दिया था। कांग्रेस के एक **साधारण कैंपेन** 'विकास पागल हो गया है' को रोकने के लिए भाजपा को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। जब कोई उपाय नहीं सूझ रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोर्चा संभालना पड़ा था, फिर भी जैसे-तैसे सरकार बन पाई। राहुल गांधी ने 2004 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा था और 2019 में कांग्रेस को उप्र में ज्यादा सीटें दिलाकर काफी तारीफ बटोरी थी, क्या प्रियंका गांधी के पास बताने के लिए ऐसा कुछ भी है?

प्रियंका गांधी को औपचारिक तौर पर तो 2019 के आम चुनाव से पहले शामिल किया गया, लेकिन 2017 में राहुल गांधी की ताजपोशी के साथ ही आगे बढ़कर दखल देने लगी थीं। तब मालूम हुआ कि ताजपोशी की सारी तैयारियों का जिम्मा प्रियंका के हाथ में ही रहा और छोटी से छोटी चीज उनसे पूछकर ही की गई। उससे पहले 2018 की शुरुआत में जब कांग्रेस ने रेप की घटनाओं के विरोध में इंडिया गेट पर कैंडल मार्च किया था तो पहल प्रियंका गांधी की ही

वंशवाद पर मोदी की नकेल

वर्ष 2014 में पीएम मोदी के सत्ता में आने के साथ देश से वंशवाद की राजनीति का सूरज अस्त होना प्रारंभ हो गया है। मोदी के कुशल नेतृत्व, भ्रष्टाचार रहित और जन-केंद्रित शासन ने जाति और तुष्टीकरण की राजनीति पर जीत हासिल करनी शुरू कर दी है। वंशवाद की राजनीति का मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कई राजनीतिक और शासन संबंधी प्रयोग भी किए हैं। भ्रष्टाचार रोकने के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं को जनधन-आधार-मोबाइल से जोड़ा। इस तरह उन्होंने एक नया लाभार्थी वोट बैंक बनाया। इंटरनेट मीडिया के जरिये सीधे मतदाताओं तक पहुंचना शुरू कर दिया। आज मोदी ने वंशवाद की राजनीति के पैरोकारों को राजनीति को पूर्णकालिक काम की तरह मानने पर बाध्य कर दिया है। कुल मिलाकर मोदी युग में वंशवाद की राजनीति के 'अच्छे-दिन' का अंत भी शुरू हो गया है।

भाजपा में योग्यता के आधार पर पदोन्नति

भाजपा का चरित्र कुछ अलग नजर आता है। वह अपने नेताओं की 'योग्यता के आधार पर पदोन्नति' देती है। यही भाजपा की सफलता का आधार है। पिछले दो दशकों में भाजपा के नेतृत्व पर एक नजर डालने से यह स्पष्ट हो जाता है। जेपी नड्डा का अमित शाह से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है। अमित शाह का राजनाथ सिंह से कोई संबंध नहीं है। राजनाथ सिंह का नितिन गडकरी या वेंकैया नायडू का लालकृष्ण आडवाणी से कोई संबंध नहीं है। वे सभी विभिन्न जातियों और देश के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। इन सभी में केवल एक चीज समान है-और वह है योग्यता और परिश्रम। इसके विपरीत प्रथम-परिवारों के नेताओं के जीवन से परिश्रम और योग्यता दूर हैं। वे अपने परिवार के नाम के सहारे ही संसद या विधानसभा में हैं। नतीजतन 17वीं लोकसभा में राहुल गांधी की उपस्थिति 56 प्रतिशत, अखिलेश यादव की 33 प्रतिशत और अभिषेक बनर्जी की 13 प्रतिशत है। जबकि मोदी के नेतृत्व में भाजपा यह सुनिश्चित करती है कि भले ही कोई किसी राजनीतिक परिवार से जुड़ा हो, लेकिन वह प्रदर्शन से समझौता नहीं करे। इस वजह से 17वीं लोकसभा में प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की उपस्थिति 93 प्रतिशत और पूनम महाजन की उपस्थिति 83 प्रतिशत रही है।

बताई गई थी। जब 2018 के आखिर में कांग्रेस को तीन राज्यों में सरकार बनाने का मौका मिला तो मुख्यमंत्री पद को लेकर पेंच फंस गया। तभी पहली बार प्रियंका गांधी के संकटमोचक रूप को देखा गया। लेकिन हुआ क्या? तीनों राज्यों में मामला अब तक उलझा हुआ है और मप्र में तो करीब सालभर बाद ही कांग्रेस को सत्ता तक गंवानी पड़ी थी।

पंजाब का प्रयोग सबने देख ही लिया है। पंजाब के पूरे एक्सपेरिमेंट को भाई-बहन लीडरशिप का फैसला माना गया, हालांकि कपिल सिब्बल के सवाल उठाने पर सोनिया गांधी ने **कार्यकारिणी की बैठक** बुलाकर काउंटर किया कि फैसले वो ही लेती हैं। पंजाब को लेकर सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एक कमेटी बना दी थी। राहुल गांधी अपने स्तर पर विधायकों से संपर्क कर रहे थे, लेकिन तभी प्रियंका गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की और बात आगे बढ़ी, बाद में क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं है।

उप्र चुनाव में भी प्रियंका गांधी को खुलकर काम करने की छूट दी गई थी। चुनावों के बीच पहली बार राहुल गांधी गए भी तो इलाहाबाद और वाराणसी होकर निजी दौरा बताकर लौट गए, और दोबारा गए तब भी अमेठी तक सीमित रहे। मतलब, किसी तरह का कोई दखल नहीं हुआ। हो सकता है ये राहुल गांधी की तरफ से हुआ हो या प्रियंका गांधी को ही दखल बर्दाश्त न हुई हो। वैसे भी कांग्रेस के एक मैनिफेस्टो रिलीज के मौके पर प्रियंका गांधी ने तो खुलकर बोल ही दिया था कि कांग्रेस में उनके अलावा किसी और का चेहरा नजर आ भी रहा है क्या? लखीमपुर खीरी जैसे मुद्दे को उठाकर सड़क पर उतरीं प्रियंका गांधी ने कोई कम मेहनत तो नहीं की थी। सोनभद्र के उभ्भा गांव से लेकर उन्नाव गैंगरेप पीड़ित की मां और सीएए आंदोलन में एक्टिव लोगों को भी टिकट दिया था, लेकिन क्या वजह रही कि पूरे उप्र में कांग्रेस को दो से ज्यादा जिताऊ उम्मीदवार नहीं मिले। तब क्या होता जब उप्र में कांग्रेस की सीटें दहाई में पहुंच गई होतीं? फिर तो कांग्रेस में प्रियंका गांधी के करीबी राहुल गांधी का जीना ही हराम कर देते।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटु आलोचक भी मानते हैं कि उन्होंने भारतीय राजनीति के व्याकरण को कई मायनों में बदल दिया है। परिश्रम, दक्षता और योग्यता तेजी से चाटुकारिता और परिवारवाद वाली राजनीति की जगह ले रही है। वैसे भी जो पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहती है, वही भविष्य के लिए खेल के नियम तय करती है। सभी छोटे खिलाड़ी उस फॉर्मूले का अनुकरण करते हैं। कांग्रेस भी लंबे समय तक सत्ता में रही है। लिहाजा अधिकांश पार्टियों ने उसका अनुकरण किया। कांग्रेस ने भारतीय राजनीति को 'वंशवाद की राजनीति' का सूत्र सिखाया। बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी सरीखे दिग्गजों ने कांग्रेस को एक आंदोलन के रूप में चलाया, लेकिन स्वतंत्रता के बाद वह नेहरू-गांधी परिवार की निजी संपत्ति मात्र बनकर रह गई। उसने समय के साथ खुद को देश के 'प्रथम-परिवार' के रूप में स्थापित कर लिया।

नेहरू-गांधी परिवार को स्थापित करने की होड़ में कांग्रेस ने सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. बीआर अंबेडकर और लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं को भी भुला दिया। पार्टी की कमान हमेशा नेहरू-गांधी परिवार के सदस्यों के बीच ही घूमती रही। जब कभी पार्टी के किसी भी क्षेत्रीय नेता का कद यदि प्रथम-परिवार के सदस्यों से ऊंचा होने लगा तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं में यह भ्रम पैदा कर दिया गया कि प्रथम-परिवार के सदस्य ही कांग्रेस को एक साथ बांधकर रख सकते हैं। दुर्भाग्य से क्षेत्रीय क्षत्रपों ने भी कांग्रेस की इस नीति का अनुसरण किया। जम्मू-कश्मीर में मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार राज्य के प्रथम-परिवार बन गए। उप्र और बिहार में मुलायम और लालू यादव परिवार प्रथम-परिवार बन गए। इसी तरह कर्नाटक में देवगौड़ा परिवार, महाराष्ट्र में ठाकरे एवं पवार परिवार, तमिलनाडु में करुणानिधि परिवार, तेलंगाना में केसीआर परिवार, आंध्र में नायडू एवं वाइएसआर परिवार ने अपनी-अपनी पार्टियों को पारिवारिक कंपनियों में बदल दिया। योग्यता पर प्रथम-परिवार को हावी रखने के लिए कांग्रेस को और कई चालें चलनी पड़ीं। पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध नौकरशाही एवं न्यायपालिका, मैत्रीपूर्ण मीडिया, जातिगत राजनीति और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के माध्यम से चुनाव जीतने जैसे हथकंडे कांग्रेस के राजनीतिक व्याकरण का हिस्सा बन गए। निरंतर हार के बाद भी नेहरू-गांधी परिवार पार्टी के शीर्ष पर बना रहा। हद तो तब हो गई जब 2017 में राहुल गांधी ने वैश्विक स्तर पर वंशवाद की राजनीति का खुलकर बचाव किया। उन्होंने कहा कि पूरा भारत राजवंशों पर चलता है और इसमें कोई हर्ज नहीं है।

● **विपिन कंधारी**

देश में अभी तक चुनावी जंग कांग्रेस बनाम भाजपा होती रहती थी, लेकिन अब क्षेत्रीय पार्टियां तेजी से उभर रही हैं, जिससे देश की दोनों पुरानी पार्टियों को कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। इससे कई राज्यों में भाजपा और कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उधर, जिस तरह क्षेत्रीय पार्टियां लामबंद होने की जमावट कर रही हैं, उससे 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। देश में उभर रहे नए राजनीतिक विकल्प से निपटने के लिए भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस बेफिक्र है। अब देखना यह है कि 2024 से पहले देश में राजनीति का नया विकल्प तैयार हो पाता है या नहीं?

देश में उभर रहा नया राजनीतिक विकल्प

2024 के चुनाव से पहले तीसरी ताकत बनी आप

करीब 8 साल पहले नई दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा को करारी पटखनी देने वाली आम आदमी पार्टी ने अब पंजाब में दशकों पुराने सियासी दिग्गजों को धूल चटाकर भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव की नींव रख दी है। दो राज्यों में सरकारों के साथ वह अब देश की सबसे पुरानी पार्टी, कांग्रेस के बराबर आ खड़ी हुई है जिसकी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, दशकभर से भी कम समय में यह सियासी सफलता हासिल करने वाली आप 2024 लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय सियासत में बड़ी ताकत के रूप में उभर आई है। 2013 में दिल्ली में अल्पकालिक सरकार बनाने के सालभर के भीतर ही आप ने 2014 लोकसभा चुनाव में पंजाब में सफलता का स्वाद चखा। तब उसे 24.4 फीसदी वोट प्रतिशत के साथ चार सीटें मिलीं। इसके बाद 2015 में पार्टी ने दिल्ली में एकतरफा जीत दर्ज की।

2009 से लेकर 2014 और 2019 के आम चुनावों तक भाजपा ने राष्ट्रीय वोट शेयर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर करीब दोगुनी कर ली है। ज्यादा मार्के की बात यह है कि तमाम सबूत यही कह रहे हैं कि आज वह दोगुनी ताकतवर हो गई है। इस बीच, 2017 के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था लंबे समय से गतिरोध की स्थिति में है, बेरोजगारी अपनी ऐतिहासिक ऊंचाई पर है, महंगाई चरम पर है, खासकर ईंधन और खाद्य तेलों की कीमतें आसमान छू रही हैं, और दो सालों से महामारी का दर्द भी झेल रहे हैं। फिर भी, भाजपा और खास तौर से नरेंद्र मोदी के वोटर डिगे नहीं हैं। और, ये वोटर, भाजपा के केवल प्रतिबद्ध मतदाता नहीं हैं जिन्हें आप ठोस हिंदुत्ववादी मतदाता कहते हैं। उन्होंने तो 2009 में भी भाजपा को वोट दिया था। ये तो वे नए करोड़ों वोटर हैं जिन्हें भाजपा ने बाद में अपनी तरफ खींचा है, और उसके प्रति जिनकी प्रतिबद्धता अडिग दिखने लगी है।

बढ़ती बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक सभी नकारात्मक बातों को वे कबूल करते हैं, उन पर झल्लाते हैं लेकिन आप उनसे पूछिए कि वे किसे वोट देंगे तो उनका जवाब यही होगा– नरेंद्र मोदी और भाजपा। अगर आप उनके तर्कों को सुनेंगे कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का दूसरा विकल्प कौन है, कहां है? तो यह सहज बुद्धि के बहुत विपरीत नहीं लगेगा। उनका तर्क होता है कि हम 'उस' राहुल गांधी को और कांग्रेस को कैसे वोट दे सकते हैं? और, फिर से एक 'खिचड़ी गठबंधन' भला कौन चाहता है?

जो लोग पारंपरिक रूप से भाजपा के वोटर्स नहीं रहे हैं, उनमें से अगर अधिकतर भाजपा के साथ इसलिए बने हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि 'कोई विकल्प नहीं है' तो बता दें कि इनमें से कुछ चीजों के बदलने की शुरुआत हो चुकी है। अब एक विकल्प उभर रहा है। लेकिन यह भाजपा और मोदी का विकल्प नहीं है, बल्कि कांग्रेस का विकल्प है। जो कि, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव है। हालांकि, मोदी के वर्चस्व के इस दौर में भी एक उल्लेखनीय तथ्य कायम है, कि कांग्रेस ने 20

फीसदी का अपना न्यूनतम वोट प्रतिशत बनाए रखा है। 2014 और फिर 2019 के आम लोकसभा चुनावों में सफाया होने के बाद भी कांग्रेस के वोट, भाजपा को छोड़ किन्हीं भी पांच दलों के कुल वोट से ज्यादा थे। इसलिए वह भविष्य के किसी भी भाजपा-विरोधी गठबंधन या चुनौती के लिए अहम बनी रही।

इसके अलावा, जब तक वह अपने इस वोट बैंक को साबुत बनाए रखेगी तब तक किसी दूसरी पार्टी या गठबंधन के लिए मोदी को चुनौती देना असंभव है। इसने कांग्रेस को सत्ता के लिए सौदेबाजी करने की ताकत भी दी है, चाहे यह गठबंधन बनाने का मामला हो या प्रशांत किशोर से निबटने का। लेकिन वह आधार अब खिसक रहा है। यह उनके लिए बुरी खबर तो है लेकिन भाजपा के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है। भाजपा को डर होगा कि उसके गैर-पारंपरिक वोटर्स के पास यह बहाना नहीं रह जाएगा नरेंद्र मोदी या भाजपा का 'कोई विकल्प है नहीं है, और हम कांग्रेस या गांधी परिवार को वोट नहीं दे सकते।'

इसका मतलब यह हुआ कि जो कांग्रेस के लिए बुरा है वह भाजपा के लिए भी अच्छा नहीं है। भाजपा अब तक कांग्रेस के इस इतिहास को जानकर संतुष्ट रही है कि जिस राज्य में वह एक बार चुनाव में निर्णायक रूप से सत्ता गंवा देती है वहां दोबारा सत्ता में नहीं लौटती। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा वोट पाने वाले दलों में दूसरे नंबर पर होने के बावजूद ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसे कांग्रेस 'अपना' कह सके। लेकिन इस स्थिति में कुछ बदलाव आ रहा है।

2014 के आसपास एक रुझान सा बन गया था कि कांग्रेस उन राज्यों में साफ होने लगी जिनमें उसका दबदबा था। सबसे उल्लेखनीय हार आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में हुई। इनमें से एक राज्य में आज उसका कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है, तो दूसरे में उसकी मामूली उपस्थिति है और वह भी घट रही है। वैसे भी, सत्ताधारी क्षेत्रीय नेताओं के मुकाबले में कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा ही चुनौती के रूप में उभरती दिख रही है। अब जरा देखिए कि हाल ही में पंजाब में क्या हुआ? एक राज्य जिसे कांग्रेस कुछ हद तक 'अपना' कह सकती थी वहां भी उसे भारी हार का मुंह देखना पड़ा, वह भी अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी अकाली दल से नहीं। बल्कि, उसका सफाया इसलिए हुआ क्योंकि उसके वोट को भाजपा के एक दूसरे 'सेकुलर' प्रतिद्वंद्वी आम आदमी पार्टी ने हड़प लिया। एक्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि करीब आधे हिंदू और दलित सिख (जो कांग्रेस के पुराने समर्थक थे) आप की ओर मुड़ गए।

भाजपा भले सिर्फ दो सीट जीत पाई लेकिन उसने राष्ट्रीय स्तर पर अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी को भारी चोट पहुंचा दी और एक फायदा यह भी हुआ कि अरविंद केजरीवाल और आप के रूप में एक नया, ज्यादा शोर मचाने वाला, तेज, ज्यादा लोकलुभावनवादी और आक्रामक प्रतिद्वंद्वी उभर आया। आप की सरकार सुस्त कांग्रेस के मुकाबले से किस तरह अलग पैमाने पर एक चुनौती बन गई है, यह तजिंदर बग्गा वाले तमाशे से स्पष्ट है। आपने पंजाब सहित किसी भी राज्य की कांग्रेस सरकार को इस तरह का तमाशा करते नहीं देखा होगा।

बहरहाल, हम राजनीति की हवा के रुख के बारे में कहीं और से भी अंदाजा लगाते हैं। गोवा में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में, 2017 में कांग्रेस को मिले वोट की तुलना में 5 प्रतिशत की कमी आई, बावजूद इसके कि वहां की भाजपा सरकार अलोकप्रिय हो गई थी। गोवा वाले भाजपा से नाराज थे। लेकिन, वे न केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस के भी विकल्प की तलाश कर रहे थे। करीब 7 फीसदी लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया और 5 फीसदी से ज्यादा ने तृणमूल कांग्रेस को। अब अगर कांग्रेस के 23.46 प्रतिशत वोट में इन वोट्स को जोड़ दें तो भाजपा गोवा में साफ हो जाती। इससे भी ताजा है गुवाहाटी नगरपालिका का चुनाव। असम वह राज्य है जहां भाजपा से हारने के पहले कांग्रेस ने तीन कार्यकाल तक राज किया था। वह अभी भी खुद को मजबूत विपक्ष मानती है और अगली बार सत्ता में वापस आने की उम्मीद करती है। लेकिन राज्य की राजधानी और राजनीतिक केंद्र गुवाहाटी में उसे आम आदमी पार्टी से इतनी कांटे की टक्कर मिली कि उसे खतरा पैदा हो गया है।

इस चुनाव में भाजपा ने 60 फीसदी वोट पाकर प्रतिद्वंदियों का सफाया कर दिया और कांग्रेस सिर्फ 13.72 फीसदी वोट के साथ बड़े अंतर से दूसरे नंबर पर रही। लेकिन खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी भी 10.69 फीसदी वोट शेयर के साथ लगभग कांग्रेस के बराबर पहुंच गई। बल्कि उसने एक सीट भी जीत ली जबकि कांग्रेस के हाथ एक सीट भी नहीं आई। राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा नहीं बल्कि कांग्रेस के एक **नए विकल्प के उभरने** का यह एक और छोटा संकेत है। बात केवल आम आदमी पार्टी की नहीं है। बात कांग्रेस की अपने वफादार वोटर्स को बचाए रखने की उस अक्षमता की है जब उसके सामने दूसरा कोई स्वीकार्य विकल्प मौजूद हो।

● **इन्द्र कुमार**

प्रशांत किशोरः डग भरने की ख्वाहिश

पदयात्राएं और देश-भ्रमण राजनीति का कोई नया नुस्खा नहीं, अपने में तो कतई नहीं। आजादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी की यात्राएं और आंदोलन तो इतिहास का अमिट हिस्सा हैं ही, उसके बाद भी खासकर पदयात्राएं कई मामलों में राजनीति में सफलता की कुंजी साबित होती रही हैं। हां, कोई चाहे तो साइकिल यात्राओं, रथयात्राओं वगैरह को भी जोड़ सकता है मगर पदयात्राएं ज्यादा असरदार साबित हुई हैं। कुछेक मिसालों में 80 के दशक में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की भारत यात्रा या बेहद हालिया आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की है। यात्राएं न सिर्फ सियासी कामयाबी दिलाती रही हैं, बल्कि कद भी कुछ पुश्त ऊंचा उठाती रही हैं। बेशक, प्रशांत किशोर को भी यह इल्म होगा। आखिर वे लगभग देशभर की राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावी रणनीतियां तैयार करने में मशगूल रह चुके हैं और उनके नाम सफलताएं भी जोड़ी जाती रही हैं, कुछेक विफलताएं भी बताई जाती हैं। इसलिए जब वे राजनीति में कदम बढ़ाने की सोच रहे हैं तो पटना में 5 मई को उनके इस ऐलान पर बहुतों की दिलचस्पी बढ़नी ही थी कि मैं 2 अक्टूबर से बिहार (अपने गृह प्रदेश) की करीब 3,000 किलोमीटर की पदयात्रा करूंगा, ताकि हर टोले, गांव, शहर, गली-मोहल्ले में पहुंच सकूं। वजह यह है कि लालू यादव और नीतीश कुमार जैसी शख्सियतों के तकरीबन 30 साल के राज में बिहार लगातार पिछड़ता ही गया है और आज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हर मानव सूचकांक पर सबसे पिछड़ा राज्य है।

फिर उठा आदिवासी आक्रोश

छत्तीसगढ़ में फिर आदिवासी आक्रोश ऊफान पर है। विधानसभा घेराव की मंशा से बस्तर के अलग-अलग इलाकों से राजधानी रायपुर की ओर कूच कर रहे आदिवासी फिलहाल तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के वादे पर लौट गए हैं, मगर महीनेभर में मांगें न मानने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। 'सर्व आदिवासी समाज' के बैनर तले इकट्ठा हुए आदिवासी सारकेगुड़ा, एडसमेटा न्यायिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलित हैं। दरअसल बीजापुर के एडसमेटा कांड की न्यायिक जांच रिपोर्ट 14 मार्च को विधानसभा में पेश हुई तो उस पर जल्द कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है।

नक्सल ग्रस्त बीजापुर जिले में 17 मई 2013 को एडसमेटा मुठभेड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग ने निष्कर्ष निकाला है कि सुरक्षा बलों ने निहत्थे लोगों की भीड़ पर घबराहट में गोलियां चलाई थीं। सुरक्षाबलों की कार्रवाई में तीन नाबालिग समेत 9 आदिवासी मारे गए थे। तत्कालीन भाजपा सरकार ने तब दावा किया था कि मारे जाने वाले लोग माओवादी थे। कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला कहते हैं, 'जब हम विपक्ष में थे तब हमारे ही दबाव के चलते तत्कालीन भाजपा सरकार को न्यायिक जांच के आदेश देने पड़े थे। लिहाजा कार्रवाई करने को लेकर कोई संदेह की बात ही नहीं है।' मुख्यमंत्री बघेल ने भी आंदोलनकारी आदिवासियों से यही वादा किया है। लेकिन मानवाधिकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं को विश्वास नहीं है कि सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाएगी। आदिवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के मन में अविश्वास के पीछे उनका पुराना अनुभव है।

विधानसभा में 2 दिसंबर 2019 को बीजापुर के सारकेगुड़ा में हुई मुठभेड़ की न्यायिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। 2012 के 28-29 जून की रात बीजापुर के सारकेगुड़ा क्षेत्र में सीआरपीएफ और सुरक्षाबलों के हमले में 17 लोगों की मौत हुई थी। सरकार ने उस दौरान दावा किया था कि सुरक्षाबलों ने 17 माओवादियों को ढेर किया है। मगर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट ने इसके उलट इस पूरे दावे को फर्जी ठहराया था। रिपोर्ट के मुताबिक मारे जाने वाले लोग निर्दोष आदिवासी थे और पुलिस की एकतरफा गोलीबारी का शिकार बने थे। मगर दोषियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह ताड़मेटला मामले की जांच में आयोग किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाया। 2011 में ताड़मेटला में करीब 259 आदिवासियों के घर जला दिए गए थे। आदिवासी अधिकारों के लिए संघर्षरत सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार कहते हैं, '2019 में सारकेगुड़ा मुठभेड़ की न्यायिक जांच की रिपोर्ट आई तब मैं दंतेवाड़ा गया था। हम लोग परसागुड़ा थाने भी गए लेकिन हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मुख्यमंत्री बघेल के सलाहकार ने फोन करके कहा कि दो महीने के भीतर कार्रवाई करेंगे....तीन साल बीत गए हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब एडसमेटा की रिपोर्ट भी आ गई है, मगर सरकार ग्रामीणों के विरोध करने के अधिकार को कुचल रही है।'

बीजापुर के एडसमेटा कांड पर न्यायिक जांच आयोग की 354 पृष्ठ की रिपोर्ट में कहा गया है 'सुरक्षा बलों ने शायद ग्राम एडसमेटा के समीप आग के आसपास एकत्रित लोगों को देखकर उन्हें नक्सली समझा और घबराहट में गोलियां चला दीं।' बस्तर अंचल में लंबे समय से आदिवासियों के बीच सक्रिय मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील बेला भाटिया का मानना है कि यहां फर्जी मुठभेड़ कोई नई बात नहीं है। वे कहती हैं, 'रमन सरकार में भी फर्जी मुठभेड़ होती थी और भूपेश सरकार में भी। लेकिन पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं करती है।'

कांग्रेस 'आदिवासी हितैषी' सरकार का तमगा लेकर सत्ता में आई थी। अब उस पर ठोस कदम उठाने का दबाव बढ़ रहा है। 2018 में सरकार के गठन के फौरन बाद टाटा संयंत्र के लिए अधिग्रहीत भूमि किसानों को वापस करने के फैसले से लेकर, वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत भूमिहीन आदिवासियों और परंपरागत वनवासियों को भूस्वामित्व देने में तेजी लाने जैसे कदमों ने आदिवासियों में विश्वास पैदा किया था। लेकिन फर्जी मुठभेड़ के आरोप, बस्तर में लगातार सुरक्षाबलों के कैंप खुलने और पेसा कानून के अनुपालन नहीं होने से खासतौर पर बस्तर के आदिवासी खफा हैं।

छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती ग्रामीण अंचलों में हुए हवाई हमले के विरोध की चिंगारी अब बड़ा रूप ले चुकी है, बस्तर पुलिस की तरफ से जारी बयान में इस तरह की घटना से साफ इंकार करने के बावजूद, बीजापुर की सीमावर्ती इलाके से लगे जगरगुंडा और पामेड़ क्षेत्र के दर्जनों गांव के ग्रामीण विस्फोट से हुए सुराख और अवशेषों को पुख्ता प्रमाण बता रहे हैं, इसके अलावा हमले के विरोध में बीते कुछ दिनों से लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहीं बोड़केल गांव में हुए प्रदर्शन में केवल हवाई हमले का विरोध ही नहीं बल्कि प्रदेश के आबकारी मंत्री और कोंटा विधायक कवासी लखमा पर भी प्रदर्शनकारियों ने जुबानी प्रहार किया है।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

नक्सलियों को बनाया गया टारगेट

बस्तर पुलिस के द्वारा ड्रोन से बमबारी का हवाला दे रहे गुस्साए ग्रामीणों ने कहा कि घटना की सच्चाई जानने और इसकी जांच की आदिवासी मंत्री कवासी लखमा ने जहमत तक नहीं उठाई, जबकि चुनाव से पहले कवासी लखमा ने कहा था कि पुलिस कैंप हटाए जाएंगे, आदिवासी इलाकों का विकास होगा और किसी तरह की ज्यादती नहीं होने देंगे, इन बातों को सुनकर गांव के ग्रामीणों ने उन्हें वोट दिया था। लेकिन चुनाव के बाद मंत्री कवासी लखमा के सुर बदल गए हैं। जनता से उन्होंने जो वायदे किए वो झूठे साबित हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि गर्मी के सीजन में महुआ फूलों की रखवाली के लिए आधी रात ग्रामीणों को उठकर जंगल जाना पड़ता है, ताकि मवेशियों का झुंड पेड़ से झड़ने वाले महुए के फूल को खा ना जाएं। इसी दौरान अगर नक्सलियों को टारगेट बताकर आसमान से बम बरसेंगे तो ग्रामीणों के साथ मवेशियों की जानें भी जा सकती हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन के नाम पर इस तरह की बमबारी से आदिवासी, जंगल, गांव तबाह हो जाएंगे, और अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो ग्रामीणों के सामने अपने घर को छोड़कर पलायन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा।

राज ठाकरे मोहरा भर ही हैं

राज ठाकरे अब भी एक करिश्माई नेता की तरह ही परफॉर्म कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे भले ही उनको नकली-ठाकरे साबित करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन अकेले में वो भी मानते होंगे कि राज ठाकरे के लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा मुहिम का कितना ज्यादा असर हुआ है। राज ठाकरे के भगवा शाल और लाल तिलक वाली तस्वीरें आने के बाद से उद्धव ठाकरे अपने समर्थकों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि महज रंग-रूप धारण कर लेने से कोई बाल ठाकरे नहीं बन सकता।

राज ठाकरे की मुहिम से ही हनुमान चालीसा उधार लेकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में नवनीत राणा और उनके पति को जेल तक की हवा खानी पड़ी, जबकि राज ठाकरे अब एक कदम आगे बढ़ाकर औरंगजेब के मकबरे के पीछे पड़ गए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में ये मुद्दा एआईएमआईएम सांसद अकबरुद्दीन ओवैसी के फूल चढ़ाने के बाद शुरू हुआ है। ऊपर से अकबरुद्दीन ओवैसी ने राज ठाकरे के खिलाफ कमजोर धाराओं में केस दर्ज किए जाने पर भी सवाल खड़े किए थे। अब राज ठाकरे अपने अयोध्या दौरे की तैयारी में लगे हैं, लेकिन उससे पहले अपनी एक और रैली के जरिए अपनी बात कहना चाहते हैं। बताते हैं कि पुणे में 21 मई को रैली करने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन फिर एप्लीकेशन को वापस ले लिया गया, क्योंकि रैली की कोई नई तारीख तय करनी है।

राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को काउंटर करने के लिए शिवसेना नेतृत्व की तरफ से भी अयोध्या भ्रमण का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, अगर उद्धव ठाकरे का कार्यक्रम नहीं बन पाया तो आदित्य ठाकरे भी चाचा राज ठाकरे से पहले अयोध्या का दौरा कर सकते हैं। असल में ये सब हिंदुत्व की राजनीति पर शह और मात के बड़े खेल का हिस्सा है। भाजपा पहले से ही उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर सवाल उठाती रही है और अब राज ठाकरे उसी को अपने तरीके से हवा दे रहे हैं। बावजूद ये सब होने के राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा के एक सांसद का कहना है कि वो राज ठाकरे को उप्र में घुसने नहीं देंगे। दरअसल, वो उत्तर भारतीयों पर राज ठाकरे के पुराने स्टैंड के लिए माफी मांगने पर अड़े हुए हैं और ऐन उसी वक्त अयोध्या के भाजपा सांसद का कहना है कि वो राज ठाकरे का तहे दिल से स्वागत करेंगे।

राज ठाकरे का विरोध और सपोर्ट ये सांसद क्या अपने मन से कर रहे होंगे? क्या भाजपा नेतृत्व की मर्जी के बगैर ये संभव है? दिसंबर, 2017 में भाजपा में अपनी बात कहने की मनाही को मुद्दा बनाकर तो नाना पटोले ने पार्टी ही छोड़ दी थी। तब नाना पटोले महाराष्ट्र के भंडारा-गोंदिया लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद हुआ करते थे और आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने किसी को बोलने ही नहीं दिया जाता है। नाना पटोले फिलहाल महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। भाजपा राज ठाकरे के पक्ष में खुलकर तो नहीं आती, लेकिन महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस मौका देखकर एक बात कहते जरूर हैं, जो लोग लाउडस्पीकर हटाने से डरते हैं, वो दावा करते हैं कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाने के समय वो वहां मौजूद थे।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेता राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या जाने वाले हैं। साथ ही ये खबर भी आई थी कि अयोध्या दौरे के वक्त राज ठाकरे उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी कर सकते हैं। उप्र के ही कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने योगी आदित्यनाथ को सलाह दी है कि वो राज ठाकरे से तब तक न मिलें, जब तक वो उत्तर भारतीयों के अपमान के लिए माफी नहीं मांग लेते। भाजपा सांसद ने चेतावनी दी है कि वो राज ठाकरे को अयोध्या में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि एमएनएस नेता ने उत्तर भारतीयों का काफी अपमान किया है। बृजभूषण शरण सिंह को जेडीयू का भी समर्थन मिला है। जेडीयू ने भी राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध करने की बात कही है। जेडीयू के उप्र अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल ने बृजभूषण शरण सिंह से इसी सिलसिले में मुलाकात भी की है। अनूप सिंह पटेल की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि जेडीयू की तरफ से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के साथ मिलकर 5 जून को राज ठाकरे को काला झंडा दिखाकर विरोध किया जाएगा।

राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर भाजपा के दो सांसद आमने-सामने भिड़ते लगते हैं। अयोध्या से भाजपा सांसद लल्लू सिंह अपने ही साथी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के विरोध के फैसले पर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से वो राज ठाकरे के स्वागत की बात कह रहे हैं। भाजपा सांसद लल्लू सिंह का कहना है कि राज ठाकरे पर हनुमानजी की कृपा हुई है, इसलिए वो प्रभु श्रीराम की शरण में आ रहे हैं और जो भी भगवान राम की शरण में आएगा, अयोध्या के राम भक्त होने के नाते हम उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। वैसे भी राज ठाकरे की हनुमान चालीसा मुहिम का उप्र में काफी असर दिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के **संसदीय क्षेत्र** वाराणसी में तो कुछ लोगों ने अपने छतों पर लाउडस्पीकर ही लगा लिया था। फिर मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर पर योगी आदित्यनाथ सरकार की सख्ती के बाद राज ठाकरे ने भी काफी तारीफ की थी। तारीफ में यहां तक कह गए कि उप्र में योगी सरकार है, जबकि महाराष्ट्र में भोगी सरकार है।

● **बिन्दु माथुर**

राज ठाकरे पर भाजपा का स्टैंड क्या है?

क्या राज ठाकरे का भी भाजपा वैसे ही इस्तेमाल कर रही है जैसे अब तक बिहार में जीतनराम मांझी और चिराग पासवान और उप्र में अब मायावती का करने लगी है? ऐसा लग रहा है कि भाजपा को राज ठाकरे के एमएनएस में भी शिवसेना जैसी संभावना नजर आ रही है और राज ठाकरे को भाजपा उद्धव ठाकरे के विकल्प के तौर पर देख रही है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में फर्क ये है कि शिवसेना के पास पहले से स्थापित संगठन है और कार्यकर्ता भी हैं। राज ठाकरे अभी तक खुद को शिवसेना की तरह स्थापित नहीं कर पाए हैं और भाजपा को शिवसेना जैसा भरोसा मनसे पर नहीं हो रहा होगा। तो क्या भाजपा राज ठाकरे को पार्टटाइम सहयोगी मानकर चल रही है? और उद्धव ठाकरे को लेकर भाजपा को अब भी फुलटाइम सहयोगी के रूप में लौटने की उम्मीद खत्म नहीं हुई है? नीतीश कुमार को मिसाल रखकर देखने पर यही लगता है। क्या ये समझा जाए कि जब तक उद्धव ठाकरे हार नहीं मान लेते और घर वापसी के फैसले की घोषणा नहीं कर देते, भाजपा यूं ही राज ठाकरे पर परदे के पीछे प्यार-दुलार लुटाती रहेगी?

खत्म होगा वसुंधरा युग!

राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा अभी से समीकरण बैठाने में लग गई है। भाजपा इस बार राजस्थान चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम पर नहीं लड़ेगी। राजस्थान भाजपा प्रमुख सतीश पूनिया ने साफ कर दिया कि पार्टी राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ेगी। जयपुर में भाजपा की तीन दिनों तक चलने वाली रणनीति बैठक के दूसरे दिन राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जयपुर में कहा कि कभी-कभी चेहरे प्रोजेक्टेड होते हैं और कभी-कभी नहीं भी होते हैं। भाजपा आगामी चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेगी। 2017 में उप्र में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया था, फिर भी हम जीत गए। भाजपा का यह बयान राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से करीब एक साल पहले आया है। राज्य भाजपा प्रमुख ने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे पार्टी ने नेतृत्व की अगली पीढ़ी को तैयार किया है। जिसके बाद यह संदेह पैदा हो गया कि कहीं भाजपा राजस्थान में पार्टी के सबसे बड़े चेहरे को संदेश तो नहीं दे रही है।

राजस्थान में सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे के बीच अनबन को लेकर अटकले लगती रही हैं। जब भी कभी इस तरह की रिपोर्ट सामने आती तो दोनों ही नेताओं की ओर से उसे नकारने का **प्रयास** भी होता रहा है। एक दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम में मंच पर पूनिया और राजे दोनों नजर आए थे। इसके अलावा नड्डा के रोड शो के दौरान भी राजे साथ नजर आईं थी। हालांकि, राजस्थान भाजपा अध्यक्ष की टाइमिंग और घोषणाओं में की गई बातों से ऐसे संकेत मिले हैं कि राज्य के नेतृत्व में राजे की अहम भूमिका हो सकती है, लेकिन वह पार्टी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार नहीं हो सकती हैं। सत्ता से बाहर होने के बावजूद वसुंधरा राजे हाल के सालों में पार्टी में अपनी भूमिका के बारे में स्पष्ट रूप से मुखर रही हैं।

राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा का चेहरा प्रधानमंत्री मोदी और कमल का फूल ही रहेंगे, लेकिन वसुंधरा समर्थकों को यह रास नहीं आया है। वसुंधरा समर्थकों ने प्रधानमंत्री मोदी को चेहरा मानने से इनकार कर दिया है। एक वसुंधरा समर्थक नेता ने कहा, वसुंधरा राजे की अनदेखी से विधानसभा चुनाव में नुकसान होगा। वसुंधरा राजे का राजस्थान में क्रेज है। विरोधी गुट वसुंधरा पर नकेल कसने की कोशिश कर रहा है। वसुंधरा समर्थकों के तेवर देख राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ अलग से बैठक कर प्रदेश के मौजूदा सियासी हालातों का फीडबैक लिया। दरअसल, समर्थक विधायक एवं नेता वसुंधरा राजे को राजस्थान की सियासत में पायलट जैसी स्थिति में नहीं देखना चाहते हैं। समर्थकों का आरोप है कि शेखावत और पूनिया बार-बार प्रधानमंत्री मोदी का नाम आगे कर सीधे तौर पर वसुंधरा पर टारगेट कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा की मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा, संगठन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से बड़ा है। वंशवाद और परिवारवाद के कीचड़ में कमल खिला है। वसुंधरा समर्थक इसे कटाक्ष के तौर पर मान रहे हैं। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया के एक समर्थक नेता ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थकों को भी एक संदेश दिया गया कि व्यक्तिगत वफादारी से उन्हें किसी तरह का लाभ नहीं मिलने वाला। वसुंधरा समर्थक गुटबाजी को हवा दे रहे है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चाहते हैं कि प्रदेश इकाई में मतभेदों को दूर किया जाए। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राजस्थान के जयपुर में आयोजित हुई। इस तीन दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ **स्टेट यूनिट्स** के प्रभारियों को पार्टी साफ तौर पर यह संदेश देने की कवायद में जुटी थी कि संगठन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से बड़ा है।

2018 का चुनाव इसलिए भी याद रखा जाता है कि लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान और मप्र में मृतप्राय कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई। यह अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी मप्र में अपने विधायकों को काबू करने में विफल रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा बगावत करके भाजपा में शामिल हो गया और 2020 में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बन गई। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति की एक बार फिर से सरकार बनी और मिजोरम में भाजपा के सहयोगी दल मिजो नेशनल फ्रंट को जीत हासिल हुई।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

मुख्यमंत्री पद से कोई समझौता नहीं

जानकारों का कहना है कि राजस्थान भाजपा में मुख्यमंत्री फेस नहीं बनाए जाने से वसुंधरा राजे बेहद नाराज हैं। वसुंधरा राजे ने भाजपा की हाई लेवल बैठक से पहले पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोसिंह शेखावत की पुस्तक धरती पुत्र का विमोचन किया था। इस दौरान वसुंधरा राजे ने शायरी से अपने सियासी विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। वसुंधरा राजे ने कहा, जिन पत्थरों को हमनें दी थी धड़कनें, उनको जुबान मिली थी तो हम पर ही बरस पड़े। वसुंधरा राजे का साफ संदेश था कि जिन लोगों को वह राजनीति में लेकर आई है, आज वो उनकी ही खिलाफत कर रहे हैं। उससे वो आहत होने वाली नहीं हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के सियासी तेवरों से साफ है कि वे मुख्यमंत्री पद से कोई समझौता नहीं करेगी।

> सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पास भविष्य की राजनीति के लिए ऐसी कोई रणनीति नहीं है, जिससे वे अपनी पार्टी को मजबूत कर सकें। एक वर्ग के लिए वे बहुसंख्यक वर्ग को निशाना बना रहे हैं।

न माया मिलेगी, न राम...

उप्र विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने महंगाई, कानून व्यवस्था, आवारा पशु जैसे मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन मुद्दों को जनहित का बताते हुए खुद को मजबूत विपक्ष के तौर पर पेश करने के हरसंभव कोशिश की। दरअसल, उप्र विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद अखिलेश यादव का पूरा फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव पर लग चुका है। लेकिन, अखिलेश यादव के लिए 2024 की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। और, इसकी वजह उनके बयान ही बनेंगे।

बीते दिनों अखिलेश यादव ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग पर ही सवाल खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, सपा नेता ने हिंदू संस्कृति और धर्म पर विवादित बयान देते हुए इन्हें कठघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल, अखिलेश यादव ने अयोध्या में बयान दिया था कि हमारे हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो पीपल के पेड़ के नीचे और मंदिर बन गया। अखिलेश के इस बयान को भाजपा वक्त आने पर एक बड़े सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगी। लेकिन, एक बात तय है कि इस बयान से अखिलेश यादव को भाजपा से नाराज वोट मिल जाए, लेकिन हिंदू वोट कभी नहीं मिलेगा।

चुनावी रणनीति हो या राजनीतिक बयान, अखिलेश यादव इन सभी मामलों में टीपू ही नजर आते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि महंगाई, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे लोगों के लिए अहम होते हैं। लेकिन, अखिलेश यादव ये भूल जाते हैं कि उप्र विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान इसी जनता ने उन्हें मंदिर-मंदिर दौड़ते हुए भी देखा था। और, कद्दावर मुस्लिम नेता आजम खान से दूरी की चर्चाएं भी उप्र चुनाव के दौरान खूब रही थीं। आसान शब्दों में कहा जाए, तो समाजवादी पार्टी पर लगने वाले मुस्लिम परस्त पार्टी के ठप्पे को मिटाने के लिए अखिलेश ने भरपूर कोशिशें की थीं। सपा नेता अपनी मुस्लिम समर्थक छवि को खत्म करने के लिए ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद सपरिवार **दर्शन करने आने का वादा** कर रहे थे।

लेकिन, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को लगता है कि हिंदुओं को अपने बयानों से मंदिर के नाम पर प्रगतिवादी साबित कर वह आसानी से हिंदू समुदाय को अपने खेमे में ला सकते हैं। लेकिन, अखिलेश यादव ये समझना नहीं चाहते कि मंदिरों को लेकर ऐसे बचकाने बयान देकर वह हिंदू समुदाय को समाजवादी पार्टी से बिदकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही खुल सका था। लेकिन, अखिलेश यादव का इस मामले में कहना है कि एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थी। भाजपा कुछ भी कर सकती है। भाजपा कुछ भी करा सकती है। एक तरफ अखिलेश यादव ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को कोर्ट का मामला बताते हैं। वहीं, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सवालिया निशान लगाने में जुट जाते हैं।

दरअसल, उप्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार की सत्ता में दोबारा वापसी ने अखिलेश यादव को दुविधा में डाल दिया है। मुस्लिम सपा नेता आजम खान से दूरी बनाने की वजह से मुस्लिम वोट उनसे छिटकने के हालात बनते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव मुस्लिम समुदाय को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश जैसे-तैसे कर रहे हैं। लेकिन, इस कोशिश में वह हिंदू धर्म के लिए ही विवादित बयान दे रहे हैं। ऐसे बयानों से समाजवादी पार्टी को भाजपा से नाराज मतदाताओं का साथ जरूर मिल जाए, लेकिन हिंदू समुदाय का वोट नहीं मिल पाएगा। आसान शब्दों में कहा जाए, तो अखिलेश यादव के लिए दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम का मुहावरा सबसे सटीक नजर आता है।

बीते कुछ दिनों से अखिलेश यादव अपने गठबंधन में अलग-थलग नजर आ रहे हैं। चाचा शिवपाल यादव और कद्दावर मुस्लिम नेता आजम खान की नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। वहीं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के नेता ओमप्रकाश राजभर भी अखिलेश यादव को एसी से निकलकर क्षेत्र में जाने का तंज मार चुके हैं। इतना ही नहीं, विधानसभा के बजट सत्र में जब समाजवादी पार्टी के सारे विधायक हंगामा कर रहे थे। तो, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान, एसबीएसपी नेता ओमप्रकाश राजभर और चाचा शिवपाल सिंह यादव ने इस हंगामे से दूरी ही बनाए रखी। वहीं, ओमप्रकाश राजभर ने तो इसे गलत परंपरा बताकर अखिलेश यादव के सशक्त, सक्रिय और सार्थक प्रतिपक्ष के दावे पर ही सवालिया निशान लगा दिया।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

बढ़ सकती है अखिलेश की मुश्किलें

वैसे, समाजवादी पार्टी के गठबंधन में उठ रहे बगावती सुरों को देखते हुए कहा जा सकता है कि जल्द ही होने वाले राज्यसभा चुनावों में भी अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि राज्यसभा की सीटों के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से भेजे जाने वाले नामों पर सहयोगी दल एकमत नहीं हैं। और, वह राज्यसभा सीटों में भी अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। आजम खान, शिवपाल यादव और जयंत चौधरी की बढ़ रही नजदीकियां काफी हद तक इसी ओर इशारा कर रही हैं। और, ओमप्रकाश राजभर भी अब इन्हीं लोगों के सुर में सुर मिलाते नजर आने लगे हैं।

बिहार की राजनीति में तूफान

मौसम भले सूखे का हो, मगर बिहार की राजनीति में चर्चाओं की नदी हमेशा उफान मारती रहती है। करीब एक महीना पूरा होने जा रहा है। पटना में राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर 28 अप्रैल को इफ्तार पार्टी हुई थी। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और राजश्री यादव की मेजबानी वाले इस आयोजन में जिस गर्मजोशी के साथ नीतीश कुमार शरीक हुए, उससे बिहार की राजनीतिक फिजा गर्म हो गई। तब से अब तक कई ऐसे वाकये हुए, जिनको बिहार की राजनीति में होने वाली किसी बड़ी हलचल का संकेत बताने की होड़ लगी रही। इस बीच नीतीश कुमार ने गत दिनों मगध महिला कॉलेज के एक कार्यक्रम में कहा कि वे जब तक हैं, सबके विकास व कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। उनके जब तक... का भी लोग अपने मन मुताबिक अर्थ निकालने लगे।

बिहार में तमाम ऐसी खबरें, चर्चाएं और अफवाहें पिछले दिनों उड़ती रही हैं, जिनसे आम आदमी के मन में यह सवाल उठा है कि क्या नीतीश कुमार अपनी रणनीति बदलने वाले हैं? इसे समझने के लिए हाल के घटनाक्रमों के साथ ही नीतीश कुमार के संपूर्ण राजनीतिक जीवन पर निगाह डालने की जरूरत होनी चाहिए। पिछले दिनों नीतीश कुमार के करीबी, जदयू के संस्थापकों में शुमार रहे वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने भाजपा के संदर्भ में एक दिलचस्प बयान दिया था।

वशिष्ठ नारायण सिंह हाल तक बिहार जदयू के अध्यक्ष रहे। नीतीश कुमार उन पर विश्वास करते रहे हैं। ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता भी अक्सर वशिष्ठ नारायण की चौखट पर पहुंचकर मार्गदर्शन लेते रहे हैं। राजनीतिक बिरादरी में दादा के तौर पर मशहूर वशिष्ठ नारायण सिंह ने पिछले दिनों कहा कि जदयू और भाजपा के संबंधों पर तो गर्व होना चाहिए। दो दलों के बीच इतने लंबे समय तक समझदारी के साथ गठबंधन चलाना मामूली बात नहीं है। यह बात उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से मुलाकात के ठीक बाद कही। ललन सिंह खुद उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे।

वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात कोई अनोखी बात नहीं है। मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच संवाद तो बना ही रहता है और ऐसा होना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बहुत मजबूती से काम कर रही है। एनडीए में बिल्कुल आल इज वेल है। बिहार में एनडीए के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं। उन्होंने कहा कि जदयू और भाजपा को अपने लंबे संबंधों पर गर्व है। इतने लंबे समय तक एक साथ गठबंधन में सरकार चलाना मौजूदा राजनीतिक हालात में एक रिकार्ड है।

बिहार में कुछ नेताओं की ओर से ऐसे बयान दिए गए हैं कि भाजपा और जदयू के बीच जातिगत जनगणना के मसले पर विरोध है, जबकि राजद और जदयू इस मसले पर साथ हैं। हालांकि, ऐसे दावों का कोई पुख्ता आधार नहीं है। भाजपा के कुछ नेताओं ने जाति जनगणना को गैरजरूरी भले बताया है, लेकिन पार्टी का ऐसा आधिकारिक स्टैंड तो अब तक देखने को नहीं मिला है। पिछली बार इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में भाजपा भी शामिल थी। गत वर्षों में इस मसले पर विधानमंडल में प्रस्ताव पारित हुए तो भाजपा की भी सहमति थी। पिछले दिनों भाजपा की नेता और उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि सरकार जल्द ही जाति जनगणना कराएगी। भाजपा के कई बड़े नेता इस मसले पर कह चुके हैं कि बैठक में फैसला लिया जाएगा।

इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वतंत्र फैसले के लिए जाने जाते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, इसके बारे में बेहद नजदीक के लोगों को भी आखिरी वक्त तक पता नहीं चलता है। उनका राजनीतिक रिकार्ड ऐसा ही रहा है। यही वजह है कि पिछले 16 वर्षों से अधिक समय से बिहार की राजनीति उनके इर्द-गिर्द ही घूमती रही है। बिहार में भाजपा फिलहाल उनका साथ छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती है, राजद के लोग जरूर ऐसी उम्मीद लगाए रहते हैं।

चर्चा है कि 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश कुमार अब उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का पद चाहते हैं। इन पदों पर कुछ ही महीने में चुनाव भी होने हैं। हालांकि नीतीश कुमार इससे इंकार कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि भाजपा को यह पता है कि नीतीश कुमार के बिना लोकसभा चुनाव में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यही कारण है कि बिहार भाजपा के प्रमुख लगातार कह रहे हैं कि 2025 तक नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे।

● **विनोद बक्सरी**

एक बार फिर खुल गया राजद कार्यालय का दूसरा दरवाजा

राजनीति में प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है। प्रतीकों के जरिए सियासत में कई संकेत दिए जाते हैं। यही संकेत इन दिनों बिहार की सियासत में देखने को मिल रही है। आरजेडी प्रदेश कार्यालय का दूसरा दरवाजा सालों के बाद एक बार फिर खोल दिया गया है। आरजेडी कार्यालय का दूसरा दरवाजा खोलने के बाद बिहार के राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म है। आरजेडी कार्यालय में दो दरवाजे हैं गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2, दोनों गेट हमेशा बंद रहते हैं। कोविडकाल में गेट नंबर 2 से प्रवेश के लिए छोटा दरवाजा बनाया गया। अक्सर लोग और तमाम नेता उसी गेट से आते हैं। तेजस्वी, राबड़ी और तेजप्रताप के लिए गेट नंबर 2 खोला जाता रहा है, पर गेट नंबर 1 तभी खोला गया जब राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे हों। बिहार की सियासत में जब 2015 में जब नीतीश कुमार गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े और सरकार बनी उस समय भी दोनों दरवाजे खोले गए थे। इन दिनों बिहार की सियासत में आरजेडी और जेडीयू की नजदीकियों को लेकर सियासत चरम पर है। जातीय जनगणना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार से मुलाकात और उसके बाद शुरू हुई सियासी सरगर्मी ने बिहार के सियासत में बदलाव के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। हालांकि, जेडीयू के नेताओं ने अब तक खुलकर कुछ भी नहीं कहा है।

नई ऊर्जा का संचार

भारत और नेपाल के गहरे रिश्ते की उम्मीद बढ़ी

भारत और नेपाल, दोनों समान संस्कृति एवं मूल्यों वाले पड़ोसी होने के बावजूद आज तक संबंधों के एक निर्धारित दायरे से बाहर नहीं निकल पाए हैं, लेकिन देउबा के भारत दौरे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा के बाद स्थिति बदलती नजर आ रही है। भारत और नेपाल में जैसे गहरे रिश्ते होने चाहिए, उनकी उम्मीद अब बढ़ रही है। ध्यान रहे कि 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पांचवीं नेपाल यात्रा थी। यह पहला अवसर था, जब दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच डेढ़ माह से भी कम समय में दूसरी बार द्विपक्षीय वार्ता हुई। नेपाल यात्रा के दौरान जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की धार्मिक कूटनीति को चुनौती देने का प्रयास किया है, वह दोनों देशों के रिश्तों में मील का पत्थर साबित होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा दोनों देशों के संबंधों में नई ऊर्जा का संचार करने में सफल रही। वह बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर लुंबिनी गए। इससे कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भी जब भारत आए थे तो काशी गए थे। मोदी और देउबा की यात्राओं के लिए जिस तरह समय और स्थान का निर्धारण किया गया, उसे महज संयोग नहीं कहा जा सकता। जिस तरह दोनों देशों ने अपने नेताओं के दौरे में धार्मिक महत्व के नगरों को शामिल किया, उसका असल उद्देश्य बहुत गहरा और दूरगामी परिणाम देने वाला है। भारत वास्तव में नेपाल का बहुत पुराना सहयोगी रहा है। दोनों के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता है।

सांस्कृतिक रूप से भी दोनों के बीच खासे गहरे संबंध हैं। इसके अलावा धार्मिक-सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारत का नेपाल के साथ एक अटूट रिश्ता है, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह चीन भारत के पड़ोस में अपनी पैठ जमाने की कोशिशों में जुटा हुआ है, उससे भारत के सामरिक हलकों में कुछ सवाल उठते रहे हैं। यह बहुत स्वाभाविक भी है। यह किसी से छिपा नहीं कि चीन नेपाल की ढांचागत परियोजनाओं में काफी रुचि ले रहा है।

नेपाल में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए अब वह निवेश के साथ-साथ धार्मिक कूटनीति का भी सहारा ले रहा है। महात्मा बुद्ध के कारण लुंबिनी दुनियाभर के बौद्ध अनुयायियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। बौद्ध धर्मावलंबियों को आकर्षित करने के लिए चीन पिछले एक दशक से लुंबिनी में निवेश कर रहा है। उसने वहां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया है। अब वह लुंबिनी में विश्व शांति केंद्र की स्थापना कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए यह जरूरी हो गया था कि वह चीन की इस नीति की प्रभावी काट करके लुंबिनी में अपना प्रभाव बढ़ाए। मोदी की लुंबिनी यात्रा को इसी कवायद से जोड़कर देखा जा रहा है। इस यात्रा के दौरान मोदी ने लुंबिनी में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज की नींव रखी।

मोदी ने अपने लुंबिनी दौरे की शुरुआत माया देवी मंदिर में दर्शन के साथ की। मान्यता है कि यहीं महात्मा बुद्ध का सिद्धार्थ के तौर पर जन्म हुआ था। मोदी-देउबा द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत द्वारा नेपाल में संचालित की जा रही परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने के लिए उनकी प्रगति की समीक्षा की गई। भारत इस समय नेपाल में बिजली परियोजनाओं, संचार एवं डिजिटल समेत कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। इसके अलावा भारत और नेपाल के बीच बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भी समझौता हुआ। भारत और नेपाल के विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच कई समझौते हुए। उच्च शिक्षा के लिहाज से ये समझौते काफी अहम माने जा रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच सुरक्षा संस्थाओं के मामले में बेहतर तालमेल और सहयोग के मुद्दे पर भी वार्ता हुई। ध्यान रहे कि पिछली ऐसी वार्ता में मोदी ने साफ कहा था कि भारत-नेपाल खुली सीमाओं का अवांछित तत्वों द्वारा किए जा रहे दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा संस्थाओं के बीच सहयोग होना चाहिए।

2015 में नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार आने के बाद भारत-नेपाल संबंधों पर संशय के जो बादल मंडरा रहे थे, वे तब और गहरा गए थे, जब तत्कालीन नेपाल सरकार ने भारत विरोधी रवैया अपना लिया था। नवंबर 2019 में भारत-नेपाल संबंधों में उस वक्त तनाव उत्पन्न हो गया था जब नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कालापानी इलाके पर कहा था कि भारत को इस क्षेत्र से अपनी सेना हटा लेनी चाहिए। 2020 में भारत-नेपाल रिश्ते उस वक्त और बिगड़ गए, जब ओली ने कालापानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा जैसे विवादित क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा बताने वाला नक्शा जारी किया। ये सभी इलाके भारत की सीमा में हैं।

भारत शुरू से ही इस नक्शे को खारिज करता रहा है। सीमा संबंधी मुद्दे उछालने के अलावा ओली ने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे कई बयान दिए, जिनसे भारत-नेपाल रिश्तों में खटास उत्पन्न हुई। जुलाई 2020 में ओली ने भगवान श्रीराम की जन्मस्थली अयोध्या पर प्रश्न उठाते हुए कहा था कि भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण करने के लिए वहां फर्जी अयोध्या का निर्माण कराया है। जबकि असली अयोध्या तो नेपाल के बीरगंज में है। इसी प्रकार जब दुनिया कोरोना संकट से गुजर रही थी, तब भी ओली ने भारत के खिलाफ विवादित बयान दिया। वन बेल्ट-वन रोड परियोजना में चीन का सहयोगी होने और व्यापारिक हितों के कारण भी नेपाल का झुकाव चीन की ओर है। 2019 में काठमांडू में हुए बिम्सटेक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्य देशों के सामने सैन्य अभ्यास का प्रस्ताव रखा था, लेकिन चीन के दबाव के चलते नेपाल ने सैन्य अभ्यास में भाग लेने से इनकार कर दिया था। जबकि उससे कुछ समय पहले ही नेपाल ने चीन के साथ सैन्य अभ्यास किया था।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

क्वाड की चुनौतियां

टोक्यो में संपन्न हुई क्वाड शिखर बैठक में यूक्रेन युद्ध से लेकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र का मुद्दा छाया रहना बड़े देशों की मुश्किलों को बताने के लिए काफी है। सम्मेलन में अमेरिका सहित दूसरे सदस्य देशों के रुख से यह भी साफ हो गया कि सभी देश आने वाले वक्त में ऐसे आर्थिक और व्यापारिक गठजोड़ बनाने के पक्षधर हैं जो उन्हें बदलती वैश्विक व्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने की ताकत दे सकें। इसीलिए अमेरिका की अगुवाई में हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचे की नींव रख दी गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि अमेरिका की इस कवायद का मकसद भी चीन की घेराबंदी ही है। वैसे भी क्वाड का गठन चीन से निपटने के लिए ही मुख्य रूप से हुआ है। शिखर बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुले शब्दों में चीन को भले न ललकारा हो, पर हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और उसे एक स्वतंत्र व खुला क्षेत्र बनाने को लेकर जो कदम उठाए हैं, वे भविष्य की रणनीतियों का संकेत देते हैं। जाहिर है, आने वाले वक्त में अमेरिका चीन को सिर्फ सैन्य मोर्चों पर ही नहीं, व्यापार के मोर्चे पर भी पटखनी देने के रास्ते पर बढ़ रहा है। इसीलिए चीन ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे अमेरिका की उकसाने वाली रणनीति करार देने में जरा देर नहीं लगाई।

क्वाड बैठक से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात भी भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्तों को रेखांकित करती है। यूक्रेन के मसले पर भारत अमेरिकी **गुट में भले शामिल** न हो, फिर भी अमेरिका भारत को साथ लेकर चल रहा है तो इसका मतलब यही माना जाना चाहिए है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में वह भारत की अहमियत समझ रहा है। इसीलिए दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकियों पर भारत-अमेरिकी पहल की शुरुआत की, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग, 5जी, 6जी, जैव तकनीक, अंतरिक्ष और सेमी कंडक्टर जैसे बड़े क्षेत्रों में मिलकर काम होना है। भारत ने भी रक्षा क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों को न्यौता दिया है। इसके अलावा जलवायु संकट, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी एक दूसरे का सहयोग करने की बात है। जाहिर है, अमेरिका और भारत एक-दूसरे के लिए उपयोगी तो हैं ही, अपरिहार्य भी हैं। आतंकवाद के मसले पर भी क्वाड देश भारत के साथ खड़े हैं। पर हैरानी की बात यह है कि अमेरिका जैसा दोस्त होते हुए भी भारत के प्रति पाकिस्तान की आतंकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है, न ही पाकिस्तान ने आज तक किसी भी वांछित आतंकी को भारत के हवाले किया।

टोक्यो में आयोजित क्वाड देशों का तीसरा शिखर सम्मेलन विश्व व्यवस्था के निर्धारण में हिंद-प्रशांत की केंद्रीय भूमिका की पुष्टि का प्रतीक है। इस समय रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पूर्वी यूरोप पर टिका हुआ है। ऐसी स्थिति में क्वाड के चारों देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र प्रमुखों का जापान में बैठक करना और एशिया के भविष्य की रूपरेखा पर रणनीति बनाना यही संकेत करता है कि एशिया में शक्ति संतुलन ही अंतत: वैश्विक भू-राजनीति एवं भू-अर्थनीति में निर्णायक सिद्ध होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति यही रही कि दुनिया के तीन प्रमुख क्षेत्रों में किसी भी प्रतिद्वंद्वी को हावी नहीं होने देना है। ये प्रमुख क्षेत्र रहे यूरोप, पश्चिम एशिया और पूर्वी एशिया। इसके पीछे अमेरिका की यह सोच रही कि इनमें से कहीं भी अगर शक्ति संतुलन अमेरिका के विपरीत गया तो उसके लिए वैश्विक महाशक्ति बने रह पाना संभव नहीं होगा। बाइडेन प्रशासन द्वारा 2021 में जारी राष्ट्रीय सुरक्षा सामरिक मार्गदर्शन में यही दोहराया गया है। उससे यही स्पष्ट होता है कि अमेरिकी सुरक्षा के लिए दुनिया के प्रमुख क्षेत्रों पर विरोधियों का आधिपत्य होने से रोकना अनिवार्य है।

पश्चिम एशिया और यूरोप में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सके। ईरान और रूस जैसे देश अमेरिका को परेशान करते आए हैं, लेकिन उनमें उतना आर्थिक एवं सैन्य बल नहीं, जिससे वे अमेरिका को मात दे सकें। केवल पूर्वी एशिया में स्थित चीन ही अमेरिका को चुनौती देने में सक्षम दिखाई पड़ता है और वह इसके लिए कमर भी कस रहा है। अमेरिका भी इससे भलीभांति अवगत है। यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र ही इक्कीसवीं सदी के भविष्य को परिभाषित करेगा और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन इस मामले में अमेरिकी नेतृत्व एवं भागीदारी को लेकर प्रतिबद्ध हैं। उल्लेखनीय है कि क्वाड के साथ ही अमेरिका एक और महत्वाकांक्षी पहल कर रहा है। इसे हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचा नाम दिया गया है। इसमें अमेरिका, भारत, आस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं।

● **कुमार विनोद**

इस समय क्वाड की अहम भूमिका

क्वाड के चार मूल सदस्य ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बहुआयामी क्षमता रखते हैं। ऐसे में उन्हें स्वाभाविक रूप से इस इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का साझा नेतृत्व करना होगा। ये चारों देश पहले ही इन्फ्रास्ट्रक्चर, वैक्सीन, आपूर्ति श्रृंखला, सामरिक साझेदारी और सेमीकंडक्टर आदि क्षेत्रों में समझौते कर चुके हैं और उनमें से कुछ पर काम भी शुरू हो चुका है। ऐसे में साझेदारी के इस दायरे को बढ़ाना और नए सहयोगियों को उसमें जोड़ना ही बुद्धिमत्ता होगी। अमूमन यही माना जाता है कि जिन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक ढांचों में अधिक हितधारक होते हैं, वहां समन्वय, सहमति बनाकर अपेक्षित कार्य को शीघ्रता से संपादित करना संभव नहीं होता। इसलिए इस फ्रेमवर्क में विभिन्न पक्षों को देखते हुए उसकी कार्यसंस्कृति को बेहतर बनाने के उपाय करने होंगे। बाइडेन प्रशासन कहता आ रहा है कि उसका लक्ष्य यह सिद्ध करना है कि लोकतांत्रिक देश वादों और अपेक्षाओं पर खरे उतर सकते हैं और तानाशाही वाले देशों से बेहतर प्रदर्शन दिखा सकते हैं। क्वाड सदस्य इसे तभी चरितार्थ कर पाएंगे जब वे मिलकर एशिया के चुनिंदा संकटग्रस्त देशों को संभाल सकें। रूस-यूक्रेन संकट से क्वाड का बहुत सरोकार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले कुछ अवसरों पर कह भी चुके हैं कि हमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने मूल उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

दमनकारी पाटों में पिसती महिलाएं

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार 'विकास' और 'प्रगति' के साथ स्त्रियों के प्रति अपराध में 7 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। यहां भी विशेषण महत्वपूर्ण हो जाते हैं, दलित स्त्रियों से बलात्कार के मामलों में केवल 2 फीसदी अपराधियों को दंड मिलता है, जबकि अन्य में यह 25 फीसदी है। विशेषण संज्ञा पर हावी हो चले हैं। दलित, अल्पसंख्यक, अश्वेत, पढ़ी-लिखी, कटे बालों वाली या हमजिंसी जैसे शब्द स्त्री और स्त्री विमर्श को परिभाषित करने लगे हैं। ये तमाम विभाजनकारी और गैर-बराबरी के विशेषण पुरुषों द्वारा पुरुषों की दुनिया के लिए रचे गए, परंतु स्त्री और स्त्री जीवन की सीमाओं को गढ़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्त्रियां इन दमनकारी पाटों में सबसे ज्यादा पीसी जाती हैं। स्त्री सशक्तिकरण की मुहिम भी स्त्री के लिए न होकर राष्ट्र या समाज की प्रगति के लिए ज्यादा चिंतित हो जाती है। स्त्री के पढ़ने को परिवार, समाज और देश के लिए आवश्यक करार दिया जाता है। शायद परिवार या देश की चिंता न हो तो स्त्री का पढ़ना अभी भी किरकिरी का ही मामला है। स्वतंत्र स्त्री या भिन्न सोचने वाली स्त्री अभी भी हमारे समाज में नाभिकीय अस्त्र के मुकाबले अधिक खतरनाक मानी जाती है। सिमोन दा बुवार का यह कथन कि 'स्त्रियां पैदा नहीं होतीं, बल्कि गढ़ी जाती हैं', उस विद्रूप को इंगित करता है जहां जनाना क्या है, यह तय करने का विशेषाधिकार पुरुष के पास है।

स्त्रियों के प्रति हिंसा अब सांख्यिकी के दस्तावेज बनकर रह गई है। प्रतिक्षण कोई न कोई स्त्री हिंसा का शिकार होती है, चाहे वह गर्भ में हो, गोद में हो, घर में, दफ्तर में, अस्पताल में, वयोवृद्ध हो, कामगार या फिर गृहिणी। मानसिक, शारीरिक और यौन हिंसा से अभिशप्त स्त्री अभी भी किसी अंबेडकर की बाट जोह रही है। आधे आसामान और आधी धरती के मालिकान का हक और सपना उस हकीकत से लांछित है जहां दुनियाभर में तीन में से एक स्त्री यौन हिंसा का शिकार है। भारतीय स्त्री की दशा और भी दयनीय है जहां हर घंटे औसतन चार स्त्रियां बलात्कार का शिकार हो रही हैं। इनमें अगर दहेज, मानसिक प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और कन्या भ्रूण हत्या के मामले जोड़ दिए जाएं, तो 62 प्रतिशत स्त्रियां सांस्थानिक पितृसत्ता के चलते त्रस्त हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार 'विकास' और 'प्रगति' के साथ स्त्रियों के प्रति अपराध में 7 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। यहां भी विशेषण महत्वपूर्ण हो जाते हैं, दलित स्त्रियों से बलात्कार के मामलों में केवल दो प्रतिशत अपराधियों को दंड मिलता है, जबकि अन्य में यह 25 प्रतिशत है। यह उन आंकड़ों का हवाला है जो रिकार्ड हुए, अन्यथा यह लिंग आधारित हिंसा की उस विकराल समस्या के संकेतक मात्र है, जिसमें लोक-लाज के कारण माना जाता है कि 99 प्रतिशत मामले दर्ज ही नहीं होते। यह हिंसा केवल पुरुष और स्त्री के जैविक स्तर पर भिन्न होने का द्वंद्व न होकर एक सांस्कृतिक विरचना है, जिसके अनुसार स्त्रियां आंगन में और गाय खूंटे में ही सुरक्षित है। यह सार्वजनिक 'देशकाल' में स्त्री की स्वतंत्रता को हस्तक्षेप मानने जैसा है। स्त्री को आर्थिक रूप से उत्पादनशील न समझना और न बनने देने का प्रयास है।

स्वतंत्र और सशक्त स्त्री पुरुषों की दुनिया में दखल मात्र है, सहनीय नहीं है, इसलिए दंडनीय है ताकि उसे अपना स्थान पता रहे। धर्मगत विषयों में भी स्त्री को कोई निर्णय करने संबंधी अधिकार नहीं है। हालांकि सारे धार्मिक मूल्यों की संवाहक स्त्री ही है। सारे व्रत, तीज, त्योहार, रस्मो-रिवाज उसे ही निभाने हैं, परंतु धर्म स्थलों में प्रवेश और अंतिम संस्कार को लेकर वर्जनाएं हैं। दुनिया के प्रत्येक धर्म में स्त्री को दोयम दर्जे का ही माना गया है। लगभग सभी धर्मों में इस दुनिया के बनने के चरणबद्ध क्रम में स्त्री हर कथोपकथा में हमेशा दूसरे नंबर पर है। जैविक विकास के क्रम में पहले पुरुष आया या स्त्री, यह एक बेमानी सवाल है क्योंकि यहां पहले आना बेहतरी का सूचक नहीं है। इस क्रम में मानव जाति का प्रादुर्भाव समझा जाता है कि पुरुष और स्त्री एक ही साथ बने होंगे तो हर संदर्भ और प्रसंग में स्त्री का पिछड़ जाना सामाजिक वर्चस्व और संघर्ष की ही गाथा रही होगी। स्त्री को प्रत्येक कालखंड में बंधक रखने और बंधन में रहने के लिए धर्म सम्मत शास्त्र रचे गए, परंपराएं बनाई गईं और संबंधों के परिमाण में शील और कर्तव्य के दायरे रचे गए। आदर्श स्त्री की परिकल्पना चाहे वैदिक युगीन हो अथवा उत्तर-आधुनिक, हमेशा ही पुरुषवादी समाज के लिए बुनी गई। आधुनिक नव-उदारवादी **अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक** मूल्यों ने भी स्त्रीत्व को देह धरे का दंड ही माना। इसके लिए फिर उसने विश्व सुंदरी प्रतियोगिताएं आयोजित कीं और स्त्री केंद्रित साहित्य और सिनेमा को आलोचकों से अनुशंसा तो दिलाई, पर उसे 'मुख्यधारा' से परे ही रखा।

विज्ञापनों की दुनिया में भी स्त्री केंद्र में रही। स्त्री के लिए उपयोगकारी वस्तुओं के विज्ञापनों में भी स्त्री मात्र देह की तरह दर्शायी जाती है। ऐसे समय में स्त्री की मुक्ति-गाथा और स्त्री विशुद्ध स्त्री बने की परिकल्पना बड़ी जीवटता का मामला है। द्वंद्व स्त्री एकता को लेकर इस समाज को और विखंडित करते हैं। दुनियाभर की स्त्रियां एक हों अथवा स्त्रियां दुनिया को एक करो- जैसे नारे अभी भी बड़ी चतुराई से विभाजित कर दिए जाते हैं। आतंकवादी और सिपाही की मां होने के भिन्न सौंदर्यबोध रचे जाते हैं, पुरुषों की दुनिया की लड़ाई का जिम्मेदार स्त्री को ही बताया जाता है।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

वीरांगना होने के बाद भी प्रताड़ना

दलित, अश्वेत, अल्पसंख्यक स्त्रियों के भिन्न अधिकार और कर्तव्य बुने जाते हैं। इन विभाजनों को भले ही स्त्री ने जन्म न दिया हो, इन्हें पोसने और संरक्षण की जिम्मेदारी भी स्त्री की ही है। स्त्री के वीरांगना होने का प्रमुख प्रमाण उसके द्वारा वीर पुत्रों को जन्म देना ही है। गांधारी और कुंती के चरित्र चित्रण उनके द्वारा जन्मे पुत्रों के आधार पर ही होना तय है। किसकी बेटी, किसकी बहन से लेकर किसकी स्त्री या किसकी मां, यही स्त्री जीवन की समीक्षा की कसौटी है। इन सब संरचनाओं के विरुद्ध जाकर जिन स्त्रियों ने पुरुषों की दुनिया में दखल दिया, अधिकतर को पुरुषों ने खलनायिका समझा या नजरअंदाज किया या अपवाद ही समझा। इसके बावजूद स्त्री ने अपनी संघर्ष यात्रा को जारी रखा। संयुक्त अरब अमीरात की सरा-अल-अमीरी ऐसी ही मिसाल हैं जो इस मुल्क की उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं और जिन्होंने उस पूरी परियोजना का नेतृत्व भी किया जिसने हाल में मंगल ग्रह पर एक उपग्रह को सफलतापूर्वक पहुंचाया था। जिस वैज्ञानिक समूह ने यह सफलता हासिल की, उसमें 80 प्रतिशत स्त्रियां ही हैं।

कपटी झूठ बोलते हैं और झूठ ही ओढ़ते हैं

रामचरित मानस के अरण्यकांड में रावण और मारीच का प्रसंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में समझाया है कि 9 तरह के लोगों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। इन लोगों की कोई भी बात तुरंत मान लेने में ही बुद्धिमानी है, वरना आप मुसीबत में फंस सकते हैं। इस प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि न चाहते हुए भी मारीच को रावण की बात माननी पड़ी और रावण के कहने पर स्वर्ण मृग बनना पड़ा जबकि मारीच जानता था कि ऐसा करने पर श्रीराम उसे मार देंगे।

सीता का हरण करने के लिए रावण मारीच के पास पहुंचा और कहा कि तुम छल-कपट करने वाला स्वर्ण मृग बनो, ताकि मैं सीता का हरण कर सकूं। तब मारीच ने रावण को समझाया कि वह श्रीराम से बैर न करें। मारीच की बातें सुनकर रावण क्रोधित हो गया एवं खुद के बल और शक्तियों का घमंड करने लगा। तब मारीच को समझ आ गया कि सीता हरण के लिए उसकी मदद करने में ही भलाई है। रावण के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं श्रीराम के हाथ मरूं, जिससे मेरा उद्धार हो जाएगा। इस पर तुलसीदास जी ने लिखा...

तब मारीच हृदयं अनुमाना।
नवहि बिरोधें नहिं कल्याना।।
सस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी।
बैद बंदि कबि भानस गुनी।।

यानी इस दोहे में मारीच की सोच बताई गई है कि हमें किन लोगों की बातों को तुरंत मान लेना चाहिए। अन्यथा प्राणों का संकट खड़ा हो सकता है। इस दोहे के अनुसार शस्त्रधारी, हमारे राज जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान व्यक्ति, वैद्य, भाट, कवि और रसोइयां, इन लोगों की बातें तुरंत मान लेनी चाहिए। इनसे कभी विरोध नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारे प्राण संकट में आ सकते हैं।

तुलसीदास जी ने लिखा है...

खलन्ह हृदयं अति ताप बिसेषी।
जरहिं सदा पर संपति देखी॥
जहं कहुं निंदा सुनहिं पराई।
हरषहिं मनहुं परी निधि पाई॥

यानी दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे दूसरों की संपत्ति (सुख) देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहां कहीं दूसरे की निंदा सुनते हैं, वहां ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे कोई रास्ते में पड़े खजाने को पाकर खुश होता है।

रामचरितमानस के बालकाण्ड में तुलसीदास जी अपने अवगुणों को विराम देते हुए रामचरित्र में उतरने की सलाह देते हैं। जो लोग बाहर से अच्छे बनते हैं और भीतर कपटी होते हैं कलियुग में पापी होते हैं। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि राम नाम भजते हुए वेदमार्ग पर रहना चाहिए।

जे जनमे कलिकाल कराला ।
करतब बायस बेष मराला।।
चलत कुपंथ बेद मग छांड़े।
कपट कलेवर कलि मल भांड़े।।

जो कलियुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौए के समान और वेष हंस के समान है, जो वेदमार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलियुग में पापों के पात्र समान हैं।

बंचक भगत कहाइ राम के।
किंकर कंचन कोह काम के।।
तिन्ह महं प्रथम रेख जग मोरी।
धींग धरमध्वज धंधक धोरी।।

जो श्रीराम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो झूठ में ही राम-राम भजने वाले, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है।

जौं अपने अवगुन सब कहऊं ।
बाढ़इ कथा पार नहिं लहऊं।।
ताते मैं अति अलप बखाने।
थोरे महुं जानिहहिं सयाने।।

यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे।

समुझि बिबिधि बिधि बिनती मोरी।
कोउ न कथा सुनि देइहि खोरी।।
एतेहु पर करिहहिं जे असंका।
मोहि ते अधिक ते जड़ मति रंका।।

जो व्यक्ति दूसरों की धन-संपदा और सम्मान को देखकर ईर्ष्या यानी जलन की भावना रखता है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। जलन की भावना रखने वाला व्यक्ति दूसरों को धोखा देता और छल-कपट करने वाला बन जाता है। रावण भी भगवान राम के प्रति ईर्ष्या रखता था, जिसके चलते उसका अंत भयानक हुआ। कौरव भी जीवनभर पांडवों के प्रति जलन की भावना रखते रहे। मद यानी अहंकार में इंसान अपना सबकुछ दांव पर लगा देता है। अंहकारी व्यक्ति के लिए कोई सीमा नहीं होती, वह अच्छे-बुरे में अंतर करना बंद कर देता है। जिसकी वजह से वह अपने परिवार को भी कष्ट पहुंचाता है। इससे ना सिर्फ मान-सम्मान में कमी आती है बल्कि वह किसी भी सलाह को शत्रुता पूर्ण मानता है। रावण को अपनी शक्तियों पर इतना अंहकार था कि उसने भगवान को ही चुनौती दे दी थी।

निर्मल मन जन, सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल, छिद्र न भावा।

ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम सरेआम नियमों की अवहेलना करें, प्राकृतिक नियमों को ताक पर रखकर खुलकर स्वेराचार (मनमानी करें), प्राकृतिक संसाधनों का निर्मम दोहन करें, पोषण और शोषण रंच मात्र भी न करें और वहां पहुंच जाए, अपना कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाते-बढ़ाते। वही ईश्वर को प्राप्त होगा एकांत में भी जो कभी भ्रष्ट नहीं होता, जिसने अपना मनो राज्य जीत लिया है। जिसके मन में कोई व्यतिकरण छल कपट नहीं है जो वीत राग हो गया जिसकी आसक्ति समाप्त हो गई है। जिनके स्वप्न में भी राग द्वेष ठहरता नहीं है, बाईपास हो जाता है, जो एकांत में भी अपने जीवन मूल्य और सम्यक ज्ञान, अपनी नैतिकता से विरक्त नहीं होता है। अपना शील कायम रखता है। ऐसे निश्छल प्राणियों को ही प्रभु की प्राप्ति होती है। वे ही हमारा आदर्श हैं। उन्हीं का यशोगान होता है उन्हीं की गाथाएं गाई जातीं हैं। हर युग में ऐसे प्राणि वंद्य हैं।

● **ओम**

मदद

चिलचिलाती धुप से जूझती नेहा अपनी स्कूटी से घर जा रही थी। रास्ते में इक्का-दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक उसकी नजर सड़क किनारे पड़े एक व्यक्ति पर पड़ी, वह पहले तो झिझकी और फिर उसने स्कूटी किनारे खड़ी कर दी।

उस व्यक्ति को पास जाकर देखा तो किसी दुर्घटना का कोई निशान नजर नहीं आया। किसी तरह उसने उस व्यक्ति को पास के पेड़ तक लगभग घसीटते हुए पहुंचाया। फिर अपनी पानी की बोतल से पानी के छींटें उसके मुंह पर मारे। पानी पड़ते ही वह व्यक्ति कुनमुनाया। नेहा ने जैसे-तैसे उसे जबरदस्ती पानी पिलाया। अब उस व्यक्ति की तंद्रा लगभग टूट चुकी थी।

नेहा को आत्मसंतोष हुआ कि उसकी छोटी सी मदद किसी के जीवन में हिलोरें पैदा कर गई। उस व्यक्ति ने नेहा के पैरों में सिर रख दिया। नेहा ने उसको कंधों के सहारे सीधा किया। ये क्या कर रहे हैं आप?

आपने हमारी जान बचाई है बेटा। साक्षात ईश्वर बनकर आई हो। वरना मेरी मौत ही हो जाती। प्यास के कारण मैं पिछले दो घंटे से पड़ा था, पर किसी ने मदद तो दूर झांकना भी मुनासिब न समझा।

अरे नहीं। मैंने तो बस मानव धर्म का पालन किया है। बाकी ईश्वर की इच्छा, अब आप ठीक महसूस कर रहे हों, तो मुझे इजाजत दीजिए। नेहा ने सलीके से कहा।

हां बेटा! अब मैं ठीक हूं। तुम्हारा कर्ज है मुझ पर। ईश्वर ने चाहा तो जरूर उतार दूंगा। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो हमारे पिता जैसे हैं, फिर आपने मुझे बेटा कहकर सारा कर्ज उतार दिया। अपना ध्यान रखा कीजिए। नेहा की आंखों में नमी आ गई।

नेहा ने उस व्यक्ति के पैर छुए और अपनी स्कूटी पर सवार हो आगे बढ़ गई। उस व्यक्ति को जब तक वो दिखाई दी, उसका हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उसे दुआएं दे रहा था। आंखों में आंसू अब भी बह रहे थे।

- सुधीर श्रीवास्तव

भले ही सुंदर वस्त्र तुम्हारे

गोल-गोल गोलाइयां सुंदर,
गहराइयों में समंदर हो।
भले ही सुंदर वस्त्र तुम्हारे,
तुम उनसे भी सुंदर हो।।
फोटो बहुत देखे हैं हमने।
वार तुम्हारे सहे हैं हमने।
चाहकर भी चाह न सकते,
विश्वासघात देखें हैं हमने।
बाहर से ना दिखलाओ केवल,
दिखलाओ कैसी अंदर हो?
भले ही सुंदर वस्त्र तुम्हारे,
तुम उनसे भी सुंदर हो।
जहरीली सोने की गागर।
बन ना सकी प्यार का सागर।
अपराधी को छोड़ के जाओ,
बन नहीं सकते, अब कभी नागर।
सुंदरता बाहर की केवल,
अंदर से चंचल बंदर हो।
भले ही सुंदर वस्त्र तुम्हारे,
तुम उनसे भी सुंदर हो।।
हमने तो था सब कुछ सौंपा।
तुमने दिल में छुरा ही भौंका।
नहीं अभी भी नफरत हमको,
किंतु बन नहीं सकतीं लोपा।
होटल की हो तुम आकर्षण,
ना गुरूद्वारे की लंगर हो।
भले ही सुंदर वस्त्र तुम्हारे,
तुम उनसे भी सुंदर हो।।

- डॉ. संतोष गौड़ राष्ट्रप्रेमी

साहस की आरती

राजेश बाबू ने संध्या आरती के लिए थाल सजाया ही था कि बेटी नीति ने टोका, पापा, आरती कीजिए लेकिन घंटी मत बजाइएगा।

क्यों भई? मुस्कुराकर राजेश बाबू ने पूछा, तुमको तो घंटी की आवाज अच्छी लगती है।

हां लेकिन अभी बाहर का माहौल सही नहीं न! दंगा किसी तरह शांत हुआ है लेकिन फिर भड़क सकता है, हमारे परिवार भी यहां बस एक तिहाई हैं। एक तिहाई हैं तो क्या करें? राजेश बाबू बोले, हम डर जाएं तो हम भी उन आततायियों जैसे ही न हो जाएं! हमारी हिम्मत के बल पर ही तो हम, हम बने हुए हैं!

हां पापा, वो सब ठीक है लेकिन मेरे सारे सोशल मीडिया के फ्रेंड्स जो शहर के बाहर हैं, कह रहे थे कि हम आप लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे! उनकी ऐसी बातें सुनकर डर लगने लगा है। बेटी, जब तुम्हारे उतने दोस्त हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो फिर हमको डरने की क्या जरूरत? कहते हुए राजेश बाबू के हाथ घंटी बजाने लगे और मुख आरती गाने लगा।

- कुमार गौरव अजीतेन्दु

डेब्यू सीजन में ही जीत

कप्तान हार्दिक पंड्या के हरफनमौला प्रदर्शन से गुजरात टाइटंस ने फाइनल में राजस्थान रॉयल्स पर 7 विकेट से एकतरफा जीत दर्ज की। इसके साथ ही उसने अपने पहले ही सीजन में इंडियन प्रीमियर लीग खिताब अपने नाम कर लिया। 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर ओबेड मैकॉय को छक्का जड़कर शुभमन गिल ने जब जीत की औपचारिकता पूरी की तो एक लाख से अधिक दर्शकों की तालियों और शोर से नरेंद्र मोदी स्टेडियम गूंज उठा। एक नई नवेली टीम को दुनिया की इस सबसे लुभावनी क्रिकेट लीग का सिरमौर बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो उसके 'कैप्टन कूल' हार्दिक पंड्या को।

खचाखच भरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात के गेंदबाजों ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स को 9 विकेट पर 130 रन पर रोक दिया। टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर जोस बटलर को कप्तान हार्दिक पांड्या ने 39 रन पर आउट किया। हार्दिक ने अपने चार ओवरों में 3/17 के आंकड़े के साथ शानदार गेंदबाजी की, जबकि राशिद खान ने भी 4 ओवर में 1/18 का शानदार प्रदर्शन किया। जवाब में गुजरात ने शुरुआत में जल्द दो विकेट खो दिए। लेकिन अंत में 11 गेंद शेष रहते 131 रनों के लक्ष्य को हासिल कर लिया। राजस्थान की टीम भले ही मैच हार गई लेकिन जोस बटलर और युजवेंद्र चहल ने ऑरेंज और पर्पल कैप अपने नाम किया। इंग्लैंड के क्रिकेटर ने कुछ छह अवार्ड अपने नाम किए।

आखिर गुजरात टाइटंस को जीत दिलाने में किसने अहम रोल निभाया। पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो सिर्फ 5 ही खिलाड़ी सभी 16 मैच में उतरे। कप्तान पंड्या ने भी चोट के कारण एक मैच नहीं खेला था। टीम ने टूर्नामेंट में कुल 18 खिलाड़ियों को मौका दिया। वहीं 5 खिलाड़ी एक भी मैच नहीं खेल सके। बतौर कोच आशीष नेहरा ने अपने शांत स्वभाव के कारण सभी का दिल जीता। मैच के बाद शुभमन गिल ने कहा कि हमारी कोई भी मीटिंग 8 मिनट से अधिक नहीं चली। यानी टीम मैनेजमेंट को अपने खिलाड़ियों पर भरोसा था और सभी प्लेयर्स को अपने रोल के बारे में जानकारी थी।

गुजरात टाइटंस की ओर से डेविड मिलर, शुभमन गिल, राहुल तेवतिया, राशिद खान और मोहम्मद शमी ने पूरे 16-16 मैच खेले। मिलर ने 2 अर्धशतक के सहारे 481 रन बनाए। यह उनका आईपीएल का बेस्ट प्रदर्शन है। वहीं गिल ने 4 अर्धशतक के सहारे 483 रन का योगदान दिया। तेवतिया ने 217 रन बनाए। राशिद खान ने 91 रन बनाए और बतौर लेग स्पिनर 19 विकेट भी झटके। उनकी इकोनॉमी सिर्फ 6.59 की रही, जो बेहतरीन है। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टीम की ओर से सबसे अधिक 20 विकेट लिए। 25 रन देकर 3 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा। यह उनका आईपीएल का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। इससे पहले उन्होंने 2020 में भी 20 विकेट झटके थे।

सीजन का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर: राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर- बटलर ने इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के फाइनल तक राजस्थान के सफर में एक बड़ी भूमिका निभाई है। इस सीजन में उन्होंने कुल 863 रन बनाए।

ऑरेंज कैप: राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर- 17 मैचों में 149 के स्ट्राइक रेट से 863 रन बनाकर बटलर ने ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाया।

पर्पल कैप: राजस्थान रॉयल्स के युजवेंद्र चहल- आईपीएल 2022 में लेग स्पिनर ने 27 विकेट विकेट लिए। इस दौरान 7.75 की इकॉनमी और 19.51 का औसत रहा। उन्होंने पूरे सत्र में राजस्थान के गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व किया।

इमर्जिंग प्लेयर ऑफ आईपीएल 2022 अवॉर्ड: सनराइजर्स हैदराबाद के उमरान मलिक- युवा तेज गेंदबाज ने आईपीएल 2022 में 14 मैचों में 20.18 की औसत और 9.03 की इकॉनमी के साथ 22 विकेट लेने में कामयाबी हासिल की।

सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का अवार्ड: राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर- इंग्लिश बल्लेबाज ने इस सीजन में अपनी टीम के 137 छक्कों में से 45 छक्के लगाए।

सीजन सबसे ज्यादा चौके लगाने का रिकॉर्ड: राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर- इस सीजन में 84 चौकों के साथ बटलर ने सर्वाधिक चौके लगाए।

पॉवरप्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड: राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर- राजस्थान के बल्लेबाज ने लगभग हर टीम के गेंदबाजों की खबर ली। उन्होंने ऐसे ही चार शतक नहीं लगाए।

गेम चेंजर ऑफ द सीजन अवार्ड: राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर- ओपनर ने पूरे सीजन में ड्रीम 11 में 1518 अंक बटोरे।

सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन अवार्ड: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के दिनेश कार्तिक- सीजन के दौरान 183.33 की स्ट्राइक रेट के साथ, कार्तिक ने आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

सीजन की सबसे तेज डिलीवरी: गुजरात टाइटंस के लॉकी फर्ग्यूसन- कीवी गेंदबाज ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सीजन के अंतिम मैच में 157.3 किमी प्रति घंटे की गति से गेंद फेंकी।

कैच ऑफ द सीजन अवार्ड: लखनऊ सुपर जायंट्स के एविन लुईस- केकेआर के खिलाफ दौड़ते हुए वेस्टइंडीज के खिलाड़ी ने एक हाथ से शानदार कैच लपका।

फेयरप्ले अवार्ड: गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स- लीग तालिका में शीर्ष पर रहने वाली और फाइनल में पहुंचने वाली दोनों टीमों ने खेल भावना को बनाए रखने वाले फेयर प्ले इंडेक्स में संभावित 10 में से 10 अंकों के हासिल किए।

● आशीष नेमा

जंजीर के लिए प्रकाश मेहरा की पहली पसंद नहीं थे अमिताभ

धर्मेंद्र से 3500 रुपए में खरीदी थी कहानी

1973 में आई जंजीर ने बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन का टैग दिलाया था। लेकिन इस फिल्म के लिए मेकर्स की पहली पसंद अमिताभ बच्चन नहीं बल्कि बॉलीवुड के ही-मैन यानी धर्मेंद्र थे। एक इंटरव्यू में फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा के बेटे पुनीत ने इस बात का खुलासा किया है।

धर्मेंद्र के पास डेट्स नहीं थीं

इंटरव्यू में पुनीत ने बताया कि जंजीर की स्क्रिप्ट धर्मेंद्र को बहुत पसंद आई थी। वही इसे पापा के पास लेकर आए थे। धर्मेंद्र के साथ पापा की फिल्म समाधि ने थिएटर्स में काफी अच्छा परफॉर्म किया था। इसके बाद वह चाहते थे कि जंजीर जैसी बढ़िया स्क्रिप्ट में धर्मेंद्र ही लीड एक्टर हों। हालांकि ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि उस समय धर्मेंद्र के पास पूरे साल डेट्स ही नहीं थीं। पापा को भी ये स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई इसीलिए उन्होंने इसकी कहानी को धर्मेंद्र से 3500 रुपए देकर खरीद ली थी। प्रकाश मेहरा को अमिताभ बच्चन के गॉडफादर के सवाल पर पुनीत ने कहा, मेरे पापा कहा करते थे कि वह अमित जी के गॉडफादर नहीं हैं। हालांकि ऐसा कई बार हुआ है कि लोग आकर उनसे ऐसी बातें कहा करते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा इस बात से इनकार किया। उनका कहना था कि एक टैलेंट को दूसरा टैलेंट मिला और जादू हो गया।

पृथ्वीराज कपूर ने पूरी जमा पूंजी लगाकर बनाया था पृथ्वी थिएटर, मुगल-ए-आजम के लिए मिला था ब्लैंक चैक लेकिन फीस ली 1 रुपए

भारतीय सिनेमा की शुरुआत में सबसे अहम हिस्सा और चेहरा रहे पृथ्वीराज कपूर ने ही कपूर खानदान को इंडस्ट्री में जगह दिलाई। महज 8 साल की उम्र में अभिनय शुरू करने वाले पृथ्वीराज ने साइलेंट फिल्मों में काम किया। जब पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी तो ये बोलती फिल्मों के पहले खलनायक बने। 47 सालों के फिल्मी कैरियर में पृथ्वीराज ने कई कल्ट क्लासिक फिल्में दीं, जिनके लिए इन्हें दादा साहेब फाल्के और पद्मभूषण से भी सम्मानित किया गया। पृथ्वीराज भले ही भारतीय सिनेमा का एक अहम हिस्सा रहे हैं, लेकिन शुरुआत में इन्हें इसी इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए सालों तक संघर्ष करना पड़ा था। 1944 में पृथ्वीराज कपूर ने पहला कमर्शियल थिएटर पृथ्वी शुरू किया। पृथ्वी थिएटर में उन्होंने पूरी जमा पूंजी लगा दी। थिएटर में शो दिखाने के बाद पृथ्वी खुद झोली लेकर दरवाजे पर खड़े होते थे। थिएटर से निकलते हुए लोग जो चंद रुपए उनकी झोली में डालते थे वो उन जमा पैसों को वर्कर फंड बनाने में इस्तेमाल करते थे। थिएटर में काम करने वाले लोगों को वो इस फंड से मदद दिया करते थे।

एक अपमान की वजह से अभिनेता से राजनेता बन गए एनटीआर, सत्रह फिल्मों में कृष्ण के रोल में नजर आए

300 से ज्यादा फिल्मों में नजर आने वाले तेलुगु सुपरस्टार एनटीआर यानी नंदमुरी तारक रामा राव एक जाने-माने एक्टर, फिल्म निर्माता और राज नेता भी थे। एनटीआर ने 1982 में तेलगु देशम पार्टी की स्थापना की और पॉलिटिक्स में एंट्री ली। एनटीआर इतने पॉपुलर थे कि लोग इन्हें देवता ही मानते थे। इसका फायदा इनको राजनीतिक कैरियर में भी मिला। रामाराव फेमस एक्टर जूनियर एनटीआर के दादाजी हैं। एनटीआर इनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी इसलिए पढ़ाई के दौरान रामा राव परिवार की मदद करने के लिए विजयवाड़ा के स्थानीय होटलों में दूध बेचने का काम भी करते थे। 1942 में इन्होंने अपने मामा की बेटी के साथ शादी की। एनटीआर ने दो शादी की थी। कुल मिलाकर इनकी 12 संतानें थीं। इसमें आठ बेटे और चार बेटियां थीं। साल 1993 में 70 साल की उम्र में रामा राव ने तेलुगु लेखक लक्ष्मी पार्वती से दूसरी शादी की लेकिन इनके के परिवार ने लक्ष्मी को कभी स्वीकार नहीं किया। एक अपमान की वजह से इन्होंने एक्टिंग छोड़ राजनीति का दामन थाम लिया। एनटीआर ने तकरीबन 17 फिल्मों में कृष्ण का किरदार निभाया था।

तेल लगाने की कला

तेल लगाना एक ललित कला है। यदि आलोचकों ने इसे ललित कला में शामिल नहीं किया है तो भी यह ललित कला है। इस आभासी तेल में बहुत फिसलन होती है। इस तेल में बड़े-बड़े लोग खड़े-खड़े फिसलते देखे गए हैं। ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के तेल में पूरियां तलनेवाले अधिकारी भी इस चिकनाई में चारों खाने चित्त हो जाते हैं। यह दैवीय गुणों से युक्त सर्वहितकारी, सर्वबाधाहारी और अचूक तेल है। कलियुग में इससे अमोघ असरकारी दूसरा कोई तेल नहीं है। यह तेल दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के दुखों का शमन करने वाला है। जिसने भी इस तरल पदार्थ का मनोयोगपूर्वक भक्ति भाव से इस्तेमाल किया उसकी जीवन नैया पार लग गई। तैलीय विधा में पारंगत होना कोई सरल कार्य नहीं है, इसके लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। कठोर तप, अहर्निश सेवा और निरंतर अभ्यास के बाद ही कोई व्यक्ति मुकम्मल तेल कलाकार बनता है। एकनिष्ठ साधना, कठोर तप और चापलूस मंत्र का जाप करने के बाद ही इस कला में प्रवीणता प्राप्त की जा सकती है। तेल कलाकारों को लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, गधों को बाप कहना पड़ता है, मूर्खों को बृहस्पति घोषित करना पड़ता है और कमीना पुरुष को महापुरुष बोलना पड़ता है। तेल लगाना कोई आसान काम नहीं है। यह तलवार की धार पर चलने के समान है, जरा संतुलन बिगड़ा और काम तमाम-चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। इस कला में कम लोग ही सफलता की सीढी चढ़ पाते हैं। यह खाला का घर नहीं है कि मुंह उठाकर चले आए और तेल लगाने लगे।

आजाद होने के बाद तैलीय पंडितों की बहुत बड़ी संख्या सरकारी दफ्तरों में विराजमान हो गई और अपनी तैलीय विद्या के बल पर सत्ता का शीर्षासन करने लगी। देशज लोग इसे चमचागिरी कहें अथवा चापलूसी-कोई फर्क नहीं पड़ता। इस महान कला परंपरा को चरणदासी संप्रदाय कहें या तैलीय संप्रदाय-कुछ भी नाम दें, लेकिन यह विधा है बहुत कमाल की। इस विधा ने भारतीय लोकतंत्र की लाज रख ली है वरना सरकारी दफ्तरों में काम करना-कराना कितना मुश्किल हो जाता। जिसने मालिश पुराण का पूर्ण निष्ठा और समर्पण भाव से पाठ किया उसकी आठों उंगलियां घी में होती हैं। तैलीय विधा में जिसने दक्षता प्राप्त कर ली उसका दुख-दारिद्र्य दूर हो जाता है, उसके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, सफलता के सभी दरवाजे खुल जाते हैं और वह परम धाम को प्राप्त करता है। चापलूसी मंत्र में अमोघ शक्ति होती है, यह निष्फल नहीं जाता। इस मंत्र का जाप कर अनेक लोग सीईओ, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक बन गए। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एक ही जीवन मिला है, उसे संवार लो। ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा? अगर अपनी मेधा और योग्यता से न संवरती हो तो चापलूसी का तेल और झूठ का क्रीम लगाओ। दुनिया तो सफलता देखती है, उसके पीछे किस ब्रांड का तेल, किस ब्रांड का क्रीम लगा है, यह कोई नहीं देखता। युद्ध और प्रेम में ही नहीं, जिंदगी में भी सबकुछ जायज है। इतिहास में सफल लोगों की कहानी लिखी जाती है। साधन पवित्र हो या अपवित्र, मूल उद्देश्य सफलता प्राप्त करना है। यह चापलूसी से मिले या मुद्रा देवी की कृपा से। कलयुग केवल तेल आधारा। कलयुग में आगे बढ़ने का सस्ता, सुंदर और टिकाऊ तरीका चापलूसी मंत्र का अहर्निश जाप है। यदि आपने इस एक मंत्र को सिद्ध कर लिया तो किसी और मंत्र की आवश्यकता नहीं। इस एक मंत्र के सामने अन्य सभी मंत्र दो कौड़ी के हैं। कलिकाल का यह एकमात्र मंत्र आपके भाग्य का सिंहद्वार खोल सकता है-एकहि साधे सब सधे। यदि कोई चापलूसी कला में पारंगत नहीं है और निर्विघ्न सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना चाहता है तो शास्त्रों में उसका भी विधान-समाधान वर्णित है। तैलीय गुण से रहित पुरुष पुंगव यदि नियमित रूप से मुद्रा देवी की उपासना-आराधना करें एवं प्रतिदिन मुद्रा चालीसा का पाठ करते हुए यथाशक्ति समयानुसार उचित पात्र को रिश्वत रूप में मुद्रा दान करें तो वे इहलोक व परलोक में सफलता के गुड़ व रसीले मीठे फल खा सकते हैं। कुछ लोग इसे स्वार्थवाद कह सकते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी तो पहले ही कह चुके हैं-सुर नर मुनि की यही सब रीति, स्वारथ लागी करहि सब प्रीति।

जिस प्रकार सच्चे भक्त भगवान को प्रिय होते हैं उसी प्रकार सच्चे चमचे नेताओं और अधिकारियों को प्रिय होते हैं। तेल कलाकार की कुछ न्यूनतम पात्रता निर्धारित है जिसके बिना कोई भी व्यक्ति उम्दा कोटि का तेल कलाकार नहीं बन सकता। तेल कलाकार की पहली योग्यता होती है कि उसे अपने आराध्य देव के खान-पान, पसंद-नापसंद, योग्यता-अयोग्यता आदि के संबंध में पूरी जानकारी हो। चरणदासी पुरुष पुंगव की दूसरी योग्यता है कि अपने आराध्य बॉस को प्रसन्न करने के लिए उसे मनोविज्ञान और कपाल विद्या का भी थोड़ा ज्ञान हो। बॉस के सोचने से पहले ही उसे बॉस की भलाई-बुराई के बारे में सोचना पड़ेगा तभी वह सुयोग्य तेल कलाकार साबित होगा। यदि एक बार आपने अपने आराध्य बॉस को प्रसन्न कर लिया तो फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आजकल सरकारी दफ्तरों में तेल कलाकारों की मांग बहुत बढ़ गई है। भारत के सरकारी दफ्तरों में तैलीय विधा में दक्ष कर्मचारी सुखी और प्रसन्न रहते हैं। वे घर से ही अपनी उंगलियों में मक्खन लगाकर आते हैं और सुबह-सुबह अपने आराध्य देव (बॉस) को चटा देते हैं। इसके बाद क्या मजाल कि कोई छोटा अधिकारी उनसे काम करा ले। तेल लगाना एक प्राचीन कला है जिसका स्वर्णिम इतिहास और गौरवशाली अतीत रहा है। गरीबनवाज, जहांपनाह, रायबहादुर, सरदार बहादुर, खान बहादुर, सितारे हिंद आदि शब्द खुशामद विधा और स्वामी भक्ति की उदात्त परंपरा के साक्षी हैं। इतिहास गवाह है कि अनेक हिन्दुस्तानियों ने अपनी इस अनमोल कला के बल पर किस प्रकार मुगलों और अंग्रेजों को चमत्कृत कर कैसी-कैसी उपाधियां झटक ली थीं।

● **वीरेन्द्र परमार**

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

Toll free: 1800-3000-1444
Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

दूर की सोच®

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

17/1, Sector-1 Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) India-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687